

मुकदमों का विवरण

इन आरई:आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अंतर्गत आर्बिट्रेशन समझौतों के बीच हस्तक्षेप

(सुधारात्मक याचिका (सी) 2023 की संख्या 44)

में

(2021 की समीक्षा याचिका (सी) संख्या 704)

में

(2020 की सिविल अपील संख्या 1599) 13 दिसंबर, 2023

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई, संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई, सूर्या कांत, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे जे।]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:यह मुद्दा तीन कानूनों के संदर्भ में उठा; मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। डाक टिकट अधिनियम "उपकरणों" पर शुल्क लगाता है। मध्यस्थता समझौते अक्सर अंतर्निहित उपकरणों या मूल अनुबंधों में अंतर्निहित होते हैं। विचार के लिए प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या इस तरह के मध्यस्थता समझौते अस्तित्वहीन, अप्रवर्तनीय या अमान्य होंगे यदि अंतर्निहित अनुबंध पर मुहर नहीं लगाई गई है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रावधानों को सुसंगत बनाने की थी।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम **1996-ss.8** और **11**-अंतर्निहित उपकरणों या मूल अनुबंधों में निहित मध्यस्थता समझौते-क्या ऐसे मध्यस्थता समझौते अस्तित्वहीन, अप्रवर्तनीय, या अमान्य होंगे यदि अंतर्निहित अनुबंध पर मुहर नहीं लगाई गई है-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996** और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, **1899** के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच परस्पर क्रिया-बिना मुहर वाले या बिना ज्ञान के मुहर वाले उपकरण-यदि साक्ष्य में स्वीकार्य हो-गैर-मुद्रांकन या अपर्याप्त मुद्रांकन-यदि ठीक हो।

एड। नोट करें। सीजेआई, माननीय डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने अपनी ओर से, माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल, माननीय न्यायमूर्ति श्री बी आर गवई, माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत, माननीय न्यायमूर्ति श्री जे बी पारदीवाला और माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज मिश्रा की ओर से निर्णय सुनाया। माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एक अलग लेकिन सहमत निर्णय सुनाया।

1082 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

आयोजित (डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, संजय किशन कौल, बी. आर. गवई, सूर्यकांत, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा,

जेजे.): जिन समझौतों पर मुहर नहीं लगी है या जिन पर अपर्याप्त रूप से मुहर लगी है, वे साक्ष्य यू/एस में अस्वीकार्य हैं।³⁵ स्टाम्प अधिनियम-इस तरह के समझौतों को शून्य या अमान्य या अप्रवर्तनीय नहीं माना जाता है-गैर-स्टाम्पिंग या अपर्याप्त स्टाम्पिंग एक उपचार योग्य दोष है-स्टाम्प अधिनियम स्वयं उस तरीके का प्रावधान करता है जिसमें दोष को ठीक किया जा सकता है और इसके लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है-स्टाम्पिंग के रूप में एक आपत्ति यू/एस. एस. के निर्धारण के लिए नहीं आती है।⁸ या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11-संबंधित न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या मध्यस्थता समझौता प्रथम दृष्टया मौजूद है-समझौते पर मुहर लगाने के संबंध में कोई भी आपत्ति मध्यस्थता न्यायाधिकरण के दायरे में आती है।[पारस

48 और 224]-आयोजित (संजीव खन्ना, जे. के अनुसार) (सहमत): अनस्टैम्प्ड

या एस के संदर्भ में साक्ष्य में अस्वीकार्य रूप से मुहर लगाए गए उपकरण।³⁵ भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को प्रारंभ से ही शून्य और शून्य नहीं माना जाता है-अंतर्निहित अनुबंध की कम-मुद्रांकन या गैर-मुद्रांकन के बारे में आपत्ति का कोई असर नहीं होगा जब मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 या 11 के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेते समय अदालतों द्वारा प्रथम दृष्टया परीक्षण, "मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व" लागू किया जाता है-अंतर्निहित समझौते की असंवेदनशील मुद्रांकन के बारे में आपत्ति की जांच और निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकता है।[पैरा 1]

साक्ष्य-दस्तावेजों की स्वीकार्यता-अस्वीकृति और शून्यता के बीच अंतर-अनुबंध अधिनियम, **1872 -एस. 2 (जी)**।

आयोजित (डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, संजय किशन कौल, बी. आर. गवई, सूर्यकांत, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):

साक्ष्य में किसी दस्तावेज की स्वीकार्यता विधि में इसकी वैधता या प्रवर्तनीयता से अलग है-एक समझौता अपनी प्रकृति के बिना एक अमान्य समझौते के रूप में अमान्य हो सकता है जिसका प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि क्या इसे साक्ष्य में पेश किया जा सकता है-इसी तरह, एक समझौता वैध हो सकता है लेकिन साक्ष्य में अस्वीकार्य हो सकता है-जब कोई समझौता अमान्य होता है, तो कोई विधि की न्यायालय में इसकी प्रवर्तनीयता की बात कर रहा होता है-जब यह अस्वीकार्य होता है, तो कोई इस बात का उल्लेख कर रहा होता है कि क्या न्यायालय मामले का निर्णय लेते समय उस पर विचार कर सकती है या उस पर भरोसा कर सकती है-यह शून्यता और स्वीकार्यता के बीच के अंतर का सार है।[पैरा 44,45 और 46]

भारतीय डाक टिकट अधिनियम, **1899**-का उद्देश्य।

आयोजित (डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, संजय किशन कौल, बी. आर. गवई, सूर्यकांत, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):

1083

इन आरई:आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899-1084 सुप्रीम न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर. के अंतर्गत आर्बिट्रेशन समझौतों के बीच हस्तक्षेप।

स्टाम्प एक्ट एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व बढ़ाना है-यह एक अनिवार्य कानून है।[पैरा 58]

मध्यस्थता-मध्यस्थता स्वायत्तता का सिद्धांत-सिद्धांत/सिद्धांत।

आयोजित (डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, संजय किशन कौल, बी. आर. गवई, सूर्यकांत, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):

मध्यस्थता स्वायत्तता का सिद्धांत मध्यस्थता विधि के निरंतर विकसित होते क्षेत्र का एक अभिन्न तत्व है-मध्यस्थता स्वायत्तता का अर्थ है कि मध्यस्थता समझौते के पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपने बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को तय करने का अधिकार देने के लिए अपनी संविदात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं-मध्यस्थता स्वायत्तता का आधार पक्षों के सच्चे इरादे को प्रभावी बनाना है ताकि वे "घरेलू न्यायिक संकीर्णता के जोखिम" से खुद को दूर कर सकें।[पैरा 66]

सिद्धांत/सिद्धांत-मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप का सिद्धांत-धाराओं में निहित गैर-अस्थाई खंड का दायरा।**5** मध्यस्थता और सुलह अधिनियम **1996**-विधायी इरादा। आयोजित (डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, संजय किशन कौल, बी. आर. गवई, सूर्यकांत, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):

मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायिक गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करने का कार्य करता है, जो अपने विवादों को मध्यस्थता करने के लिए सहमत होने में पक्षों के उद्देश्य को कमजोर करेगा, कम औपचारिक और अधिक व्यावहारिक प्रक्रियाओं के लिए उनकी इच्छा, और तटस्थ और विशेषज्ञ मध्यस्थता प्रक्रियाओं के लिए उनकी इच्छा-मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायिक गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत मध्यस्थता प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए पक्षों की स्वायत्तता का सम्मान करता है-इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों में भी शामिल किया गया है -मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 एस. एस. के अंतर्गत न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा की व्याख्या करने में सहायक है।**8** और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 -एस. 5 में न्यायिक गैर-हस्तक्षेप का एक सामान्य नियम है-इसलिए, मध्यस्थता अधिनियम के प्रत्येक प्रावधान का अर्थ एस. को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए।**5** न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप के विधायी इरादे को सही प्रभाव देना। [पारस 69 और 82]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996**-एक स्व-निहित संहिता है-अन्य कानूनों के प्रावधान मध्यस्थता के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

मध्यस्थता अधिनियम, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।[डा. के निर्णय में पैरा 85।

डी. वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई]

मध्यस्थता-मध्यस्थता समझौता-मध्यस्थता की नींव है क्योंकि यह पक्षकारों की सहमति अभिलेख करता है

मध्यस्थता के लिए विवाद।[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई के निर्णय में पैरा 88]

मध्यस्थता-मध्यस्थता समझौता-मध्यस्थता समझौते को उस अंतर्निहित अनुबंध से अलग करना जिसमें यह निहित है।

आयोजित (डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, संजय किशन कौल, बी. आर. गवई, सूर्यकांत, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):

एक मध्यस्थता समझौता अंतर्निहित अनुबंध से न्यायिक रूप से स्वतंत्र है जिसमें यह निहित है-पृथक्करण की अवधारणा अंतर्निहित अनुबंध को अलग करने के लिए पक्षों के अनुमानित इरादे को दर्शाती है, जो पक्षों के मूल अधिकारों और दायित्वों को पकड़ती है, एक मध्यस्थता समझौते से जो अंतर्निहित अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए एक प्रक्रियात्मक ढांचा प्रदान करता है-इस धारणा के सिद्धांत और व्यवहार में विभिन्न परिणाम हैं, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक मध्यस्थता समझौता अंतर्निहित अनुबंध की अयोग्यता या समाप्ति से बच जाता है-पृथक्करण की धारणा क्षमता-क्षमता के सिद्धांत को प्रभावी बनाती है।[पैरा 90 और 112]

सिद्धांत/सिद्धांत-योग्यता-क्षमता का सिद्धांत-तुलनात्मक विश्लेषण-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम **1996** -एस. **16**.आयोजित (डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, संजय किशन कौल, बी. आर. गवई, सूर्यकांत, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा,

जेजे.):कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ (जिसे योग्यता क्षमता के रूप में भी जाना जाता है) का सिद्धांत, जैसा कि मूल रूप से जर्मनी में विकसित किया गया था, पारंपरिक रूप से यह संकेत देने के लिए समझा जाता था कि मध्यस्थों को अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर एक अंतिम निर्णय देने का अधिकार है, जिसमें किसी भी न्यायालय द्वारा निर्णय की कोई बाद में न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती है-हालाँकि, कई अधिकार क्षेत्र एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय देने की अनुमति देते हैं, जो ठोस न्यायिक समीक्षा के अधीन है-यूके

की स्थिति यह है कि हालांकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को यह विचार करने का अधिकार है कि क्या उसका अधिकार क्षेत्र है, इसका निर्धारण 1085 के अधीन है।

इन आरई:आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899-1086 सुप्रीम न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर. के अंतर्गत आर्बिट्रेशन समझौतों के बीच हस्तक्षेप।

न्यायालय ों की जाँच-संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय ों ने योग्यता-योग्यता के सिद्धांत को पृथक्करण की धारणा के साथ जोड़ा हुआ माना है-सिंगापुर उच्च न्यायालय ने क्षमता-क्षमता के सिद्धांत को पूरा प्रभाव दिया है क्योंकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के संबंध में भी मुद्दों को निर्धारित करने के लिए पहली प्राथमिकता मिलती है, जबकि न्यायालय ों का अधिकार क्षेत्र प्रथम दृष्टया निर्धारण तक सीमित है - मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 भारतीय मध्यस्थता विधि में योग्यता-क्षमता के सिद्धांत को मान्यता देती है।[पारस 115,117,118,119,120]

सिद्धांत/सिद्धांत-योग्यता-क्षमता का सिद्धांत-सिद्धांत के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू-नकारात्मक क्षमता-क्षमता-पर चर्चा की गई।

आयोजित (डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, संजय किशन कौल, बी. आर. गवई, सूर्यकांत, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):द.

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता विधि के साथ-साथ घरेलू विधि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अदालतों के बजाय अपने अधिकार की चुनौतियों पर शुरू में निर्णय लेने की अनुमति देकर प्राथमिकता देते हैं-इस दृष्टिकोण के पीछे नीतिगत विचार दो गुना है:पहला, अनुबंध से उत्पन्न होने वाले मूल अधिकारों और दायित्वों के बारे में अपने सभी विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ का चयन करने के पक्षों के आपसी इरादे को पहचानना; और दूसरा, अदालतों के समक्ष समानांतर कार्यवाही शुरू करने और मध्यस्थता प्रक्रिया में देरी करने से पक्षों को रोकना-यह क्षमता-क्षमता के सिद्धांत का सकारात्मक पहलू है-इसके विपरीत, नकारात्मक पहलू राष्ट्रीय अदालतों से बात करता है-यह अदालतों को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता से संबंधित मुद्दों में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को स्थगित करके रेफरल चरण में अपने हस्तक्षेप को सीमित करने का निर्देश देता है-मध्यस्थता न्यायाधिकरणों को अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र में पहले नियम को लागू करने की अनुमति देना और बाद में अदालतों को यह निर्धारित करने की अनुमति देना कि क्या न्यायाधिकरण ने अपनी शक्तियों का उपयोग सही तरीके से किया है।[पारस 129,130]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996**-मध्यस्थता अधिनियम भारत में मध्यस्थता से संबंधित विधि को समेकित करने के लिए अधिनियमित एक विधि है-मध्यस्थता समझौतों के संबंध में स्टाम्प अधिनियम और अनुबंध अधिनियम पर इसकी प्रधानता होगी।[डा. के निर्णय में पैरा **166**।

डी. वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई]

क्रानूनों की व्याख्या-सामंजस्यपूर्ण निर्माण-दो क्रानूनों में निहित प्रावधानों की व्याख्या, यदि संभव हो, तो दोनों क्रानूनों को पूर्ण प्रभाव देने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए-एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या प्रदान करने में, न्यायालय को इस तथ्य का संज्ञान लेना होगा कि यह क्रानूनों के उद्देश्य को विफल नहीं करता है या उन्हें प्रस्तुत नहीं करता है।

निष्क्रिय सक्रिय।[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई के निर्णय में पैरा 165]

क्रानूनों की व्याख्या-गैर-अस्थायी खंड-आयोजित:यद्यपि एक गैर-अस्थायी खंड को पूरे जोश के साथ संचालित करने की अनुज्ञात जानी चाहिए, लेकिन इसका प्रभाव विधायिका द्वारा इच्छित सीमा तक सीमित है।[पैरा 77 में

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई का निर्णय]

शब्द और वाक्यांश-"स्वीकार्य"।[डॉ. के निर्णय में पैरा 44।

डी. वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई]

शब्द और वाक्यांश-शब्द "होगा"-एसएस में।**33** और स्टाम्प अधिनियम की **35**-का अर्थ और प्रभाव।[डॉ. डी. वाई. के निर्णय में पैरा **189**।

चंद्रचूड़, सीजेआई]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के निर्णय में, सीजेआई

एन एन ग्लोबल मर्केटाइल (पी) लिमिटेड बनाम इंडो यूनिफ फ्लेम लिमिटेड (2023) 7 एस. सी. सी. 1 और एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (पी) लिमिटेड बनाम।चांदमारी टी कं. (पी) लिमिटेड (2011)

14 एससीसी 66:[2011] 9 एस. सी. आर. 382-खारिज।

गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम तटीय समुद्री निर्माण और इंजीनियरिंग।

लिमिटेड (2019) 9 एससीसी 209:[2019] 5 एस. सी. आर. 579-कुछ हद तक खारिज कर दिया गया।

उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड बनाम उत्तरी कोयला क्षेत्र (2020) 2 एस. सी. सी. 455-पर निर्भर।

विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा व्यापार निगम (2021) 2 एस. सी. सी. 1:[2020]

11 एससीआर 1001-स्पष्टीकरण संस्करण।

1087

इन आरई:आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 1088 सुप्रीम न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर. के अंतर्गत आर्बिट्रेशन समझौतों के बीच हस्तक्षेप।

एन एन ग्लोबल मर्केटाइल (पी) लिमिटेड बनाम इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड (2021) 4 एस. सी. सी. 379; धर्मरत्नाकर राय बहादुर आर्कोट नारायणस्वामी मुदलियार छत्रम बनाम भास्कर राजू और ब्रदर्स (2020) 4 एस. सी. सी. 612:[2020] 3 एस. सी. आर. 798; रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002) 4 एस. सी. सी. 388:[2002] 2 एस. सी. आर. 1006; भारत पेट्रोलियम निगम बनाम मुंबई श्रमिक संघ

(2001) 4 एससीसी 448:[2001] 3 एससीआर 208; प्रदीप चंद्र परिजा बनाम प्रमोद चंद्र पटनायक (2002) 1 एससीसी 1:[2001] 5 पूरक।एस. सी. आर. 460; भारत संघ बनाम हंसोली देवी, (2002) 7 एस. सी. सी. 273:[2002] 2 पूरक।एस. सी. आर. 324; केंद्रीय

दाउदी बोहरा समुदाय बोर्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 2

एससीसी 673:[2004] 6 पूरक।एससीआर 1054; शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन

2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 544; कांतारू राजीवरु बनाम इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन (2020) 9 एस. सी. सी. 121; गंगा शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम।की स्थिति

उत्तर प्रदेश (1980) 1 एस. सी. सी. 223:[1980] 1 एससी 769; तिरुवेंगडम पिल्लई बनाम नवनीथमल, (2008) 4 एससीसी 530:[2008] 3 एस. सी. आर. 23; हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम दिलीप कंस्ट्रक्शन कंपनी (1969) 1 एस. सी. सी. 597:[1969] 3 एससीआर 736; संघ

भारत बनाम लोकप्रिय निर्माण कंपनी, (2001) 8 एस. सी. सी. 470:[2001] 3 पूरक।एससीआर 619; पी आनंद गजपति राजू बनाम पी. वी. जी. राजू, (2000) 4 एससीसी 539:[2000] 2 एस. सी. आर. 684; भारतीय खाद्य निगम बनाम भारतीय मध्यस्थता परिषद,

(2003) 6 एससीसी 564:[2003] 1 पूरक।एस. सी. आर. 568; भारत संघ बनाम लोकप्रिय

कंस्ट्रक्शन कं., (2001) 8 एस. सी. सी. 470; स्विस् टाइमिंग लिमिटेड बनाम।राष्ट्रमंडल खेल 2010 आयोजन समिति, (2014) 6 एससीसी 677:[2014] 6 एस. सी. आर. 514; बिहार राज्य बनाम बिहार राज्य M.S.E.S.K.K. महासंघ (2005) 9 SCC 129: [2004] 5 पूरक।एस. सी. आर. 376; पोत एम. वी. में रुचि रखने वाले मालिक और पक्षकार। पोलारिस गैलेक्सी बनाम बैंक कैंटोनल डी जिनेवा, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1293; चंदावरकर सीता रत्न राव बनाम आशालता एस. गुरम (1986) 4 एससीसी

447:[1986] 3 एस. सी. आर. 866; आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड बनाम सिडको लेदर लिमिटेड, (2006)

10 एससीसी 452:[2006] 1 पूरक।एस. सी. आर. 528; जे. आई. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम अमरलाल वी. जुमानी, (2012) 3 एससीसी 255:[2012] 3 एससीआर 114; मॉर्गन सिक्वोरिटीज एंड क्रेडिट (पी) लिमिटेड बनाम मोदी रबर लिमिटेड (2006) 12 एस. सी. सी. 642:[2006] 10 पूरक।एससीआर

1022; सिक्वोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गोदरेज एंड बॉयस एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड (2004) 3 एस. सी. सी. 447:[2004] 2 एस. सी. आर. 705; भावेन निर्माण बनाम सरदार सरोवर नर्मदा

निगम लिमिटेड (2022) 1 एस. सी. सी. 75:[2021] 1 एससीआर 1; गिरनार ट्रेडर्स बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 3 एससीसी 1:[2011] 3 एस. सी. आर. 1; फुएस्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2011) 8 एस. सी. सी. 333:[2011] 11 एस. सी. आर. 1; पासल विंड सॉल्यूशंस

(पी) लिमिटेड बनाम जी. ई. पावर कन्वर्जन (इंडिया) (पी) लिमिटेड, (2021) 7 एस. सी. सी. 1; कांडला निर्यात निगम बनाम ओ. सी. आई. निगम, (2018) 14 एस. सी. सी. 715:[2018] 1

एस. सी. आर. 915; सुबल पॉल बनाम मालिना पॉल, (2003) 10 एस. सी. सी. 361:[2003] 1 एससीआर

1092; बिहार राज्य खनिज विकास निगम बनाम एनकॉन बिल्डर्स

(2003) 7 एससीसी 418:[2003] 2 पूरक।एस. सी. आर. 812; भारत संघ बनाम किशोरीलाल गुप्ता, 1959 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 6; दामोदर घाटी निगम बनाम के. के. कर (1974) 1 एससीसी 141:[1974] 2 एससीआर 240; फर्म अशोक ट्रेडर्स बनाम गुरुमुख दास सलूजा (2004) 3 एससीसी 155:[2004] 1 एस. सी. आर. 404; राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति।

मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड बनाम (2007) 5 एस. सी. सी. 692; पी. मनोहर रेड्डी एंड ब्रदर्स।बनाम महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम।

(2009) 2 एससीसी 494:[2008] 17 एस. सी. आर. 1217; मैग्मा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड बनाम पोटलुरी माधविलता (2009) 10 एस. सी. सी. 103:[2009] 14 एससीआर 815; आर्सेलर

मित्तल निप्पॉन स्टील (इंडिया) लिमिटेड बनाम एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड (2022) 1 एससीसी

712; ए. अय्यासामी बनाम ए. परमशिवम, (2016) 10 एससीसी 386:[2016] 11 एससीआर 521;

एस. पी. बी. एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (2005) 8 एससीसी 618: [2005] 4 पूरका एस. सी. आर. 688; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बोधारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड (2009) 1 एससीसी 267:[2008] 13 एस. सी. आर. 638; डुरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम गंगावरम बंदरगाह

लिमिटेड (2017) 9 एससीसी 729:[2017] 10 एस. सी. आर. 285; मायावती ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड बनाम प्रद्युत देब बर्मन (2019) 8 एस. सी. सी. 714:[2019] 12 एससीआर 123; शिन-एत्सु

केमिकल कं. लिमिटेड बनाम अक्ष ऑप्टिफ़ी ब्री लिमिटेड (2005) 7 एस. सी. सी. 234: [2005] 2 पूरक।

एस. सी. आर. 699; सी. आई. टी. बनाम हिंदुस्तान बल्क कैरियर, (2003) 3 एस. सी. सी. 57:[2002] 5 पूरक।

एस. सी. आर. 387; सुल्ताना बेगम बनाम प्रेम चंद जैन (1997) 1 एस. सी. सी. 373: [1996] 9 पूरक। एससीआर 707; कांडला निर्यात निगम बनाम ओसीआई निगम (2018) 14 एससीसी 715:[2018] 1 एस. सी. आर. 915; शिल्पी इंडस्ट्रीज बनाम केरल राज्य सड़क परिवहन

निगम 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 439; एल. आई. सी बनाम डी. जे. बहादुर (1981) 1 एस. सी. सी.

315:[1981] 1 एस. सी. आर. 1083; सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम टी. थंकम (2015) 14 एससीसी 444:[2015] 2 एस. सी. आर. 228; सी. डी. सी. वित्तीय सेवा (मॉरीशस) लिमिटेड बनाम बी. पी. एल. कम्युनिकेशंस लिमिटेड, (2003) 12 एस. सी. सी. 140; एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड बनाम जूट

कॉर्प.ऑफ इंडिया लिमिटेड, (2007) 14 एस. सी. सी. 680:[2007] 11 एससीआर 388; एसोसिएट बिल्डर्स बनाम डीडीए, (2015) 3 एससीसी 49:[2014] 13 एस. सी. आर. 895; भावेन निर्माण

बनाम सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, (2022) 1 एस. सी. सी. 75:[2021] 1 एससीआर

1 ; हमीद जोहान बनाम अब्दुल सलाम (2001) 7 एस. सी. सी. 573:[2001] 1 पूरक।

एससीआर 469; ए. अय्यासामी बनाम ए. परमशिवम (2016) 10 एससीसी 386:
 [2016] 11 एससीआर 52; यू. पी. राज्य बनाम बाबू राम उपाध्याय 1960 एस. सी. सी.
 ऑनलाइन एस. सी. 5; एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम आफताब सिंह (2019)
 12 एससीसी 751; इंटरकांटेनेंटल होटल्स ग्रुप (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम वाटरलाइन
 होटल्स (पी) लिमिटेड (2022) 7 एससीसी 662; जुपुडी केशव राव बनाम पुलवर्थी वेंकट
 सुब्बाराव (1971) 1 एससीसी 545; हरिओम अग्रवाल बनाम प्रकाश चंद मालवीय
 (2007) 8 एससीसी 514; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हुंडई इंगलैंड
 कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड (2018) 17 एस. सी. सी. 607; करियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल
 सोसाइटी बनाम ओम श्री ठाकुरजी 1089

इन आरई:आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 1090 के अंतर्गत मध्यस्थता
 समझौतों के बीच हस्तक्षेप

एजुकेशनल सोसाइटी 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 586; भारतीय किसान उर्वरक
 सहकारी लिमिटेड बनाम भद्रा उत्पाद (2018) 2 एस. सी. सी. 534:[2018] 1 एस. सी.
 आर. 848; आधिकारिक न्यासी, पश्चिम बंगाल बनाम सचिंद्र नाथ चटर्जी [1969] 3 एस.
 सी. आर. 92; एन. टी. पी. सी. बनाम सीमेंस एटकिंजेसलचाफ्ट (2007) 4 एस. सी. सी.
 451:[2007] 3 एस. सी. आर. 399; क्लोरो कंट्रोल्ल्स इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम सेवर्न
 ट्रेट वाटर प्यूरीफाई कैटायन

इंक. (2013) 1 एससीसी 641:[2012] 3 एस. सी. आर. 402 और सेका डोब्रिक बनाम एस.
 ए. इओनसोफ्टेक

प्राइवेट लिमिटेड (मध्यस्थता याचिका में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय)

2023 का सं. 25)-निर्दिष्ट।

सुख लाल शेख बनाम तारा चंद ता, 1905 एस. सी. सी. ऑनलाइन काल 164; गुलजारी
 लाल मारवाड़ी बनाम राम गोपाल 1936 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 275; बूटतम पिचिया
 बनाम.

बोयापति कोटेश्वर राव 1964 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. 5; मुल्हेम पाइपकोटिंग्स
 जी. एम. बी. एच. बनाम वेलस्पन फिट्रेड लिमिटेड, 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1048-
 संदर्भित।

रियो अलगाम बनाम सम्मी स्टील कंपनी, ओंटारियो न्यायालय ऑफ जस्टिस, कनाडा, 1
 मार्च 1991 [1991] ओ. जे. नहीं। 268; हेमन बनाम डार्विन्स [1942] एसी 356;
 हार्बर एश्योरेंस कंपनी (यू. के.) लिमिटेड बनाम कंस जनरल इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी
 लिमिटेड [1993] क्यू. बी. 701; प्रीमियम नाफ्टा प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम फिली शिपिंग

कंपनी लिमिटेड [2007] यूकेएचएल 40; प्राइमा पेंट कॉर्पोरेशन बनाम फ्लड एंड कॉन्क्लिन एमएफजी। कं., 388 यू. एस. 395 (1967); बकये चेक कैशिंग इंक बनाम कार्डेग्रा 546 यू. एस. 440,440 (2006); रेंट-ए-सेंटर, वेस्ट, इंक. बनाम। जैक्सन 2 561 यू. एस. 63 (2010); डल्लाह रियल एस्टेट एंड टूरिज्म होलिंग कंपनी बनाम धार्मिक मामलों के मंत्रालय, पाकिस्तान सरकार [2010] यूकेएससी 46; मालिनी वेंचुरा बनाम नाइट कैपिटल पीटीई लिमिटेड [2015] एसजीएचसी 225; टोबलर बनाम.

जस्टिजकमिशन डेस कैन्टन्स श्विज़, डी. एफ. टी. 59। 177 (1933)-संदर्भित। गैरी बोर्न, द प्रिंसिपल ऑफ ज्युडिशियल नॉन-इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स '(2009) 30 यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया जर्नल ऑफ इंटरनेशनल विधि 999,1002; गैरी बोर्न, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन विधि एंड प्रैक्टिस (3 वां संस्करण, 2021) 2361; डाइजेस्ट ऑफ केस विधि ऑन द मॉडल विधि ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन (2012) 21,60; रिचर्ड गार्नेट, 'मॉडल विधि का अनुच्छेद 5: मध्यस्थ प्रक्रिया का संरक्षक?' (2021) 38(2) जर्नल ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन 127-146; रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (7 वीं संस्करण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2023) 3; स्टीफन श्वबेल, ल्यूक सोबोटा और रयान मेंटन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन: तीन प्रमुख समस्याएं (कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस, दूसरा संस्करण, 2020) 4; हेनरी हॉर्विट्ज़ और जेम्स ओल्डहैम, 'जॉन लॉक, जॉन मैन्सफी एल्ड, और अठारहवीं शताब्दी के दौरान मध्यस्थता' (1993) 36 (1) ऐतिहासिक पत्रिका 137,139; अर्ल वोलावर, 'वाणिज्यिक मध्यस्थता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि'

/

[2023] 15 एस सी आर।

(1934) 83 यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया विधि रिव्यू 132,142; जूलियन डी. एम. ल्यू, 'अचीविंग द ड्रीम: ऑटोनॉमस आर्बिट्रेशन' (2006) 22 (2) आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल 17,93 और पी. रामनाथ अय्यर की द विधि लेक्सिकन-का उल्लेख किया गया है।

संजीव खन्ना के निर्णय में, जे.

एन एन ग्लोबल मार्केटाइल (पी) लिमिटेड बनाम इंडो यूनिफ फ्लेम लिमिटेड (2023) 7 एस. सी. सी. 1-निरस्त।

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (2021) 2 एससीसी

1:[2020] 11 एससीआर 1001-स्पष्टीकरण संस्करण।

जावेर चंद और अन्य। बनाम पुखराज सुराना ए. आई. आर 1961 एस. सी. 1655: [1962] 2 एस. सी. आर. 333; बिहार राज्य बनाम मेसर्स करम चंद थापर एंड ब्रदर्स लिमिटेड।

ए. आई. आर 1962 एस. सी. 110:[1962] 1 एस. सी. आर. 827; जुपुडी केशव राव बनाम पुलवर्णी वेंकट सुब्बाराव और अन्य (1971) 1 एस. सी. सी. 545:[1971] 3 एससीआर 590;

एल. आर. द्वारा हमीद जोहारन (मृत) और अन्य बनाम अब्दुल सलाम (मृत) और

अन्य (2001) 7 एस. सी. सी. 573:[2001] 1 पूरक।एससीआर 469; डॉ. चिरंजी लाल (डी) एल. आर. वी.एलआर द्वारा हरि दास (डी)। (2005) 10 एससीसी 746:[2005] 1 पूरक।

एस. सी. आर. 359; हरिओम अग्रवाल बनाम प्रकाश चंद मालवीय (2007) 8 एस. सी. सी. 514:[2007] 10 एससीआर 772; श्यामल कुमार राँय बनाम सुशील कुमार अग्रवाल (2006)

11 एससीसी 331:[2006] 8 पूरक।एस. सी. आर. 47; अविनाश कुमार चौहान बनाम विजय कृष्ण मिश्रा (2009) 2 एस. सी. सी. 532:[2008] 17 एस. सी. आर. 944; केशव मिल्स कं.

लिमिटेड वी.आयकर आयुक्त, बॉम्बे उत्तर, अहमदाबाद, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1636:[1965] 2 एससीआर 908; आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम ए. पी. जयसवाल और अन्य, (2001) 1 एस. सी. सी. 748; टोटल एनवायरनमेंट बिल्डिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बनामवाणिज्यिक कर और अन्य उपायुक्त, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 953; भारत संघ और एक अन्य बनाम रघुबीर सिंह (मृत) एल. आर. आदि द्वारा, (1989) 2 एस. सी. सी. 754:[1989] 3 एस. सी. आर. 316; कारवेल शिपिंग सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनामप्रीमियर सी फूड्स एक्विज़म (पी)

लिमिटेड (2019) 11 एससीसी 461:[2018] 14 एस. सी. आर. 289; गोविंद रबर लिमिटेड बनाम.लुई ड्रेफस कमोडिटीज एशिया प्रा. लि. (2015) 13 एससीसी 477:[2014] 12 एससीआर

488; बी. ओ. आई. फाइनेंस लिमिटेड बनामसंरक्षक और अन्य (1997) 10 एस. सी. सी. 488:[1997] 3 एस. सी. आर. 51; केनरा बैंक और अन्य बनाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (2002) 10 एस. सी. सी. 697; स्विस् टाइमिंग लिमिटेड बनाम।राष्ट्रमंडल खेल 2010 का आयोजन

समिति (2014) 6 एससीसी 677:[2014] 6 एस. सी. आर. 514; एवितेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड।

v. एचएसबीसी पी. आई. होलिंग्स (मॉरीशस) लिमिटेड (2021) 4 एससीसी 713: [2020] 10 एस. सी. आर. 791; करियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी बनाम ओम श्री ठाकुरजी एजुकेशनल सोसाइटी 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 586 और गरवारे बॉल रोप्स लिमिटेड बनामातटीय 1091

इन आरई:आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 1092 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

समुद्री निर्माण और इंजीनियरिंग लिमिटेड (2019) 9 एससीसी 209:[2019] 5 एस. सी. आर. 579-संदर्भित।

राम रतन बनाम परम नंद ए. आई. आर. 1946 पी. सी. 51-संदर्भित।

बी. एन. ए. बनाम बी. एन. बी. और एक अन्य [2019] एस. जी. एच. सी. 142 और इन्सिग्मा टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड बनाम अल्सटॉम टेक्नोलॉजी लिमिटेड [2009] एस. जी. सी. ए. 24-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

अंतर्निहित/नागरिक मूल न्यायनिर्णय:2020 की सिविल अपील संख्या 1599 में 2021 की समीक्षा याचिका (सी) No.704 में 2023 की सुधारात्मक याचिका (सी) संख्या 44।

निर्णय भनिर्णय ानिर्णय रनिर्णय तनिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय सनिर्णय रनिर्णय
 ्रनिर्णय वनिर्णय ोनिर्णय चनिर्णय ्रनिर्णय चनिर्णय न्यायालय निर्णय निर्णय कनिर्णय
 ेनिर्णय निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय 2 निर्णय 1 निर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय
 आनिर्णय रनिर्णय .निर्णय निर्णय पनिर्णय ीनिर्णय .निर्णय निर्णय (निर्णय सनिर्णय ीनिर्णय
)निर्णय निर्णय N निर्णय 0 निर्णय .निर्णय 7 निर्णय 0 निर्णय 4 निर्णय निर्णय मनिर्णय ेनिर्णय
 ंनिर्णय निर्णय दनिर्णय िनिर्णय ननिर्णय ानिर्णय ंनिर्णय कनिर्णय िनिर्णय तनिर्णय
 निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय .निर्णय 0 निर्णय 7 निर्णय .निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय 2 निर्णय 1 निर्णय
 निर्णय औनिर्णय रनिर्णय निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय
 निर्णय सनिर्णय ीनिर्णय .निर्णय निर्णय एनिर्णय .निर्णय निर्णय N निर्णय 0 निर्णय .निर्णय
 1 निर्णय 5 निर्णय 9 निर्णय 9 निर्णय निर्णय मनिर्णय ेनिर्णय ंनिर्णय निर्णय दनिर्णय
 िनिर्णय ननिर्णय ानिर्णय ंनिर्णय कनिर्णय िनिर्णय तनिर्णय निर्णय 1 निर्णय 4 निर्णय
 .निर्णय 0 निर्णय 2 निर्णय .निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय निर्णय सनिर्णय ेनिर्णय
 ।निर्णय

सह

2023 की मध्यस्थता याचिका संख्या 25।

रूप:

अरविंद पी दातार, निखिल सखारदंडे, जयंत मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता।, देबेश पांडा, सुश्री
 अमृता पांडा, नमन माहेश्वरी, सुश्री स्नेहल माहेश्वरी, रामेश्वर टोटाला, राहुल टोटाला, उदभव
 गाडी, आशीष वेणुगोपाल, सुश्री सोनाली माथुर, सिद्धार्थ सिजोरिया, गर्व मल्होत्रा, ईशान ए
 चतुर्वेदी, अरिजीत सान्याल, सुश्री अरुंधति काले, उमर अहमद, प्रत्यूष मिगलानी, प्रणव मागो,
 कनिष्क अग्रवाल, श्री आदित्य कुमार, सूरज शर्मा, सुश्री पायल चावला, सुश्री हिना शाहीन,

सुश्री यामिनी डागा, शुभा स्वामी परांजपे, राघव भाटिया, सोयिब कुरैशी, अधिवक्ता।
याचिकाकर्ताओं के लिए।

श्याम दीवान, निखिल नय्यर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री प्रिथा श्रीकुमार अय्यर, सुलभ रेवाड़ी,
दिव्यांशु राय, रोंगोन चौधरी, सुश्री मानस्विनी जैन, अथर्व गुप्ता, रवि रघुनाथ, सुश्री आकाशी
लोढ़ा, धनाराम रामचंद्रन, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

गौरव बनर्जी, सीनियर एड., टी. एस. सुंदरम, सुभ्रो प्रोकास मुखर्जी, वेंकट सुप्रीत, मोहित
पांडे, राकेश तालुकदार, शशांक गर्ग, शिवांक दिदेली, (एन. एन. ग्लोबल में न्यायमित्र)

/

[2023] 15 एस सी आर।

डेरियस जे खंबाटा, नकुल दीवान, सुश्री मालविका त्रिवेदी, के रमाकांत रेड्डी, अरविंद वर्मा,
प्रशांतो चंद्र सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, विजेंद्र प्रताप सिंह, अभिज्ञान झा, सुश्री श्रेया चौधरी,
अंकितेश ओझा, तुषार हाथीरामानी, सुश्री श्रीनंदिनी मुखोपाध्याय, सुश्री विधि शाह, प्रद्युम्न
गोहिल, श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, सुश्री रानू पुरोहित, अलपति साहित्य कृष्ण, ऋषभ एन
कपाडिया, सुश्री निधि मित्तल, नील चटर्जी, सुश्री नूरिन सरना, सुश्री तानसी फोतेदार, सौमिल
ज्ञानवर, सत्येंद्र सहारन, रोहन नाइक, सतविक चंद्रशेखर, राहुल आर्य, प्रेमलाल कृष्णन,
विवेक सिंह, सुश्री बानी दीक्षित, माधव भाटिया, शैलेंद्र स्लारिया, योगेश शर्मा।हस्तक्षेप करने
वालों के लिए।

1093

इन आरई:आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अंतर्गत आर्बिट्रेशन
समझौतों के बीच हस्तक्षेप

सर्वोच्च
न्यायालय
का
निर्णय/आदेश
निर्णय

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

ए. संदर्भ. **5** * बी. प्रस्तुतियाँ. **12** * सी. रखरखाव. **18** * डी. भारतीय डाक टिकट
अधिनियम **1899.22** *i. अवलोकन। **22** *ii. किसी उपकरण पर मुहर लगाने में
विफलता के परिणाम **27** *

ए। स्टाम्प एक्ट. 27 * के अंतर्गत प्रक्रियाबी। अस्वीकृति और शून्यता के बीच का अंतर। 32 * ग. स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 किसी दस्तावेज़ को अस्वीकार्य और अमान्य नहीं बनाती है।

iii. मुद्रांक अधिनियम का उद्देश्य. 38 * ई. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996.40 *

i. मध्यस्थ स्वायत्तता। 42 * ii. न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप का सिद्धांत। 45 * iii. मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है। 52 * iv. आधुनिक मध्यस्थता के सिद्धांत। 54 *

च. मध्यस्थता समझौते पर विधि। **55 * i. मध्यस्थता समझौते की पृथक्ता। 56 ***

घ. यूनाइटेड किंगडम. 58 * ई. संयुक्त राज्य अमेरिका. 61 * च. सिंगापुर. 62 *

* एड नोट: पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

1094

/

[2023] 15 एस सी आर।

छ. अंतर्राष्ट्रीय समझौते। 62 * ज. भारत. 64 *

जी. योग्यता-योग्यता का सिद्धांत। **70 ***

आई. तुलनात्मक विश्लेषण. **71 * ii. भारत. 73 * iii. नकारात्मक योग्यता-योग्यता. 79 ***

एच. मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक हस्तक्षेप। **81 * I. मध्यस्थता अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम और अनुबंध अधिनियम का सामंजस्यपूर्ण निर्माण। 97 ***

आई. मध्यस्थता समझौतों के संबंध में मध्यस्थता अधिनियम की प्रधानता होगी। **101 ***

ए। मध्यस्थता अधिनियम एक विशेष विधि है और भारतीय अनुबंध अधिनियम और स्टाम्प अधिनियम सामान्य विधि हैं। बी। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5। 104 * ग. संसद स्टाम्प अधिनियम के बारे में तब जानती थी जब उसने मध्यस्थता अधिनियम. 106 * लागू किया था।

ii. विचाराधीन तीन अंतर्गत नूनों अंतर्गत सामंजस्यपूर्ण निर्माण। 106 *

ए। योग्यता-योग्यता सिद्धांत का प्रभाव। 106 * बी। डाक टिकट अधिनियम की धारा 33 और 35 में "होगा" शब्द का प्रभाव। ग. डाक टिकट अधिनियम का उद्देश्य संरक्षित है। घ. विधि की व्याख्या को स्टाम्प अधिनियम के अलावा मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावी बनाना चाहिए।

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1096 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच मध्यस्थता

जे. एस. एम. एस. टी एस्टेट और गरवारे वॉल रोप गलत तरीके से तय किए गए थे।

i. एस. एम. एस. चाय संपदा. 115 *ii. गारवेयर वॉल Ropes.119 *

के. भारत के मुख्य न्यायाधीश योजना, **1996** द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति. **124 *** एल. विद्या द्रोलिया मुद्रांकन के मुद्दे से संबंधित नहीं है. **126 *** एम. निष्कर्ष. **129 ***

ए *।संदर्भ

1. इस न्यायालय को तीन कानूनों-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996-1, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899-2 और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के संदर्भ में उत्पन्न एक मुद्दे को हल करने के लिए कहा गया है। 3 डाक टिकट अधिनियम "उपकरणों" पर शुल्क लगाता है। एक उपकरण जिस पर बिना मोहर या बिना ज्ञान के मुहर लगी हो, साक्ष्य में अस्वीकार्य है और उसके प्रावधानों के संदर्भ में उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मध्यस्थता समझौते अक्सर अंतर्निहित उपकरणों या मूल अनुबंधों में अंतर्निहित होते हैं। जब एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन किया जाता है, तो इस आधार पर एक आपत्ति उठाई जाती है कि मध्यस्थता समझौता अस्वीकार्य है क्योंकि यह एक ऐसे दस्तावेज में है जिस पर मुहर नहीं लगी है या अपर्याप्त रूप से मुहर लगी है। प्राथमिक मुद्दा जो उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या इस तरह के मध्यस्थता समझौते अस्तित्वहीन, अप्रवर्तनीय या अमान्य होंगे यदि अंतर्निहित अनुबंध पर मुहर नहीं लगाई गई है। जिस संदर्भ में यह प्रश्न उत्पन्न होता है, उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

2. एन एन ग्लोबल मर्केटाइल (पी) लिमिटेड बनाम इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड, 4

(इसके बाद "एन एन ग्लोबल 1" के रूप में संदर्भित) इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ को एक विशेष अनुमति याचिका में एक अप्रकाशित कार्य आदेश में निहित मध्यस्थता समझौते की प्रवर्तनीयता निर्धारित करने के लिए बुलाया गया था। पीठ ने न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के माध्यम से बोलते हुए कहा कि

* एड। ध्यान दें: भाग ए 1 "मध्यस्थता अधिनियम" 2 "स्टाम्प अधिनियम" 3 "अनुबंध अधिनियम"

4 (2021) 4 एस. सी. सी. 379

/

[2023] 15 एस सी आर।

एक मध्यस्थता समझौता, अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंध से अलग और अलग होने के कारण, अमान्य, अप्रवर्तनीय या अस्तित्वहीन नहीं होगा। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

कि स्टाम्प शुल्क का भुगतान न करने से अंतर्निहित अनुबंध भी अमान्य नहीं होगा क्योंकि यह एक उपचार योग्य दोष है। इस प्रक्रिया में, इस न्यायालय ने एस. एम. एस. टी एस्टेट (पी) के साथ भिन्नता पर एक दृष्टिकोण अपनाया।

लिमिटेड वी.चांदमारी टी कं. (पी) लिमिटेड **5** और गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम. तटीय समुद्री निर्माण और इंजीनियरिंग लिमिटेड **6** एस. एम. एस. टी एस्टेट (ऊपर) में,

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि बिना मोहर वाले अनुबंध में मध्यस्थता समझौते पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसकी दो-न्यायाधीशों की पीठ

गरवारे वॉल रोप्स (ऊपर) में न्यायालय ने एस. एम. एस. टी एस्टेट (ऊपर) पर भरोसा किया।

यह अभिनिर्धारित करना कि एक अप्रकाशित वाणिज्यिक अनुबंध में एक मध्यस्थता समझौता विधि के मामले के रूप में "मौजूद" नहीं होगा और जब तक अंतर्निहित अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लग जाती, तब तक उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती:

“22. जब कोई मध्यस्थता खंड "किसी अनुबंध में" निहित होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि समझौता केवल तभी अनुबंध बन जाता है जब यह विधि द्वारा लागू किया जा सके। हमने देखा है कि कैसे, स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत, एक समझौता एक अनुबंध नहीं बन जाता है, अर्थात्, यह विधि में लागू करने योग्य नहीं है, जब तक कि उस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई जाती है। इसलिए, धारा 11 (6-ए) को जब 1996 के अधिनियम की धारा 7 (2) और अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (एच) के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी समझौते में मध्यस्थता खंड तब मौजूद नहीं होगा जब वह विधि द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यह भी एक संकेतक है कि एस. एम. एस. टी एस्टेट्स [एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (पी) लिमिटेड v. चांदमारी टी कंपनी (पी) लिमिटेड, (2011) 14 एस. सी. सी. 66: (2012) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 777] को धारा 11 (6-ए) के संशोधन द्वारा किसी भी तरह से छुआ नहीं गया है।

[...]

29. हुंडई इंग में यह निर्णय। मामला [यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम. हुंडई इंग। & कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, (2018) 17 एस. सी. सी. 607

:(2019) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 530] इस मायने अंतर्गत महत्वपूर्ण है कि जो विशेष रूप से विचाराधीन था वह एक मध्यस्थता खंड था जो केवल तभी सक्रिय होगा जब कोई बीमाकर्ता देयता स्वीकार या स्वीकार करता है। तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि बीमाकर्ता ने दावे को अस्वीकार कर दिया, हालांकि एक मध्यस्थता

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1098 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच मध्यस्थता

खंड "मौजूद" था, इसलिए कहने के लिए, पॉलिसी में, यह विधि में मौजूद नहीं होगा, जैसा कि उस निर्णय में माना गया था, जब एक महत्वपूर्ण तथ्य पेश किया जाता है, अर्थात्, बीमाकर्ता ने दायित्व को स्वीकार या स्वीकार नहीं किया है। इसी तरह, वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि उप-अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड तब तक विधि में मामले के रूप में "मौजूद" नहीं होगा जब तक कि उप-अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लग जाती, जैसा कि हम ऊपर मान चुके हैं। यह तर्क कि धारा 11 (6-ए) धारा 8, धारा 16 और धारा 45 के विपरीत "अस्तित्व" से संबंधित है, जो एक मध्यस्थता समझौते की "वैधता" से संबंधित है, हुंडई एंग में अभिव्यक्ति "अस्तित्व" की इस अदालत की समझ से जवाब मिलता है। मामला [संयुक्त भारत]

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम हुंडई इंग। & निर्माण कंपनी लिमिटेड, (2018)

17 एससीसी 607:(2019) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 530], जैसा कि हमारे द्वारा अनुसरण किया जाता है। "

इसके बाद, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विद्या द्रोलिया बनाम.

दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, 7 ने गरवारे वॉल रोप के पैराग्राफ 29 का हवाला दिया

(उपर्युक्त) (ऊपर निकाला गया) इस प्रस्ताव के अनुमोदन के साथ कि एक मध्यस्थता समझौता केवल तभी मौजूद होता है जब वह वैध और कानूनी होता है:

“146. अब हम इस प्रश्न की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या धारा 11 में "अस्तित्व" शब्द केवल अनुबंध गठन (क्या कोई मध्यस्थता समझौता है) को संदर्भित करता है और प्रवर्तन (वैधता) के प्रश्न को बाहर करता है और इसलिए बाद वाला निर्देश स्तर पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। न्यायशास्त्र और पाठ्यवाद पर मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और मध्यस्थता समझौते की वैधता के बीच अंतर करना संभव है। इस तरह की व्याख्या "अस्तित्व" शब्द के स्पष्ट अर्थ से समर्थन प्राप्त कर सकती है। हालाँकि, न्यायशास्त्र और प्रासंगिकता पर यह मानना भी समान रूप से संभव है कि किसी समझौते का कोई अस्तित्व नहीं है यदि वह लागू करने योग्य नहीं है और बाध्यकारी नहीं है। एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व एक वैध समझौते का अनुमान लगाता है जिसे न्यायालय द्वारा पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए खारिज करके लागू किया जाएगा। कानूनी और सादे अर्थ की व्याख्या परिभाषा खंड सहित प्रासंगिक पृष्ठभूमि के विपरीत होगी और इसके परिणामस्वरूप अप्रिय परिणाम होंगे। "अस्तित्व" की एक उचित और न्यायपूर्ण व्याख्या के लिए संदर्भ, उद्देश्य और प्रासंगिक कानूनी समझ की आवश्यकता होती है।

/

[2023] 15 एस सी आर।

बाध्यकारी और प्रवर्तनीय मध्यस्थता समझौते के लिए लागू मानदंड। लिखित रूप में प्रमाणित समझौते का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि पक्षों को शर्तों का पालन करने और उनका पालन करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। एक पक्ष एक अप्रवर्तनीय दस्तावेज़ के आधार पर अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है। इस प्रकार, यह मानने के लिए अच्छे कारण हैं कि एक मध्यस्थता समझौता केवल तभी मौजूद होता है जब वह वैध और कानूनी होता है। एक शून्य और अप्रवर्तनीय समझ कुछ भी करने के लिए कोई समझौता नहीं है। एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का अर्थ है एक मध्यस्थता समझौता जो मध्यस्थता अधिनियम और अनुबंध अधिनियम दोनों की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और संतुष्ट करता है और जब यह विधि में लागू करने योग्य होता है।

147. हम विस्तार से आगे बढ़ेंगे और आगे के कारण देंगे:

147.1.(i) गारवेयर बॉल रोप्स लिमिटेड में [गारवेयर बॉल रोप्स लिमिटेड बनामा। तटीय समुद्री निर्माण और इंजीनियरिंग। लिमिटेड, (2019) 9 एससीसी 209:(2019)

4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 324], इस न्यायालय ने एक मध्यस्थता खंड के साथ एक अंतर्निहित अनुबंध में स्टाम्प शुल्क के प्रश्न की जांच की थी और इस संदर्भ में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 (2) के पहले और दूसरे भाग के बीच अंतर किया था, यद्यपि मध्यस्थता समझौते के "अस्तित्व" और "वैधता" के संदर्भ में ऊपर की गई और उद्धृत टिप्पणियाँ उपयुक्त और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, हम इसके पैरा 29 को पुनः प्रस्तुत करके इसे दोहराएंगे: (एस. सी. सी. पी. 238)

[...]

अस्तित्व और वैधता आपस में जुड़े हुए हैं, और मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है यदि यह अवैध है या अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। अमान्य समझौता कोई समझौता नहीं है। "

3. एन एन ग्लोबल 1 (ऊपर) ने विद्या द्रोलिया (ऊपर) में समन्वय पीठ के निर्णय को नोट किया और गरवारे बॉल रोप्स (ऊपर) के पैराग्राफ 22 और 29 और विद्या द्रोलिया (ऊपर निकाले गए) के पैराग्राफ 146 और 147 में अपनाए गए विचार की शुद्धता पर संदेह किया। इसने निम्नलिखित मुद्दे को एफ. आई. वी. न्यायाधीशों की पीठ को भेजा:

“58. [...] क्या स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 35 में निहित वैधानिक प्रतिबंध अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क के लिए प्रभार्य उपकरणों पर लागू होता है, ऐसे साधन में निहित मध्यस्थता समझौते को भी प्रस्तुत करेगा, जो स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए प्रभार्य नहीं है, क्योंकि यह अस्तित्व में नहीं है।

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1100 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच मध्यस्थता

अप्रवर्तनीय, या अमान्य, मूल अनुबंध/साधन पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान लंबित है? "

4. एन एन ग्लोबल मार्केटाइल (पी) लिमिटेड में संविधान पीठ बनाम.इंडो

यूनिक फ्लेम लिमिटेड 8 (इसके बाद "एन एन ग्लोबल 2" के रूप में संदर्भित) ने संदर्भ का उत्तर दिया। 3 के बहुमत से: 2, यह अभिनिर्धारित किया गया कि एन. एन. ग्लोबल 1 (उपर्युक्त) विधि की सही स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बहुमत के निर्णय (न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ द्वारा अपने और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस द्वारा न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार द्वारा एक सहमति वाले निर्णय के साथ लिखा गया) ने इस विचार को बरकरार रखा।

इस न्यायालय द्वारा एस. एम. एस. टी एस्टेट (ऊपर) और गरवारे वॉल रोप में लिया गया (ऊपर)। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने अलग-अलग असहमति वाले फैसले दिए। बहुमत के निष्कर्षों को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है:

ए। अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (जी) के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते वाला एक अनस्टैम्ड इंस्ट्रुमेंट अमान्य है।

बी। एक अनस्टैम्ड उपकरण, जो एक अनुबंध नहीं है और विधि में लागू करने योग्य नहीं है, विधि में मौजूद नहीं हो सकता है। ऐसे लिखत में मध्यस्थता समझौते पर विधिवत मुहर लगाने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है।

ग. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6 ए) के अंतर्गत विचार किए गए मध्यस्थता समझौते का "अस्तित्व" वास्तव में केवल चेहरे का अस्तित्व या अस्तित्व नहीं है, बल्कि "कानून में अस्तित्व" भी है।

घ. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कार्य करने वाला न्यायालय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 और 35 के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता है, जिसमें उसे बिना स्टाम्प वाले या कृत्रिम रूप से स्टाम्प वाले उपकरण की जांच करने और उसे जप्त करने की आवश्यकता होती है; और

ई. मध्यस्थता समझौते की प्रमाणित प्रतियों में स्पष्ट रूप से भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क का संकेत होना चाहिए।

5. अल्पमत निर्णय ने एक अलग कानूनी दृष्टिकोण अपनाया। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने कहा कि धारा 11 के अंतर्गत रेफरल न्यायालय का दायरा मध्यस्थता समझौते के "अस्तित्व" की जांच तक सीमित है। उनका मानना था कि मुद्रांकन के मुद्दे सहित अन्य सभी विवादास्पद मुद्दे,

/

[2023] 15 एस सी आर।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

6. न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने स्टाम्प अधिनियम की योजना पर भरोसा करते हुए कहा कि एक बिना स्टाम्प वाले या बिना ज्ञान के स्टाम्प वाले दस्तावेज़ को शुरू से ही अमान्य या अमान्य नहीं माना जाता है क्योंकि किसी उपकरण पर स्टाम्प लगाने में विफलता एक उपचार योग्य दोष है। इसके अलावा, न्यायमूर्ति रॉय ने यह देखने के लिए मध्यस्थता अधिनियम के विकास का पता लगाया कि यह मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 को मध्यस्थ के लिए मुद्रांकन के मुद्दे को स्थगित करके मुद्रांकन अधिनियम की धारा 35 के साथ सुसंगत बनाया जाना चाहिए। अंत में, न्यायमूर्ति रॉय ने कहा कि एस. एम. एस. टी एस्टेट (ऊपर) और गरवारे वॉल रोप (ऊपर) विधि की सही स्थिति निर्धारित नहीं करते हैं। 7. 14 फरवरी 2020 को इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने

धर्मरत्नाकर राय बहादुर आर्कोट नारायणस्वामी मुदलियार छत्रम बनाम भास्कर राजू और ब्रदर्स **9** ने एस. एम. एस. टी एस्टेट (ऊपर) का हवाला दिया।

स्वीकृति के साथ। भास्कर राजू (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस निर्णय को उलट दिया जिसने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के अंतर्गत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक असंवेदनशील लीज डीड पर भरोसा किया था। भास्कर राजू (सुप्रा) को एन एन ग्लोबल 1 (सुप्रा) से पहले तय किया गया था। हालांकि, एन एन ग्लोबल 1 (ऊपर) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया संदर्भ लंबित था, लेकिन भास्कर राजू (ऊपर) में समीक्षा याचिकाओं का नेतृत्व किया गया था। 20 जुलाई 2021 को, पुनर्विचार याचिका को देरी के साथ-साथ गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था। 10 7 दिसंबर 2022 को भास्कर राजू (ऊपर) के पुनर्विचार की मांग करने वाली एक सुधारात्मक याचिका दायर की गई थी। एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) में संविधान पीठ ने संदर्भ का जवाब दिया और 25 अप्रैल 2023 को अपना फैसला सुनाया।

8. 8 मई 2023 को, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सेका डोब्रिक बनाम एसए इओनसोफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक याचिका में नोटिस जारी किया।¹¹ इस बीच, 18 जुलाई 2023 को इस न्यायालय की एक न्यायाधीश पीठ ने भास्कर राजू (उपरोक्त) में सुधारात्मक याचिका में नोटिस जारी किया और मामले को 24 अगस्त को खुली अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

10 सीए संख्या 1599/2020 में याचिका (सिविल) संख्या 704/2021 की समीक्षा करें। 11 2023 1101 की मध्यस्थता याचिका संख्या 25

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1102

2023. 12 14 अगस्त 2023 को, सेका डोब्रिक (उपरोक्त) मामले में पीठ ने कहा कि उस मामले में आपत्तियों में से एक मध्यस्थता समझौते पर मुहर न लगाने से संबंधित थी। इसलिए, मध्यस्थता याचिका को भास्कर राजू (उपरोक्त) में सुधारात्मक याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे निकाला गया है:

“1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) और 11 (9) के अंतर्गत याचिका के जवाब में प्रतिवादी की ओर से उठाई गई आपत्तियों में से एक यह है कि मध्यस्थता समझौते पर मुहर नहीं लगी है।

2. इस न्यायालय द्वारा 2023 की सुधारात्मक याचिका (दीवानी) संख्या 44 पर नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है जिसे 24 अगस्त 2023 को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

3. इन कार्यवाहियों को तदनुसार सुधारात्मक याचिका के साथ 24 अगस्त 2023 को सूचीबद्ध किया जाएगा।

4. काउंटर अफि डेविट, यदि कोई हो, तो इस बीच में आगे बढ़ें। ”

9. 26 सितंबर 2023 को, पांच न्यायाधीशों की एक पीठ ने सुधारात्मक याचिका के साथ मध्यस्थता याचिका पर सुनवाई की। एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) में निर्णय के व्यापक प्रभावों और परिणामों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कार्यवाही को सात-न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया। आदेश का प्रासंगिक हिस्सा नीचे निकाला गया है:

“2. एन. एन. ग्लोबल मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड और अन्य में बहुमत के दृष्टिकोण के व्यापक प्रभावों और परिणामों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि कार्यवाही को सात-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि न्यायपीठ के विचार की शुद्धता पर पुनर्विचार किया जा सके। ” 10. यह इस संदर्भ में है कि कार्यवाही को 11 अक्टूबर 2023 को सात न्यायाधीशों की इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जब इस न्यायालय ने कारण शीर्षक को बदलने का निर्देश दिया था: “इन रे:मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच अंतःक्रिया।” हम मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को पुनः प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

12 2020 की सिविल अपील संख्या 1599 में 2021 की समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 704 में 2023 की सुधारात्मक याचिका (सिविल) संख्या 44।

/

[2023] 15 एस सी आर।

जैसा कि हमें विधि के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए कहा गया है। इस प्रक्रिया में, हम एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) के साथ-साथ अन्य सहायक मुद्दों में अपनाए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर विचार करेंगे।

बी *। प्रस्तुतियाँ

11. याचिकाकर्ताओं का मोटे तौर पर तर्क है कि एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) विधि की सही स्थिति निर्धारित नहीं करता है। याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों की ओर से विद्वान वकील की प्रस्तुतियों का सारांश नीचे दिया गया है। 12. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

ए। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6 ए) स्पष्ट रूप से मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करने के लिए रेफरल अदालत की शक्ति को स्वीकार करती है। इस तरह की जांच स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत मुद्रांकन की पर्याप्तता तक नहीं फैली है; बी। एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) में बहुमत ने धारा 11 (6 ए) को प्रभावी रूप से रद्द कर दिया है, जिसने इस न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच के लिए सीमित कर दिया है।

ग. मुद्रांक अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत निहित निर्देशों का पालन करने के लिए रेफरल स्तर पर अदालतों को अनिवार्य करना परीक्षा के प्रेषण से अधिक होगा। मध्यस्थता अधिनियम एक मध्यस्थता समझौते की जांच के लिए रेफरल न्यायालय के अधिकार को सुनिश्चित करता है न कि साधन को;

घ. मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास मुद्रांकन से संबंधित मुद्दों सहित अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने की क्षमता है।

ई. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 में गैर-अस्थाई खंड का समावेश मध्यस्थता प्रक्रिया में अदालतों के न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करता है और इसे स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए; और

च. मुद्रांकन की आवश्यकता किसी उपकरण को शून्य नहीं बनाती है। यह केवल साक्ष्य में उपकरण को तब तक अस्वीकार्य बनाता है जब तक कि स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोष ठीक नहीं हो जाता है।

* एड। ध्यान दें: भाग बी 1103

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1104

13. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री निखिल सखारदंडे ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

ए। मुद्रांकन में अवज्ञा एक इलाज योग्य दोष है, जिसका प्रभाव राज्य के राजस्व हित को सुरक्षित करते ही बंद हो जाता है।

बी। स्टाम्प शुल्क का भुगतान न करना, एक अस्थायी अनुबंध होने के कारण, मध्यस्थता समझौते की वैधता को प्रभावित नहीं कर सकता है; और

ग. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या धारा 11 के स्तर पर न्यायालयों को मुद्रांकन के मुद्दे की जांच करने के लिए अनिवार्य करने से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 में निहित न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप के विधायी उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा।

14. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री डेरियस जे खंबाटा ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

ए। पृथक्ता का सिद्धांत यह मानता है कि एक मध्यस्थता समझौता एक स्व-निहित समझौता है, जो अंतर्निहित अनुबंध से अलग है;

बी। एक अंतर्निहित अनुबंध के भीतर निहित एक मध्यस्थता समझौता स्टाम्प अधिनियम की धारा 5 के संदर्भ में एक "अलग मामला" होगा, और इसलिए अनुबंध की गैर-मुद्रांकन या अपर्याप्त मुद्रांकन के बावजूद वैध और प्रवर्तनीय बना रहेगा।

ग. एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) में बहुमत यह गलत तरीके से अभिनिर्धारित करके पृथक्करण के सिद्धांत को पूर्ण प्रभाव देने में विफल रहा कि अंतर्निहित अनुबंध पर मुहर न लगाने से ऐसे अनुबंध में निहित मध्यस्थता समझौते को वास्तव में अमान्य कर दिया जाएगा।

घ. गैर-मुद्रांकन या असंवेदनशील मुद्रांकन के कारण किसी दस्तावेज़ की अस्वीकृति के परिणामस्वरूप दस्तावेज़ अमान्य, अमान्य या कानून में अस्तित्वहीन नहीं होता है।

ई. एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) में बहुमत ने धारा 11 के अंतर्गत रेफरल न्यायालय को मुद्रांकन के लिए एक उपकरण की जांच करने के लिए अनिवार्य करके क्षमता-क्षमता के सिद्धांत की अवहेलना की;

/

[2023] 15 एस सी आर।

च. पूर्व-मध्यस्थता स्तर पर, रेफरल अदालतों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए मुद्रांकन से संबंधित सभी मुद्दों को छोड़ देना चाहिए; और

छ. मुद्रांक अधिनियम की धारा 33 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को मुद्रांकन के मुद्दों को निर्धारित करने के लिए "पक्षों की सहमति" से अधिकार हो सकता है। इस तरह के प्राधिकरण में अनिवार्य रूप से एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण शामिल है जिसका गठन मध्यस्थता समझौते के माध्यम से पक्षों की सहमति से किया जाता है।

15. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गौरव बनर्जी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

ए। मुद्रांक अधिनियम को लागू करने में विधायिका का उद्देश्य सार्वजनिक राजस्व की रक्षा करना है और व्यापार और वाणिज्य के सुचारू प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों को अमान्य करके वाणिज्यिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है।

बी. गैर-मुद्रांकन किसी उपकरण को शून्य नहीं बनाता है। ऐसा उपकरण, भले ही बिना मोहर वाला हो, वास्तव में और कानून में मौजूद है;

ग. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6 ए) के अंतर्गत रेफरल स्तर पर मुद्रांकन के पहलुओं की जांच उक्त प्रावधान की सरल भाषा और विधायी इरादे के विपरीत है; और घ। स्टाम्प शुल्क का निर्णय एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। स्टाम्प शुल्क के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत न्यायालय को अनिवार्य करना मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (13) के अंतर्गत निहित मध्यस्थों की शीघ्र नियुक्ति के लक्ष्य के खिलाफ होगा।

16. लर्नर सीनियर काउंसल श्री जयंत मेहता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

ए। यद्यपि मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य है, लेकिन इसका गैर-अनुपालन ठीक किया जा सकता है और एक बिना मुद्रांकित या बिना ज्ञान के मुद्रांकित उपकरण को अमान्य या अमान्य नहीं बनाता है। बी। एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) में बहुमत का दृष्टिकोण मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 से संबंधित नहीं है जो भारत में स्थित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मध्यस्थताओं में सुरक्षा के अंतरिम उपायों की मांग करने में एक गंभीर बाधा पैदा करता है; और 1105

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1106

ग. एक फाइ स्केल कानून एक एल. आई. एस. की मनोरंजन क्षमता को बाधित नहीं करता है, सिवाय इसके कि कानून निर्दिष्ट रूप से ऐसा निर्धारित करता है। डाक टिकट अधिनियम में मुद्रा की मनोरंजन क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

17. उत्तरदाताओं का काफी हद तक तर्क है कि एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) सही है और एस. एम. एस. टी एस्टेट (उपरोक्त) और गरवारे वॉल रोप्स (उपर्युक्त) में इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई सुसंगत स्थिति के अनुरूप है, जिसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उत्तरदाताओं और हस्तक्षेप करने वालों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों का सारांश नीचे दिया गया है।

18. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

ए। उपचारात्मक याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि निवेदन किए गए आधारों में से कोई भी रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।¹¹³

चूँकि उपचारात्मक याचिका विचारणीय नहीं है, इसलिए सात-न्यायाधीशों की पीठ का संदर्भ अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

बी। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6 ए) के अंतर्गत न्यायालय द्वारा की गई जांच केवल मध्यस्थता समझौते के चेहरे के अस्तित्व तक सीमित नहीं है। रेफरल न्यायालय को प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता दोनों की जांच करनी होती है।

सी. स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 धारा 11 की कार्यवाही के अंतर्गत अदालतों पर एक अनिवार्य कानूनी आवश्यकता डालती है कि वे एक बिना स्टाम्प वाले या कृत्रिम रूप से स्टाम्प वाले उपकरण को जब्त कर लें। जब तक स्टाम्प शुल्क और अपेक्षित दंड का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे दस्तावेज को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है या अन्यथा कार्यवाई नहीं की जा सकती है; और

घ. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 स्टाम्प अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के संचालन को सीमित नहीं करती है।

19. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री निखिल नय्यर ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

ए। धारा 11 (6 ए) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "परीक्षा" मध्यस्थता की वैधता की जांच पर विचार करती है।

13 (2002) 4 एस. सी. सी. 388

/

[2023] 15 एस सी आर।

समझौता, जिसमें मुद्रांकन की पर्याप्त योग्यता की जांच शामिल है; और

बी। मध्यस्थता अधिनियम में धारा 11 (6 ए) को शामिल करने का उद्देश्य एस. एम. एस. चाय संपदा (उपरोक्त) के प्रभाव को कम करना नहीं था। 20. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नकुल दीवान ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

ए। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 में निहित पृथक्ता के सिद्धांत का तात्पर्य है कि एक मध्यस्थता समझौते को केवल इसकी वैधता या प्रवर्तनीयता निर्धारित करने के उद्देश्य से एक अलग समझौते के रूप में माना जा सकता है।

बी। धारा 11 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने वाले न्यायालय को पक्षकारों द्वारा पक्षों के अधिकारों और दायित्वों के ठोस निर्णय के उद्देश्य से साक्ष्य प्राप्त करने के लिए नामित नहीं किया जाता है; और ग। यहां तक कि अगर मध्यस्थता समझौते वाले किसी दस्तावेज पर कोई मुहर नहीं लगी है या उस पर पूरी तरह से मुहर नहीं लगी है, तो भी इस तरह की अपर्याप्तता या अपर्याप्तता मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6 ए) के अंतर्गत रेफरल चरण में मध्यस्थ

की नियुक्ति को पटरी से नहीं उतारनी चाहिए। 21. सुश्री माधवी दीवान, श्री प्रशांत चंद्र सेन, श्री अरविंद वर्मा, श्री रमेश सिंह, श्री के. रमाकांत रेड्डी, श्री राहुल जी. तनवानी, श्री अबीर फूकन, श्री तेजास करिया, श्री पल्लव मोंगिया, श्री कुणाल वाजानी, सुश्री अपोर्वा नेरल, श्री वरुण के. चोपड़ा, डॉ. पी. वी. अमामदा प्रसाद, श्री गौहर मिर्जा, सुश्री हीराल गुप्ता, श्री जॉर्ज पूथन पूथिकोट, सुश्री मनीषा सिंह, श्री शादन फरासत, श्री सौरव अग्रवाल, श्री सिद्धांत बक्सी, सुश्री प्रियंका वोरा, श्री देबांशु खेत्री, श्री शिवम सिंह, सुश्री दीया कपूर और श्री जतिंदर कुमार सेठी इसके पूरक थे।

सी *।रखरखाव

22. हम इस खंड में वर्तमान कार्यवाही की स्थिरता के प्रारंभिक मुद्दे को संबोधित करते हैं। कार्यवाही के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि 18 जुलाई 2023 को सुधारात्मक याचिका में नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद, सेका डोब्रिक (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए धारा 11 के आवेदन पर सुनवाई करते हुए, उपचारात्मक याचिका के साथ कार्यवाही को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। 26 सितंबर 2023 को, एन. एन. ग्लोबल 2 में लिए गए दृष्टिकोण के साथ न्यायपीठ अलग हो गई।

* एड। ध्यान दें: पार्ट सी 1107

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1108

(ऊपर) और इस मुद्दे को सात-न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया। इस प्रकार, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुधारात्मक याचिका के साथ, वर्तमान कार्यवाही में इस न्यायालय के समक्ष एक धारा 11 याचिका भी सूचीबद्ध है।

23. विधि के विकास में निरंतरता और निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक अनुशासन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। न्यायिक अनुशासन के नियम की मांग है कि कम संख्या वाली पीठ एक बड़ी पीठ के फैसले से बंधी हो। 14 न्यायिक अनुशासन यह भी निर्धारित करता है कि आम तौर पर, एक ही शक्ति की एक पीठ एक समन्वित पीठ द्वारा दिए गए निर्णय की शुद्धता पर प्रश्न उठा सकती है। ऐसी स्थिति में, मामले को अधिक संख्या वाली पीठ के समक्ष रखा जाता है। 15

24. हालाँकि, ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं जहाँ कम संख्या वाली पीठ अधिक संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए निर्णय से अलग हो गई है। भारत संघ बनाम हंसोली देवी, 16 मामले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की व्याख्या से संबंधित मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के साथ फैसला सुनाया और मामले को संविधान पीठ को भेज दिया। संविधान पीठ ने कहा कि दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया संदर्भ "अनुचित" था। फिर भी, संविधान पीठ

संदर्भ का उत्तर देने का निर्णय लिया "क्योंकि इसमें शामिल प्रश्न विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई मामलों में लंबित हैं और अधिनियम की धारा 28-ए के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में कुछ संदेह उत्पन्न हुए हैं।" में।

दाउदी बोहरा समुदाय का केंद्रीय बोर्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य, 17

इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि हंसोली देवी (उपरोक्त) में अपनाया गया न्यायिक पाठ्यक्रम एक नियम के बजाय अपवाद के रूप में था। इसलिए, न्यायिक अनुशासन के नियम में कुछ निश्चित अपवाद भी हैं।²⁵ प्रतिवादी ने संविधान पीठ के निर्णय पर भरोसा किया है

इस न्यायालय ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन, 18 में यह प्रस्तुत करने के लिए कि इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के आह्वान को उचित ठहराने के लिए कोई जीवित कारण या मामला नहीं है। सेका डोब्रिक (ऊपर) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मुद्दा धारा 11 के स्तर पर एक मध्यस्थ की नियुक्ति से संबंधित है जब अंतर्निहित अनुबंध पर मुहर नहीं लगाई जाती है या वैज्ञानिक रूप से मुहर नहीं लगाई जाती है। पीठ ने निर्देश दिया कि

14 भारत पेट्रोलियम निगम बनाम मुंबई श्रमिक संघ, (2001) 4 एससीसी 448 15 प्रदीप चंद्र परिजा बनाम प्रमोद चंद्र पटनायक, (2002) 1 एससीसी 1

16 (2002) 7 एससीसी 273 17 (2005) 2 एससीसी 673

18 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 544

/

[2023] 15 एस सी आर।

एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) से होने वाले व्यापक कानूनी प्रभावों को देखते हुए धारा 11 के आवेदन को उपचारात्मक याचिका के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा। इसलिए, प्रतिवादी का तर्क गलत है क्योंकि सेका डोब्रिक (उपरोक्त), जो एक जीवित कारण या मामला है, भी उपचारात्मक याचिका के साथ सूचीबद्ध है।²⁶ प्रत्यर्थी ने यह भी तर्क दिया है कि संविधान पीठ के लिए मामले को सात न्यायाधीशों की इस पीठ को भेजने के लिए अपने उपचारात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना अनुचित था। उच्चतम न्यायालय नियम 2013 के आदेश VI नियम 2 में यह प्रावधान है कि यदि कोई पीठ किसी कारण, अपील या "अन्य कार्यवाही" की सुनवाई के दौरान यह मानती है कि मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा निपटाया जाए, तो वह मामले को मुख्य न्यायाधीश को भेजेगी, जो इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए ऐसी पीठ का गठन करेगा। कांतारू राजीवरु बनाम भारतीय युवा अधिवक्ता संघ, 19 में इस विधि की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि उच्चतम विधि नियम, 2013 के आदेश VI नियम 2 में प्रयुक्त "अन्य कार्यवाही" शब्द एक व्यापक शब्द है जो अदालत को मामले में पक्षों के साथ न्याय करने की व्यापक स्वतंत्रता देता है। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि

पुनरीक्षण याचिकाएं भी "अन्य कार्यवाही" अभिव्यक्ति के दायरे में आती हैं।" कांतारू राजीवरु (उपरोक्त) में निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 के आदेश VI नियम 2 के अंतर्गत "अन्य कार्यवाही" शब्द में उपचारात्मक याचिकाएं भी शामिल होंगी। इसलिए, हम इस पीठ को दिए गए निर्देश में कोई अनियमितता नहीं समझते हैं।

27. इसके अलावा, संदर्भ विधि के बिंदुओं पर महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है, जिन पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता होती है। दाउदी बोहरा समुदाय के केंद्रीय बोर्ड (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित नियमों के लिए दो अपवाद निर्धारित किए:

“12. (3) उपरोक्त नियम दो अपवादों के अधीन हैं: (i) उपर्युक्त नियम मुख्य न्यायाधीश के विवेकाधिकार को बाध्य नहीं करते हैं, जिसमें रोस्टर तैयार करने की शक्ति निहित है और जो किसी विशेष मामले को किसी भी शक्ति की किसी विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखने का निर्देश दे सकता है; और (ii) ऊपर निर्धारित नियमों के बावजूद, यदि मामला पहले ही बड़ी कोरम की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आ चुका है और वह पीठ स्वयं महसूस करती है कि कम कोरम की पीठ द्वारा लिए गए विधि के दृष्टिकोण, जो विचार संदेह में है, में सुधार या पुनर्विचार की आवश्यकता है, तो अपवाद के रूप में (और नियम के रूप में नहीं) और निम्नलिखित कारणों से।

19 (2020) 9 एससीसी 121 1109

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1110 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

यदि, वह मामले की सुनवाई करने के लिए आगे बढ़ सकता है और एक विशिष्ट संदर्भ की आवश्यकता या पीठ और ऐसी सूची का गठन करने वाले मुख्य न्यायाधीश के आदेश के साथ प्रश्न में पिछले निर्णय की शुद्धता की जांच कर सकता है। रघुबीर सिंह [(1989) 2 एस. सी. सी. 754] और हंसोली देवी [(2002) 7 एस. सी. सी. 273] में ऐसी स्थिति थी। "

28. दाउदी बोहरा समुदाय के केंद्रीय बोर्ड (उपरोक्त) में निर्धारित दो असाधारण स्थितियों को सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए, और उन स्थितियों में जिनमें विधि के लिए व्यापक प्रभाव शामिल हैं। गंगा चीनी में

निगम लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 20 न्यायाधीश वी. आर. कृष्ण अय्यर

संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कहा गया कि "विधायी नीति

देश में संविधान पीठ द्वारा इस न्यायालय के निर्णयों को तब तक अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि विषय राष्ट्रीय जीवन के लिए इतना मौलिक महत्व का न हो या बाद के विचार के आलोक में तर्क इतना स्पष्ट रूप से गलत न हो कि लगातार सही होने की तुलना में अंततः सही होना बुद्धिमानी है।

गलत है।” हमारी राय है कि निर्णायक-न्यायाधीश पीठ द्वारा दिया गया संदर्भ भारत में मध्यस्थता विधि की व्याख्या और अनुप्रयोग के संबंध में मौलिक महत्व का प्रश्न उठाता है, जिसका बदले में देश में व्यापार और वाणिज्य पर प्रभाव पड़ता है। तदनुसार, हम अलग-अलग मामलों के तथ्यों में तल्लीन हुए बिना संदर्भ का जवाब देंगे। उपचारात्मक याचिका की स्थिरता का मुद्दा खुला छोड़ दिया गया है और प्रतिवादी द्वारा एक उपयुक्त पीठ के समक्ष उठाया जा सकता है।

डी *। भारतीय डाक टिकट अधिनियम **1899** i.सारांश

29. जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, स्टाम्प अधिनियम एक ऐसा विधान है जो कानून में निर्दिष्ट तरीके से कुछ उपकरणों के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान से संबंधित कानूनों को समेकित करता है। धारा 2 (14) "साधन" को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

“(14) “उपकरण में शामिल हैं -

(क) प्रत्येक दस्तावेज, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व बनाया गया है, हस्तांतरित किया गया है, सीमित किया गया है, विस्तारित किया गया है, समाप्त किया गया है या दर्ज किया गया है;

* एड। ध्यान दें: भाग डी 20 (1980) 1 एस. सी. 223

/

[2023] 15 एस सी आर।

(बी) स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी में लेनदेन के लिए बनाया गया एक इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा दस्तावेज, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व बनाया गया है, या बनाया गया है, स्थानांतरित किया गया है, सीमित किया गया है, बढ़ाया गया है, समाप्त किया गया है या दर्ज किया गया है; और

(ग) अनुसूची I में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज, लेकिन इसमें ऐसे दस्तावेज शामिल नहीं हैं जिन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

30. "उपकरण" शब्द को व्यापक रूप से समावेशी अर्थों में परिभाषित किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज शामिल हैं। मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची I में उनमें से प्रत्येक पर देय मुद्रांक शुल्क के साथ विभिन्न उपकरणों का विवरण शामिल है। धारा 3 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जा सकता है, जो निम्नानुसार है:

“3. शुल्क के साथ प्रभार्य उपकरण।— इस अधिनियम के प्रावधानों और अनुसूची I में निहित छूटों के अधीन, निम्नलिखित लिखत उस अनुसूची में इंगित राशि के शुल्क के साथ क्रमशः उचित शुल्क के रूप में प्रभार्य होंगे, अर्थात्-(ए) उस अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक

लिखत, जिसे पहले किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है, भारत में जुलाई, 1899 के पहले दिन या उसके बाद निष्पादित किया जाता है।

((ख) भारत में मांग पर या उस दिन या उसके बाद भारत से निकाले गए या बनाए गए वचन पत्र और स्वीकार किए गए या भुगतान किए गए, या स्वीकृति या भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए, या समर्थन किए गए, हस्तांतरित किए गए या अन्यथा बातचीत किए गए, के अलावा अन्य कोई भी देय विनिमय पत्र; और

(ग) उस अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक लिखत (विनिमय पत्र या वचन पत्र के अलावा), जिसे पहले किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है, उस दिन या उसके बाद भारत से बाहर निष्पादित किया जाता है, भारत में स्थित किसी संपत्ति या भारत में किए गए या किए जाने वाले किसी मामले या वस्तु से संबंधित है और भारत में प्राप्त होता है:

बशर्ते कि इनके संबंध में कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा -

(1) 1111 ऐसे मामलों में सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित कोई लिखत जहां इस छूट के लिए सरकार ऐसे लिखत के संबंध में प्रभार्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1112 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

(2) मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम, 1894 के अंतर्गत या 1838 का अधिनियम, 19 या भारत जहाज पंजीकरण अधिनियम, 1841 के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी जहाज या पोत की बिक्री, हस्तांतरण या अन्य निपटान के लिए कोई साधन, या तो पूरी तरह से या बंधक के रूप में या अन्यथा, या किसी भी भाग, ब्याज, शेयर या संपत्ति।

(3) विकासकर्ता या इकाई की ओर से या उसके पक्ष में या विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों को पूरा करने के संबंध में निष्पादित कोई लिखत।

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विकासकर्ता", "विशेष आर्थिक क्षेत्र" और "इकाई" शब्दों का अर्थ विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (जी), (जेडए) और (जेडसी) में क्रमशः दिया जाएगा। "

31. धारा 3 में प्रावधान है कि खंड (ए), (बी) और (सी) में लिखतों की तीन श्रेणियां अनुसूची I में दर्शाई गई राशि के शुल्क के साथ प्रभार्य होंगी। स्टाम्प अधिनियम की धारा 5 के संदर्भ में, किसी भी लिखत पर प्रभार्य शुल्क जो कई अलग-अलग मामलों को शामिल करता है या उनसे संबंधित है, कर्तव्यों की कुल राशि है जिसके साथ अलग-अलग लिखत (प्रत्येक जिसमें कई मामलों में से एक शामिल है या उससे संबंधित है) एक ही कानून के अंतर्गत प्रभार्य होगी। धारा 6 उन स्थितियों को नियंत्रित करती है जहां एक ही उपकरण अनुसूची I में दो या दो से अधिक विवरणों के भीतर आता है। ऐसी स्थिति में, यदि अलग-अलग विवरणों के

अंतर्गत प्रभार्य कर्तव्य अलग-अलग हैं, तो उपकरण उनमें से उच्चतम के साथ प्रभार्य होगा। धारा 6 में नियम धारा 5 के प्रावधानों के अधीन है। परिणामस्वरूप, स्टाम्प शुल्क के भुगतान से बचने के लिए धारा 6 पर भरोसा नहीं किया जा सकता है यदि कोई लिखत अनुसूची I में एक अलग प्रविष्टि द्वारा कवर किए गए प्रत्येक ऐसे मामले के साथ कई अलग-अलग मामलों से संबंधित है। धारा 6 केवल तभी लागू होती है जब कोई लिखत एक ही मामले से संबंधित होती है जो अनुसूची I में दो या दो से अधिक विवरणों द्वारा कवर की गई हो, या जब कई अलग-अलग मामलों से संबंधित किसी लिखत में एक ही मामले को उस अनुसूची में दो या दो से अधिक विवरणों द्वारा कवर किया गया हो।

32. धारा 13 और 14 मुद्रांकन के तरीके को इंगित करते हैं। धारा 13 के संदर्भ में, कागज पर लिखे गए प्रत्येक उपकरण पर एक छाप के साथ मुहर लगाई गई है।

/

[2023] 15 एस सी आर।

डाक टिकट इस तरह से लिखा जाएगा कि डाक टिकट उपकरण के चेहरे पर दिखाई दे और इसका उपयोग किसी अन्य उपकरण के लिए या उस पर नहीं किया जा सकता है। धारा 14 में कहा गया है कि शुल्क के साथ प्रभार्य कोई दूसरा लिखत मुहर लगे कागज के उस टुकड़े पर नहीं लिखी जाएगी जिस पर शुल्क के साथ प्रभार्य लिखत पहले ही लिखी जा चुकी हो।²¹ धारा 15 महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह धारा 13 और 14 के गैर-अनुपालन के प्रभाव को इंगित करती है: धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखे गए उपकरणों को अप्रकाशित माना जाएगा।²²

33. मुद्रांक अधिनियम के अध्याय 2 में विभिन्न अन्य आकस्मिकताओं या स्थितियों का प्रावधान है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समुद्री-बीमा की नीतियां, 23 बॉन्ड, डिबेंचर और प्रतिभूतियां, स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी में 24 लेनदेन, 25 और भारत के बाहर निष्पादित उपकरण शामिल हैं।²⁶ अध्याय 2 स्टाम्प शुल्क के मूल्यांकन के लिए भी प्रावधान करता है, जिसमें विदेशी मुद्राओं में व्यक्त राशि का रूपांतरण, 27 स्टॉक और विपणन योग्य प्रतिभूतियों का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाए, 28 विनिमय दर या औसत मूल्य के विवरण का प्रभाव, 29 साधन आरक्षित ब्याज, 30 साधन विपणन योग्य प्रतिभूतियों के बंधक से जुड़े, 31 ऋण आदि का हस्तांतरण और विचार कैसे लिया जाना है, वार्षिकी के मामले में 32 मूल्यांकन, 33 स्टाम्प जहां विषय-वस्तु का मूल्य अनिश्चित है।³⁴

21 धारा 14 के परंतुक में निम्नलिखित प्रावधान है "बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी नहीं है।

ऐसा कोई भी समर्थन, जिस पर विधिवत मुहर लगी हो या उस पर शुल्क नहीं लगाया जा रहा हो, जिसे किसी ऐसे अधिकार को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से या किसी ऐसे धन या माल की प्राप्ति को स्वीकार करने के लिए किया जा रहा हो, जिससे भुगतान या वितरण सुनिश्चित किया गया हो, उस पर रोक लगाएगा। "

22 धारा 15, स्टाम्प अधिनियम 23 धारा 7, स्टाम्प अधिनियम

24 धारा 8 से 8 एफ, स्टाम्प अधिनियम 25 धारा 9 ए, स्टाम्प अधिनियम 26 धारा 18,19, स्टाम्प अधिनियम 27 धारा 20, स्टाम्प अधिनियम 28 धारा 21, स्टाम्प अधिनियम 29 धारा 22, स्टाम्प अधिनियम 30 धारा 23, स्टाम्प अधिनियम 31 धारा 23 ए, स्टाम्प अधिनियम 32 धारा 24, स्टाम्प अधिनियम 33 धारा 25, स्टाम्प अधिनियम 34 धारा 26, स्टाम्प अधिनियम 1113

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते 1114 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

34. धारा 29 इंगित करती है कि स्टाम्प शुल्क किसके द्वारा वहन किया जाना है (इसके विपरीत समझौते के अभाव में) और धारा 30 में कहा गया है कि कुछ मामलों में रसीद दी जानी चाहिए।

35. एक व्यक्ति स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत किसी विशेष साधन पर देय शुल्क (यदि कोई हो) के बारे में अपनी राय के लिए कलेक्टर को भी आवेदन कर सकता है। कलेक्टर को उनकी राय के लिए दिए गए लिखत को निष्पादित किया जा सकता है या पहले से मुहर लगाई जा सकती है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि इसे निष्पादित किया जाना चाहिए या पहले से मुहर लगाई जानी चाहिए।³⁵ यदि धारा 31 के अंतर्गत कलेक्टर के पास लाया गया कोई लिखत उनकी राय में शुल्क के साथ प्रभार्य है, और वे यह निर्धारित करते हैं कि उस पर पहले से ही पूरी तरह से मुहर लगी हुई है, या कि धारा 31 के अंतर्गत उनके द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो वे ऐसे लिखत पर समर्थन द्वारा प्रमाणित करेंगे कि जिस पूर्ण शुल्क के साथ वह प्रभार्य है, उसका भुगतान कर दिया गया है।³⁶ यदि कलेक्टर की राय है कि उपकरण शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं है, तो वे प्रमाणित करेंगे कि यह इतना प्रभार्य नहीं है।³⁷ कोई भी लिखत जिस पर धारा 32 के अंतर्गत समर्थन किया गया है, उस पर विधिवत मुहर लगी हुई या शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।³⁸ धारा 32 के परंतुक में तीन श्रेणियों के उपकरणों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें कलेक्टर उसी धारा के अंतर्गत अनुमोदित करने के लिए अधिकृत नहीं है।

36. स्टाम्प अधिनियम के अध्याय IV में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण दिया गया है, यदि स्टाम्प लगाने योग्य उपकरणों पर विधिवत मुहर नहीं लगाई जाती है। इस अध्याय के प्रावधानों की बाद के खंड में विस्तार से जांच की गई है। अध्याय 5 में कुछ मामलों में डाक टिकटों (जैसे खराब या दुरुपयोग किए गए डाक टिकट) के लिए भत्ते का प्रावधान है और अध्याय 6 में अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को उच्च न्यायालयों सहित अधिकारियों को संदर्भित करने के साथ-साथ डाक टिकटों की पर्याप्तता के संबंध में न्यायालयों के कुछ निर्णयों के संशोधन का भी प्रावधान है। मुद्रांक अधिनियम के अध्याय VII में इसके प्रावधानों का पालन न करने के लिए दंड का संकेत दिया गया है और अध्याय VIII में कानून के संबंध में कुछ पूरक प्रावधान हैं।

35 धारा 31 (1), स्टाम्प अधिनियम 36 धारा 32 (1), स्टाम्प अधिनियम 37 धारा 32 (2), स्टाम्प अधिनियम 38 धारा 32 (3), स्टाम्प अधिनियम

ii. किसी उपकरण पर मुहर लगाने में विफलता के परिणाम **a.** मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रिया

37. डाक टिकट अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है कि भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा शुल्क के साथ प्रभार्य और निष्पादित किए जाने वाले सभी उपकरणों पर निष्पादन से पहले या उसके समय मुहर लगाई जाएगी। धारा 62 अन्य बातों के साथ-साथ धारा 17 का पालन करने में विफलता को दंडित करती है। हालांकि, इस आदेश के बावजूद कि शुल्क के साथ चार्ज करने योग्य सभी उपकरणों पर मुहर लगाई जानी चाहिए, कई उपकरणों पर मुहर नहीं लगाई जाती है या उन पर पूरी तरह से मुहर नहीं लगाई जाती है। किसी लिखत को निष्पादित करने वाले पक्ष, विधि के अधिदेश के विपरीत, स्टाम्प शुल्क के भुगतान से बचने का प्रयास कर सकते हैं और इसलिए उस पर मुहर लगाने से बच सकते हैं। इस स्थिति के अलावा, अन्य तरीके हैं जिनसे किसी उपकरण पर ठीक से मुहर नहीं लगाई जा सकती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

ए। शुल्क का भुगतान अनुसूची I के अंतर्गत गलत विवरण के अंतर्गत किया गया हो सकता है;

बी। देय शुल्क पर्याप्त राशि का हो सकता है लेकिन अनुचित विवरण का हो सकता है।

ग. धारा 5 के प्रावधान जो कई अलग-अलग मामलों से संबंधित उपकरणों को नियंत्रित करते हैं, उनका अनुपालन नहीं किया गया हो सकता है; या घ। लिखत को धारा 13 और 14 के उल्लंघन में लिखा जा सकता है, और इस प्रकार धारा 15 के संदर्भ में अप्रकाशित माना जा सकता है।

38. विधायिका ने माना कि स्टाम्प अधिनियम के जनादेश का पालन पिछले पैराग्राफ में सूचीबद्ध कारणों या अन्यथा के कारण नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य की मान्यता में ही अध्याय IV के प्रावधानों को अधिनियमित किया गया था। धारा 33 में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है (या तो विधि द्वारा या पक्षों की सहमति से) वह एक ऐसे दस्तावेज को जब्त करेगा जो उनकी राय में शुल्क के साथ प्रभार्य है, लेकिन जिस पर विधिवत मुहर नहीं लगी है। धारा 33 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब प्राधिकरण के समक्ष कोई उपकरण पेश किया जाता है या जब वे अपने कार्यों के प्रदर्शन में इसे देखते हैं। पुलिस अधिकारियों को छोड़कर सार्वजनिक कार्यालयों के प्रभारी व्यक्तियों को धारा 33 के अंतर्गत समान रूप से सशक्त किया जाता है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

1115

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते 1116 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

“33. उपकरणों की जाँच और ज़ब्त करना।—(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे विधि द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है, और सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति, पुलिस के एक अधिकारी को छोड़कर, जिसके समक्ष, उसकी राय में, कर्तव्य के साथ कोई प्रभार्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है या अपने कार्यों के निष्पादन में आता है, यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे दस्तावेज पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है, तो उसे ज़ब्त कर लिया जाएगा।

(2) उस उद्देश्य के लिए ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपने समक्ष इस तरह से प्रभार्य और इस तरह से प्रस्तुत या आने वाले प्रत्येक उपकरण की जांच करेगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उस पर भारत में लागू विधि द्वारा आवश्यक मूल्य और विवरण की मुहर लगी है जब ऐसा उपकरण निष्पादित किया गया था या पहली बार निष्पादित किया गया था:

बशर्ते कि -

(क) इसमें निहित किसी भी बात के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि किसी आपराधिक न्यायालय के किसी मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश से दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अध्याय XII या अध्याय XXXVI के अंतर्गत कार्यवाही के अलावा किसी अन्य कार्यवाही के दौरान उसके सामने आने वाले किसी भी दस्तावेज की जांच करने या ज़ब्त करने की आवश्यकता है, यदि वह ऐसा करने के लिए नहीं सोचता है।

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में, इस धारा के अंतर्गत किसी भी लिखत की जांच करने और उसे ज़ब्त करने का कर्तव्य ऐसे अधिकारी को सौंपा जा सकता है जिसे न्यायालय इस संबंध में नियुक्त करता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, संदेह के मामलों में -

(क) राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि कौन से अधिकारी सार्वजनिक अधिकारी माने जाएंगे; और

(ख) राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि सार्वजनिक कार्यालयों के प्रभारी व्यक्ति कौन माने जाएंगे। "

39. धारा 35 इस न्यायालय के समक्ष मुद्दे के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है-यह उन उपकरणों को प्रस्तुत करती है जिन पर साक्ष्य में विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है। धारा 35 इस प्रकार है:

“35. जिन उपकरणों पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, वे साक्ष्य आदि में अस्वीकार्य हैं।—

कर्तव्य के साथ प्रभार्य किसी भी दस्तावेज को किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसके पास विधि द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है, या उस पर कार्रवाई की जाएगी, पंजीकृत या पंजीकृत किया जाएगा।

ऐसे किसी भी व्यक्ति या किसी भी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा प्रमाणित, जब तक कि इस तरह के उपकरण पर विधिवत मुहर न लगे:

बशर्ते कि -

((क) ऐसा कोई भी लिखत उस शुल्क के भुगतान पर, जिसके साथ वह प्रभार्य है, साक्ष्य में स्वीकार किया जाएगा, या उस उपकरण के मामले में, जिस पर संज्ञानात्मक रूप से मुहर लगी हो, उस शुल्क को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि के साथ-साथ पांच रुपये के जुर्माने के साथ, या जब उचित शुल्क या उसके अवज्ञाकारी हिस्से की राशि का दस गुना पांच रुपये से अधिक हो, तो उस शुल्क या हिस्से के दस गुना के बराबर राशि के साथ।

(ख) जहां कोई व्यक्ति जिससे मुहर लगी रसीद की मांग की जा सकती थी, ने एक बिना मुहर वाली रसीद दी है और ऐसी रसीद, यदि मुहर लगी है, तो उसके खिलाफ साक्ष्य में स्वीकार्य होगी, तो ऐसी रसीद को देने वाले व्यक्ति द्वारा एक रुपये के जुर्माने के भुगतान पर उसके खिलाफ साक्ष्य में स्वीकार किया जाएगा।

(ग) जहां किसी भी प्रकार का अनुबंध या समझौता दो या दो से अधिक पत्रों वाले पत्राचार द्वारा किया जाता है और किसी भी पत्र पर उचित मुहर होती है, तो अनुबंध या समझौते पर विधिवत मुहर लगी हुई मानी जाएगी।

(घ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अध्याय 12 या अध्याय XXXVI के अंतर्गत कार्यवाही के अलावा, इसमें निहित कुछ भी आपराधिक न्यायालय में किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में किसी भी दस्तावेज के प्रवेश को नहीं रोकेगा।

(ङ) इसमें निहित कुछ भी किसी भी न्यायालय में किसी भी दस्तावेज के प्रवेश को नहीं रोकेगा जब ऐसा दस्तावेज सरकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया है या जहां यह धारा 32 या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान द्वारा प्रदान किए गए कलेक्टर के प्रमाण पत्र को धारण करता है। 39 धारा 35 के परंतुक का खंड (क)

39 धारा 35 के परंतुक के अधीन।

1117

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1118 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

यह निर्धारित करता है कि प्रावधान में निहित बाधा को शुल्क और जुर्माने (यदि कोई हो) के भुगतान पर हटा दिया जाता है। पक्ष या पक्ष उस व्यक्ति को प्रभार्य कर्तव्य का भुगतान कर सकते हैं जिसके पास विधि द्वारा या पक्षों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 35 महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह यह सुनिश्चित करके कि किसी समझौते से उत्पन्न अधिकारों और दायित्वों को लागू करने से पहले स्टाम्प-शुल्क का भुगतान किया जाता है, स्टाम्प अधिनियम को बल देता है।

40. धारा 38 (1) इंगित करती है कि जिस उपकरण को जब्त किया गया है, उससे कैसे निपटा जाए:

“38. उपकरणों को जब्त कर लिया गया कि कैसे निपटा जाता है।—

(1) जहां धारा 33 के अंतर्गत किसी लिखत को जब्त करने वाले व्यक्ति को विधि द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है और वह धारा 35 द्वारा प्रदान किए गए जुर्माने या धारा 37 द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्य के भुगतान पर साक्ष्य में ऐसे लिखत को स्वीकार करता है, तो वह कलेक्टर को लिखित में एक प्रमाण पत्र के साथ ऐसे लिखत की एक प्रमाणित प्रति भेजेगा, जिसमें उसके संबंध में लगाए गए शुल्क और जुर्माने की राशि का उल्लेख होगा और ऐसी राशि कलेक्टर या ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जिसे वह इस संबंध में नियुक्त करे।

(2) प्रत्येक अन्य मामले में, इस तरह से एक उपकरण को जब्त करने वाला व्यक्ति इसे मूल रूप से कलेक्टर को भेजेगा। ”

41. कलेक्टर को धारा 33 के अंतर्गत किसी उपकरण को जब्त करने की शक्ति प्रदान की जाती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण किसी दस्तावेज को जब्त करता है, तो इसे धारा 38 के खंड (2) के अंतर्गत कलेक्टर को भेजा जाना चाहिए। एक बार जब कलेक्टर को कोई लिखत प्राप्त हो जाती है, तो उसके पास धारा 40 के अंतर्गत उस पर मुहर लगाने की शक्ति होती है, यदि यह विनिमय पत्र, वचन पत्र या एक ऐसा लिखत नहीं है जो दस पैसे से अधिक शुल्क के साथ प्रभार्य है। कलेक्टर कर सकता है: क. समर्थन द्वारा प्रमाणित करें कि उपकरण पर विधिवत मुहर लगी है, यदि वे ऐसी राय रखते हैं;

ख. समर्थन द्वारा प्रमाणित करें कि लिखत शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं है, यदि वे ऐसी राय रखते हैं; और

40 धारा 40 (1) (ए), स्टाम्प अधिनियम 41

/

[2023] 15 एस सी आर।

ग. उचित शुल्क के भुगतान या उचित शुल्क की पूर्ति के लिए आवश्यक राशि की आवश्यकता है, यदि उनकी राय है कि उपकरण शुल्क के साथ प्रभार्य है और विधिवत मुहर नहीं है।⁴² कलेक्टर धारा 40 द्वारा दिए गए प्रावधान के अनुसार जुर्माना भी लगा सकता है। यदि लिखत को धारा 38 के अंतर्गत कलेक्टर को भेजा गया है, तो इसे ऊपर वर्णित तरीके से निपटाने के बाद जब्त करने वाले अधिकारी को वापस कर दिया जाना चाहिए।⁴³

42. मुद्रांक अधिनियम की धारा 42 के संदर्भ में, शुल्क का भुगतान और जुर्माना (यदि कोई हो) पूरा होने के बाद एक दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार्य है। यह निर्धारित करता है कि या तो

साक्ष्य में दस्तावेज़ को स्वीकार करने वाला व्यक्ति या कलेक्टर, जैसा भी मामला हो, समर्थन द्वारा प्रमाणित करेगा कि उचित शुल्क का भुगतान किया गया है।

43. मुद्रांक अधिनियम द्वारा विचार की गई प्रक्रिया राजस्व संग्रह की सुविधा प्रदान करती है। यह न केवल सार्वजनिक कार्यालय के प्रभारी व्यक्तियों या जिन्हें विधि द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है, बल्कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, जिसे पक्षों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है, उपकरणों को ज़ब्त करने की अनुमति देता है। इसके बाद क़ानून किसी दस्तावेज़ को ज़ब्त करने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाए। अनुसूची I में उचित विवरण के अंतर्गत उचित राशि के भुगतान और जुर्माना (यदि कोई हो) के बाद, स्टाम्प अधिनियम उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा समर्थन द्वारा इस तरह के भुगतान के प्रमाणन का प्रावधान करता है। एक बार जब किसी उपकरण का समर्थन कर दिया जाता है, तो उसे साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है, पंजीकृत किया जा सकता है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है या प्रमाणित किया जा सकता है जैसे कि उस पर विधिवत मुहर लगाई गई हो।

बी। अस्वीकृति और शून्यता के बीच का अंतर

44. साक्ष्य में किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता विधि में इसकी वैधता या प्रवर्तनीयता से अलग है। अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (जी) में प्रावधान है कि एक समझौता जो विधि द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, उसे अमान्य कहा जाता है। दूसरी ओर, किसी विशेष दस्तावेज़ या मौखिक गवाही की स्वीकार्यता इस बात को संदर्भित करती है कि इसे साक्ष्य में पेश किया जा सकता है या नहीं। पी. रामनाथ अय्यर की द विधि लेक्सिकन इस प्रकार 'स्वीकार्य' है:

42 धारा 40 (1) (बी), स्टाम्प अधिनियम 43 धारा 40 (3), स्टाम्प अधिनियम 1119

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1120 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच मध्यस्थता

“स्वीकार्य है।

प्राप्त करने के लिए उचित, सक्षम और भर्ती होने के योग्य। जैसा कि साक्ष्य पर लागू होता है, इस शब्द का अर्थ है कि यह ऐसी प्रकृति का है कि न्यायालय या न्यायाधीश इसे प्राप्त करने के लिए बाध्य है, यानी इसे साक्ष्य में पेश करने की अनुमति दें।

कई कानूनों में दस्तावेज़ों की स्वीकार्यता पर नियम हैं, जिनमें से एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 45 है।

45. एक समझौता अपनी प्रकृति के बिना एक अमान्य समझौते के रूप में अमान्य हो सकता है जिसका प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि इसे साक्ष्य में पेश किया जा सकता है या नहीं। इसी तरह, एक समझौता वैध हो सकता है लेकिन साक्ष्य में अस्वीकार्य हो सकता है। उदाहरण के लिए, ए और बी एक समझौता कर सकते हैं जिसके द्वारा बी को किसी विशेष

व्यापार को करने से रोका जाता है। यह समझौता अनुबंध अधिनियम 46 की धारा 27 के अंतर्गत अमान्य होगा, लेकिन यह सबूत में इसकी स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करता है यदि बी के खिलाफ इसे लागू करने का प्रयास किया जाता है तो न्यायालय पक्षों के बीच समझौते को लागू नहीं करेगी क्योंकि यह अमान्य है लेकिन समझौता फिर भी सबूत में स्वीकार्य है।

46. जब कोई समझौता अमान्य होता है, तो हम विधि में इसकी प्रवर्तनीयता की बात कर रहे होते हैं। जब यह अस्वीकार्य होता है, तो हम इस बात का उल्लेख कर रहे होते हैं कि क्या न्यायालय मामले का निर्णय लेते समय इस पर विचार कर सकती है या उस पर भरोसा कर सकती है। यही शून्यता और स्वीकार्यता के बीच के अंतर का सार है।

ग. स्टाम्प अधिनियम की धारा **35** किसी दस्तावेज़ को अस्वीकार्य और अमान्य नहीं बनाती है।

47. एन एन ग्लोबल 2 (ऊपर) में बहुमत के निर्णय ने निम्नलिखित शब्दों में अपनी धारणा का सारांश दिया:

44 पी. रामनाथ अय्यर, द विधि लेक्सिकन (दूसरा संस्करण, 1997) 45 "साक्ष्य अधिनियम"

46 "27. व्यापार के प्रतिबंध में समझौता अमान्य है।— प्रत्येक समझौता जिसके द्वारा किसी को भी किसी भी प्रकार के वैध पेशे, व्यापार या व्यवसाय का प्रयोग करने से रोका जाता है, उस हद तक अमान्य है।

अपवाद 1.— ऐसे व्यवसाय को न चलाने के लिए समझौते की बचत, जिसकी साख बेची जाती है।— जो व्यक्ति किसी व्यवसाय की सद्भावना बेचता है, वह खरीदार से सहमत हो सकता है कि वह निर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर इसी तरह का व्यवसाय करने से बचें, जब तक कि खरीदार या उससे सद्भावना का अधिकार प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति उसमें इसी तरह का व्यवसाय करता है: बशर्ते कि व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसी सीमाएं न्यायालय को उचित लगती हैं। "

/

[2023] 15 एस सी आर।

"109. ... एक समझौता जिस पर बिना मोहर लगी हो या जिस पर बिना ज्ञान के मुहर लगी हो, तब तक लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि यह उक्त स्थिति में रहता है। इस तरह का एक साधन अमान्य होगा क्योंकि यह लागू करने योग्य नहीं है [अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (जी देखें)]। "

उपरोक्त अवलोकन प्रवर्तनीयता और स्वीकार्यता के बीच के अंतर को दर्शाता है।

48. मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 स्पष्ट है। इसमें कहा गया है, "नहीं।

कर्तव्य के साथ प्रभार्य लिखत को साक्ष्य में स्वीकार किया जाएगा। "

“साक्ष्य में स्वीकार किया जाना "उपकरण की स्वीकार्यता को संदर्भित करता है। धारा 42 की उप-धारा (2) में भी कहा गया है कि एक दस्तावेज जिसके संबंध में स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाता है और जिसका समर्थन किया जाता है, वह "साक्ष्य में स्वीकार्य" होगा।" शुल्क का भुगतान नहीं करने या अपर्याप्त राशि का भुगतान करने का प्रभाव किसी साधन को अस्वीकार्य और अमान्य नहीं बनाता है। गैर-मुद्रांकन या अनुचित मुद्रांकन के परिणामस्वरूप उपकरण अमान्य नहीं हो जाता है। डाक टिकट अधिनियम इस तरह के उपकरण को अमान्य नहीं करता है। स्टाम्प शुल्क का भुगतान न करने को ठीक किए जा सकने वाले दोष के रूप में सटीक रूप से वर्णित किया जाता है। डाक टिकट अधिनियम स्वयं उस तरीके का प्रावधान करता है जिसमें दोष को ठीक किया जा सकता है और इसके लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह उल्लेख करने योग्य है कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा एक अमान्य समझौते को "ठीक" किया जा सके।

49. तिरुवेंगडम पिल्लई बनाम नवनीथमल, 47 में इस न्यायालय ने उल्लेख किया

कि निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कुछ अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए एक समझौते की प्रामाणिकता पर संदेह किया था क्योंकि यह अलग-अलग तिथियों पर खरीदे गए दो स्टाम्प पेपरों पर लिखा गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह अपने आप में समझौते को अमान्य नहीं करेगा। इसने समझौते की कानूनी वैधता और इसकी स्वीकार्यता के बीच अंतर को देखा:

“13. मुद्रांक अधिनियम राज्य के लिए राजस्व सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक व्यापक अधिनियम है। किसी भी नियम के अभाव में एक ही दिन खरीदे गए क्रमिक रूप से क्रमांकित स्टाम्प पेपर की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग एक ऐसे उपकरण के लिए किया जाता है जिसका पंजीकरण करने का इरादा नहीं है, एक दस्तावेज़

इसे केवल इसलिए अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग तिथियों पर खरीदे गए दो स्टाम्प पेपरों पर लिखा गया है। यह मानते हुए भी कि इस तरह के स्टाम्प पेपर का उपयोग एक अनियमितता है,

47 (2008) 4 एससीसी 530 1121

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1122 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

न्यायालय केवल दस्तावेज़ पर ठीक से मुहर नहीं लगा सकता है, लेकिन केवल उस आधार पर दस्तावेज़ को अमान्य नहीं ठहरा सकता है। भले ही किसी समझौते को आवश्यक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित नहीं किया जाता है, यह स्टाम्प अधिनियम, **1899** की धारा **35** या **37** के अंतर्गत शुल्क और जुर्माने के भुगतान पर साक्ष्य में स्वीकार्य है। यदि कोई समझौता किया जाता है

एक सादे कागज पर शुल्क और जुर्माना देकर साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि दो स्टाम्प पेपरों पर निष्पादित एक समझौते को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यह मानते हुए भी कि वे दोषपूर्ण थे

शुल्क और जुर्माने के भुगतान पर। लेकिन साक्ष्य में किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता और ऐसे दस्तावेज़ की वास्तविकता का प्रमाण अलग-अलग मुद्दे हैं। "

(जोर दिया गया) 50। यह लंबे समय से भारत में विधि की स्थिति रही है

स्टाम्प एक्ट। गुलजारी लाल मारवाड़ी बनाम राम गोपाल में, 48 दलों में से एक

उन्होंने तर्क दिया कि समझौता अमान्य था क्योंकि उस पर ठीक से मुहर नहीं लगी थी। धारा 35 का हिस्सा जो बिना मोहर वाले उपकरणों की स्वीकार्यता को रोकता है, तब वही था जो अब है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा:

“... धारा का प्रभाव इस तरह के एक अप्रकाशित दस्तावेज़ को साक्ष्य में अस्वीकार्य बनाना है, और सबूत प्राप्त करने का अधिकार रखने वाले व्यक्तियों या किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा उस पर कार्रवाई करने में असमर्थ है। यह दस्तावेज़ की वैधता को प्रभावित नहीं करता है।

दस्तावेज़ों की अयोग्यता और अस्वीकृति के बीच एक स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए। कुछ क़ानून और धाराएँ दस्तावेज़ों को अमान्य बना देती हैं यदि उन पर मुहर नहीं लगाई जाती है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की किसी भी धारा में ऐसा प्रभाव नहीं है।

उच्च न्यायालय ों ने बूटतम पिचिया बनाम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय सहित अन्य मामलों में भी विधि की स्थिति पर ध्यान दिया है।

बोयापति कोटेश्वर राव 49.

51. एन एन ग्लोबल 2 (ऊपर) में, इस न्यायालय ने माना कि मध्यस्थता समझौते पर मुहर लगाने में विफलता एक "उपचार योग्य दोष" नहीं है।" प्रावधानों पर निर्भर

48 1936 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 275 49 1964 एस. सी. सी. ऑनलाइन एपी 5

/

[2023] 15 एस सी आर।

अनुबंध अधिनियम के साथ-साथ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6-ए) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक अनस्टैम्ड मध्यस्थता समझौता अमान्य है। बहुमत के निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं:

“103. ... केवल एक अनस्टैम्ड मध्यस्थता समझौते को "इलाज योग्य दोष" के रूप में वर्णित करना उचित नहीं हो सकता है। जब तक यह एक अप्रकाशित साधन बना रहता है, तब तक इसे किसी भी उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, जैसा कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 में विचार किया गया है। यह अप्रवर्तनीय बना हुआ है।

... यह "कानून में लागू करने योग्य नहीं है"। उक्त अर्थ में, यह विधि में भी मौजूद नहीं हो सकता है। यह शून्य होगा। इस संबंध में हमारा विचार कि शून्यता को अप्रवर्तनीयता से जोड़ा जाता है, अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (जे) से पुष्टि प्राप्त करता है जो एक अनुबंध को प्रदान करता है जो लागू करने योग्य शून्य नहीं है। "

(मूल में जोर) 52। इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणी गलत है। अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (जे) निम्नलिखित प्रावधान करती है:

“(जे) एक अनुबंध जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाता है, वह अमान्य हो जाता है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाता है। ”

53. धारा 2 (जे) तब आकर्षित नहीं होती है जब किसी उपकरण को स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत अस्वीकार्य माना जाता है। उत्तरार्द्ध का प्रभाव एक अप्रकाशित समझौते को अप्रवर्तनीय नहीं बनाना है। यदि यह अप्रवर्तनीय था, तो इसका मतलब होगा कि यह शून्य था। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पिछले पैराग्राफ में एक बिना मुहर वाला या अपर्याप्त मुहर वाला समझौता क्यों अमान्य नहीं है। वास्तव में, अनुबंध अधिनियम के लिए एन एन ग्लोबल 2 (ऊपर) में बहुमत का दृष्टिकोण शुरुआत से ही अप्रमाणित समझौतों को अमान्य कर देगा और अमान्य नहीं होगा। 54. एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6 ए) पर भी भरोसा किया:

“104. धारा 11 (6-ए) जिस पर विचार करती है वह एक अनुबंध है और यह एक ऐसा समझौता नहीं है जिसे अनुबंध के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह धारा 11 (6-ए) में "मध्यस्थता समझौता" शब्दों के उपयोग के बावजूद है। दूसरे शब्दों में, अनुबंध अधिनियम की धारा 7 के अनुरूप होना चाहिए। होना ही चाहिए।

यह भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह अनुबंध अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(जोर दिया गया)

1123

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1124 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर. के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते।

55. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6-ए) 50 नीचे दी गई है:“(6-क) उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय, उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के

अंतर्गत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, किसी के अस्तित्व की जांच करने के लिए स्वीकार नहीं करेगा।

मध्यस्थता समझौता। "

(जोर दिया गया) 56। धारा 11 (6 ए) के एक सादे अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह एक मध्यस्थता समझौते का उल्लेख कर रहा है। धारा 11 (6 ए) में प्रावधान है कि अदालतों को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच के लिए खुद को आश्वस्त करना चाहिए। "कन्फिने" शब्द एक मध्यस्थ की नियुक्ति के चरण में अदालतों के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने के लिए विधायिका के इरादे को इंगित करता है।

57. विद्या द्रोल्या (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

“21. मध्यस्थता अधिनियम में "समझौता" शब्द की अवहेलना नहीं की गई है, हालांकि इसे अनुबंध अधिनियम, 1872 (संक्षेप में "अनुबंध अधिनियम") की धारा 10 में अनुबंध के लिए सक्षम पक्षों की निशुल्क सहमति से किए गए अनुबंधों के रूप में, एक वैध विचार के लिए और एक वैध उद्देश्य के साथ किया गया है, और इस प्रकार स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित नहीं किया जाता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 10 यह भी निर्धारित करती है कि उपरोक्त आवश्यकताएं भारत में लागू किसी भी विधि (और स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं) को लागू नहीं करेंगी, जिसके द्वारा गवाहों या दस्तावेजों के पंजीकरण से संबंधित किसी भी विधि की उपस्थिति में लिखित रूप में अनुबंध करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, एक मध्यस्थता समझौते को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 में निर्धारित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अधिदेश को पूरा करना चाहिए।

58. उपरोक्त टिप्पणियां सही हैं क्योंकि मध्यस्थता समझौते को अनुबंध अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। हालांकि, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत मध्यस्थता न्यायाधिकरण को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि क्या अनुबंध अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। निम्नलिखित खंडों में इसे अधिक विस्तार से संबोधित किया गया है।

50 2019 के अधिनियम 33 द्वारा लोप किया गया। इस चूक को अभी तक अधिसूचित/प्रभावी रूप से लिया जाना बाकी है।

iii. मुद्रांक अधिनियम का उद्देश्य

59. स्टाम्प एक्ट एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व बढ़ाना है। यह एक अनिवार्य कानून है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम. दिलीप कंस्ट्रक्शन कं., 51 इस न्यायालय ने स्टाम्प अधिनियम की धारा 35, 36 और 42 के आयात पर विचार किया। एक

पक्ष ने यह तर्क देने के लिए धारा 35 और 36 के बीच वाक्यांश में अंतर पर भरोसा किया कि एक उपकरण जिस पर वैज्ञानिक रूप से मुहर लगाई गई थी या जिस पर मुहर नहीं लगाई गई थी, उसे शुल्क और जुर्माने (यदि कोई हो) के भुगतान पर साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन एक बार स्वीकार किए जाने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यह तर्क दिया गया था कि धारा 35 दो मामलों में एक बाधा के रूप में काम करती है, अर्थात्, साक्ष्य में एक दस्तावेज का प्रवेश और साथ ही उस दस्तावेज पर कार्य करना। यह तर्क दिया गया कि धारा 35 के विपरीत, धारा 36 ने केवल एक मामले में प्रतिबंध को हटा दिया-साक्ष्य में दस्तावेज की स्वीकार्यता। इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि स्टाम्प अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि एक उपकरण को साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है और साथ ही उचित शुल्क का भुगतान करने और उपकरण का समर्थन करने के बाद उस पर कार्रवाई की जा सकती है:

“6. ... यह तर्क धारा 36 के वास्तविक महत्व की अनदेखी करता है। उस धारा द्वारा एक बार साक्ष्य में स्वीकार किए गए दस्तावेज पर उसी वाद या कार्यवाही के किसी भी चरण में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि उस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है। धारा 36 किसी लिखत के खिलाफ चुनौती को प्रतिबंधित नहीं करती है कि उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि उस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है, लेकिन उस कारण से किसी ऐसे लिखत के खिलाफ कोई रोक नहीं है जिस पर अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्टाम्प शुल्क और जुर्माने के भुगतान के बाद विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है। संदेह, यदि कोई हो, तो धारा 42 (2) की शर्तों द्वारा दूर किया जाता है, जो स्पष्ट रूप से अधिनियमित करता है कि धारा 42 (1) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा समर्थित प्रत्येक दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार्य होगा और उस पर इस तरह से कार्रवाई की जा सकती है जैसे कि उस पर विधिवत मुहर लगी हो। ”

(मूल में जोर) 60। इस तरह के निर्णय में, इस न्यायालय ने स्टाम्प अधिनियम के उद्देश्य और अदालतों द्वारा इसकी व्याख्या करने के तरीके के बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की:

51 (1969) 1 एससीसी 597 1125

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1126 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

“7. मुद्रांक अधिनियम कुछ वर्गों के साधनों पर राज्य के लिए राजस्व सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित एक व्यापक उपाय है: यह हथियार के लिए अधिनियमित नहीं है

अपने मामले को पूरा करने के लिए तकनीकीता के हथियार के साथ एक वादी

विरोधी। अधिनियम के कड़े प्रावधानों की कल्पना राजस्व के हित में की जाती है, एक बार जब वह उद्देश्य विधि के अनुसार सुरक्षित हो जाता है, तो साधन पर अपना दावा करने वाले

पक्ष को साधन में प्रारंभिक दोष के आधार पर पराजित नहीं किया जाएगा। उस दृष्टि से देखा जाए तो योजना स्पष्ट है। "

(जोर दिया गया) स्टाम्प अधिनियम एक ऐसा विधान है जो राजस्व के हित में अधिनियमित किया जाता है। कानून की व्याख्या उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

ई *। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम **1996**

61. मध्यस्थता वैकल्पिक विवाद समाधान की एक विधि है जहाँ पक्ष अपने विवादों को एक तटस्थ तीसरे पक्ष को संदर्भित करने के लिए सहमत होते हैं जिसे मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है। मध्यस्थता का उद्देश्य पक्षकारों के बीच उनके मूल दायित्वों के संबंध में उत्पन्न हुए विवादों का त्वरित, प्रभावी और बाध्यकारी समाधान प्रदान करना है। मध्यस्थता विधि का जोर संक्षेप में रेडफर्न और हंटर में निहित है: "यह त्वरित होना चाहिए जहाँ विधि

धीमा, सस्ता है जहाँ विधि महंगा है, सरल है जहाँ विधि तकनीकी है, संघर्ष को भड़काने के बजाय एक शांतिदूत है।" 52

62. मध्यस्थता अधिनियम के अधिनियमन से पहले, मध्यस्थता पर विधि मध्यस्थता अधिनियम 1940, 53 मध्यस्थता (प्रोटोकॉल और कन्वेंशन) अधिनियम 1937 और विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम 1961 में निहित था। 1978 में, भारत के विधि आयोग ने 1940 के अधिनियम में पर्याप्त संशोधन का सुझाव दिया ताकि इसे समकालीन विधि की और आर्थिक आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि 54 पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 1985 में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में उत्पन्न होने वाले विवादों के निष्पक्ष और प्रभावी निपटारे के लिए एक एकीकृत विधि की ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए आदर्श विधि को अपनाया।

* एड। ध्यान दें: भाग ई

52 रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (7 वां संस्करण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2023) 3.

53 "1940 ऐक्ट "

54 "अनौपचारिक "

/

[2023] 15 एस सी आर।

संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने सभी राज्यों से मध्यस्थता प्रक्रिया के विधि की एकरूपता और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता अभ्यास की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने की वांछनीयता को देखते हुए आदर्श विधि पर उचित विचार करने की सिफारिश की। 55

63. मध्यस्थता अधिनियम को "घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित विधि" को समेकित और संशोधित करने के साथ-साथ सुलह से संबंधित विधि और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों की अवहेलना करने के लिए भी अधिनियमित किया गया था।" इस प्रक्रिया में, मध्यस्थता अधिनियम ने 1940 अधिनियम, मध्यस्थता (प्रोटोकॉल और कन्वेंशन) अधिनियम 1937 और विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम 1961 को निरस्त कर दिया। इसने मॉडल विधि, न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनेवा कन्वेंशन के अनुरूप घरेलू के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता भी लाई। मध्यस्थता अधिनियम को चार भागों में विभाजित किया गया है: (i) भाग I भारत में होने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से संबंधित है; (ii) भाग II न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित है; (iii) भाग III सुलह से संबंधित है; और (iv) भाग IV में पूरक प्रावधान हैं। वर्तमान संदर्भ में, हम काफी हद तक मध्यस्थता अधिनियम के भाग I से संबंधित हैं। उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा निम्नलिखित खंड में की गई है जो वास्तव में मध्यस्थता अधिनियम के रूप में मध्यस्थता पर विधि को सक्रिय करते हैं। ये सिद्धांत मध्यस्थता अधिनियम की व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण सहायक के रूप में कार्य करते हैं।

i. मध्यस्थ स्वायत्तता

64. मध्ययुगीन इंग्लैंड में, व्यापारियों और व्यापारियों के बीच मध्यस्थता का सहारा लेना आम बात थी। सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के दौरान, मध्यस्थता द्वारा वाणिज्यिक विवादों के निपटारे को चांसरी और अदालतों दोनों द्वारा प्रोत्साहित किया गया था।⁵⁶ मध्यस्थता के व्यापक उपयोग के आलोक में, न्यायालय की मुकदमेबाजी में तेजी से गिरावट के साथ, अंग्रेजी न्यायालयों ने एक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना शुरू कर दिया।⁵⁷ न्यायिक

55 संयुक्त राष्ट्र की महासभा, 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि' पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर आदर्श विधि' 40/72 112 वां पूर्ण सत्र, 11 दिसंबर 1985।

56 हेनरी हॉर्विट्ज़ और जेम्स ओल्डहैम, 'जॉन लॉक, जॉन मैन्सफी एल्ड, और 18 वीं शताब्दी के दौरान मध्यस्थता' (1993) 36 (1) द हिस्टोरिकल जर्नल 137, 139.

57 अर्ल वोलावर, 'द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कमर्शियल आर्बिट्रेशन' (1934) 83 यूनिवर्सिटी ऑफ पेसिल्वेनिया विधि रिव्यू 132, 142.

1127

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1128 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

मध्यस्थता कार्यवाही के प्रति संदेह मुख्य रूप से दृष्टिकोण से उत्पन्न हुआ

न्यायाधीशों का कहना है कि "अधिकार क्षेत्र के भीतर होने वाली प्रत्येक गतिविधि राज्य के विधि और न्यायालय के दायरे में होनी चाहिए।" 58

65. जैसे-जैसे सीमा पार वाणिज्य और लेन-देन बढ़े, कंपनियों और व्यवसायों ने अपने वाणिज्यिक विवादों को हल करने के लिए अलग-अलग तरीके खोजे। राष्ट्रीय न्यायालयों की औपचारिकता, रीति-रिवाज और कानूनी परंपराएं अपने विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान प्राप्त करने के पक्षकारों के इरादे से भिन्न थीं। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में व्यापार और वाणिज्य के अंतर्राष्ट्रीयकरण ने मध्यस्थता के विनियमन और संस्थागतकरण की आवश्यकता पैदा कर दी। इस प्रक्रिया में, लंदन चैंबर ऑफ आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स जैसे मध्यस्थ संस्थानों के विकास के साथ मध्यस्थता को राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों से भी अलग कर दिया गया था। मध्यस्थता विधि की इस नई व्यवस्था ने राष्ट्रीय विधि की प्रणालियों की पेचीदगियों में फंसे बिना विवादों को हल करने के लिए पक्षों के आपसी इरादे और मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के अधिकार की अधिक मान्यता का मार्ग प्रशस्त किया। न्यूयॉर्क कन्वेंशन और UNCITRAL मॉडल लॉ जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों में इसकी सराहना की गई और इसे प्रतिबिंबित किया गया। तदनुसार, मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायिक गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करने के लिए राष्ट्रीय विधि में बदलाव किया गया। वाणिज्य और व्यावसायिक प्रभावशीलता की मांगों का अर्थ था कि राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा नियंत्रण पक्षों के इरादे और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार के अधीन हो गया।⁵⁹

66. मध्यस्थ स्वायत्तता का सिद्धांत मध्यस्थता विधि के निरंतर विकसित होने वाले क्षेत्र का एक अभिन्न तत्व है। मध्यस्थता स्वायत्तता का अर्थ है कि एक मध्यस्थता समझौते के पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण को उनके बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को तय करने का अधिकार देने के लिए अपनी संविदात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। मध्यस्थ स्वायत्तता का आधार पक्षों के "घरेलू जोखिम" से खुद को दूर रखने के सच्चे इरादे को प्रभावी बनाना है।

न्यायिक संकीर्णतावाद।" 60

58 जूलियन डी. एम. ल्यू, 'सपने को हासिल करना: स्वायत्त मध्यस्थता' (2006) 22 (2) मध्यस्थता अंतर्राष्ट्रीय, 183.

59 इबिद, 185 पर

60 रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (7 वां संस्करण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2023) 388

/

[2023] 15 एस सी आर।

67. न्यायिक गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत मध्यस्थता न्यायाधिकरणों की स्वायत्तता को दर्शाता है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस अर्थ में स्वायत्त हैं कि उनका गठन अपनी पसंद के तटस्थ और विशेषज्ञ प्राधिकरण के माध्यम से अपने विवादों को निपटाने के लिए पक्षों के आपसी इरादे को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय सहित अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय

देने के लिए एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण की क्षमता यह भी इंगित करती है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को राष्ट्रीय न्यायालयों से पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है।

68. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 में यह प्रावधान है कि अदालतों को सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा, सिवाय उन मुकदमों के जिनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है। अनुबंध अधिनियम की धारा 28 में कहा गया है कि ऐसे समझौते जो किसी पक्ष को किसी अनुबंध के लिए सामान्य कानूनी कार्यवाही के माध्यम से किसी भी अनुबंध के अंतर्गत या उसके संबंध में अपने अधिकारों को लागू करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हैं, अमान्य हैं। हालाँकि, यह प्रावधान स्पष्ट रूप से उन अनुबंधों को बचाता है जिनके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी विषय या विषयों के वर्ग के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए सहमत होते हैं। मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों को निपटाने का विकल्प चुनकर, पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पक्ष में राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष मुकदमा करने के अपने अधिकार को सौंप देते हैं। राष्ट्रीय न्यायालयों में मुकदमेबाजी करने के अपने अधिकार को समर्पण करके, पक्षकार अभियान, अनौपचारिकता और मध्यस्थता प्रक्रिया की प्रभावशीलता के पक्ष में राष्ट्रीय प्रक्रियात्मक कानूनों से बंधे होने के अपने अधिकार को भी समर्पण कर देते हैं। मध्यस्थ न्यायाधिकरण किसी देश के प्रक्रियात्मक कानूनों के अधीन नहीं है। उदाहरण के लिए, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 19 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से बाध्य नहीं होगा। इसके अलावा, यह निर्धारित करता है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण किसी भी तरीके से कार्यवाही का संचालन कर सकता है जिसे वह उचित समझता है यदि पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सहमत होने में विफल रहते हैं। यद्यपि माध्यस्थ न्यायाधिकरणों को प्रक्रियात्मक और मूल अर्थों में स्वायत्तता प्राप्त है, वे उस देश के विधि से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं जिसमें माध्यस्थ न्यायाधिकरण का अपना न्यायिक स्थान है, जैसा कि निम्नलिखित खंडों में चर्चा की गई है।

ii. न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप का सिद्धांत

69. मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायिक गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता दोनों के लिए मौलिक है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि मध्यस्थता की कार्यवाही पक्षों के समझौते के अनुसार या 1129 के निर्देश के अंतर्गत की जाती है।

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1130 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना न्यायाधिकरण।⁶¹ यह सिद्धांत मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करने का कार्य करता है, जो अपने विवादों को मध्यस्थता करने के लिए सहमत होने में पक्षों के उद्देश्य, कम औपचारिक और अधिक व्यावहारिक प्रक्रियाओं के लिए उनकी इच्छा और तटस्थ और विशेषज्ञ मध्यस्थता

प्रक्रियाओं के लिए उनकी इच्छा को कमजोर करेगा।⁶² मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायिक गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत मध्यस्थता प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए पक्षों की स्वायत्तता का सम्मान करता है। इस सिद्धांत को न्यूयॉर्क कन्वेंशन 63 और मॉडल विधि सहित अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों में भी शामिल किया गया है।

70. आदर्श विधि का अनुच्छेद 5 न्यायालय के विस्तार से संबंधित है।

हस्तक्षेप। इसमें कहा गया है कि "इस विधि द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, सिवाय इसके कि जहां इस विधि में ऐसा प्रावधान किया गया है।" आदर्श विधि के मसौदों ने इस लेख को शामिल करना महत्वपूर्ण समझा ताकि "पक्षकारों और मध्यस्थों को उन उदाहरणों के बारे में निश्चितता प्रदान की जा सके जिनमें न्यायालय पर्यवेक्षण करती है।

या सहायता की अपेक्षा की जानी थी।"⁶⁴ "इस विधि द्वारा शासित मामलों में" परिचयात्मक शब्दों को शामिल करके, प्रावधान का दायरा केवल उन मामलों तक सीमित था जो मॉडल विधि द्वारा शासित या विनियमित थे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी न्यायिक प्राधिकरण स्वयं को वह शक्ति प्रदान न करे जो स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रदान की गई है। उदाहरण के लिए, आदर्श विधि का अनुच्छेद 16 मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता से संबंधित आपत्तियों से निपटने सहित अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने की एक विशेष शक्ति प्रदान करता है।⁷¹ आदर्श विधि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के साथ-साथ मध्यस्थता प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों को विनियमित या नियंत्रित नहीं करता है।⁶⁵ इसी तरह, अनुच्छेद 5 राष्ट्रीय न्यायालयों को हस्तक्षेप करने से नहीं रोकता है।

61 गैरी बोर्न, द प्रिंसिपल ऑफ ज्यूडिशियल नॉन-इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स '(2009) 30 यूनिवर्सिटी ऑफ पेसिल्वेनिया जर्नल ऑफ इंटरनेशनल विधि 999,1002।

62 गैरी बोर्न, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन विधि एंड प्रैक्टिस (तीसरा संस्करण, 2021) 2361 63 अनुच्छेद II (3), न्यूयॉर्क कन्वेंशन

64 अपने सातवें सत्र के काम पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध प्रथाओं पर कार्य समूह की रिपोर्ट, ए/सी. एन. 9/246 (न्यूयॉर्क, 23 जनवरी-3 फरवरी 1984) 45.

65 मैनुअल ए गोमेज़, 'अनुच्छेद 5: अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर इलियास बेंटेकास (ई. डी. एस.) यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. मॉडल विधि में न्यायालय की हस्तक्षेप का विस्तार: एक टिप्पणी 89 (2020)

/

[2023] 15 एस सी आर।

ऐसे मामले जो आदर्श विधि द्वारा शासित नहीं हैं।⁶⁶ यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. कार्य समूह स्वयं कुछ ऐसी स्थितियों की पहचान करता है जिन पर आदर्श विधि के अंतर्गत विचार नहीं किया गया है जहां राष्ट्रीय अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं:

“उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 5 उन मामलों में अदालत के नियंत्रण या सहायता को बाहर नहीं करेगा जिन पर कार्य समूह ने विधि में विचार नहीं करने का निर्णय लिया था (उदाहरण के लिए, मध्यस्थता समझौते को समाप्त करने के लिए पक्षों की क्षमता; राज्य प्रतिरक्षा का प्रभाव; अनुबंधों को अनुकूलित करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की क्षमता; मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित संरक्षण के अंतरिम उपायों के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तन; शुल्क या लागत के लिए सुरक्षा सहित जमा के लिए शुल्क या अनुरोध का निर्धारण; पुरस्कारों को लागू करने के लिए समय-सीमा)। ”

72. यह इंगित करता है कि आदर्श विधि का अनुच्छेद 5 इस बात पर जोर देता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण विधि या निर्माण के मामलों के साथ-साथ अधिकार क्षेत्र और प्राधिकरण के दायरे से संबंधित सभी मुद्दों को निर्धारित करने का पहला उदाहरण है।⁶⁷ यह विशेष रूप से मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप के तरीके और रूप को निर्धारित करता है। राष्ट्रीय न्यायालय उन मामलों के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते हैं जो स्पष्ट रूप से आदर्श विधि द्वारा शासित नहीं हैं।⁶⁸

73. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 आदर्श विधि के अनुच्छेद 5 पर आधारित है। हालाँकि, धारा 5 में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे को निर्धारित करने वाला एक गैर-अस्थायी खंड भी शामिल है। वह इस प्रकार है:

“5. न्यायिक हस्तक्षेप का विस्तार।- किसी भी बात के बावजूद

मामलों में, उस समय लागू किसी अन्य विधि में निहित

इस भाग द्वारा शासित, कोई भी न्यायिक प्राधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेगा सिवाय इसके कि इस भाग में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। ”

आदर्श कानून के अनुच्छेद 5 के साथ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 की तुलना से दो पहलू स्पष्ट हो जाते हैं: पहले, धारा 5 अनुच्छेद 5 के विपरीत एक गैर-अस्थायी खंड के साथ शुरू होती है; और दूसरा, यह न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे को भाग I में “इस तरह से प्रदान की गई सीमा तक सीमित करती है।

66 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर आदर्श विधि पर मामला विधि का पाचन (2012) 21

67 रियो अलगाम बनाम सम्मी स्टील कंपनी, ओंटारियो न्यायालय ऑफ जस्टिस, कनाडा, 1 मार्च 1991, ओ. जे. संख्या 268

68 रिचर्ड गार्नेट, ‘मॉडल लॉ का अनुच्छेद 5: मध्यस्थ प्रक्रिया का संरक्षक?’ (2021) 38(2) जर्नल ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन 127-146।

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय हस्तक्षेप अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1132 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर. के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते।

74. मध्यस्थता अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों में से एक मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायालयों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करना है। पक्ष की स्वायत्तता और एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विवादों का निपटान मध्यस्थता विधि की विशेषताएँ हैं। धारा 5 पक्षकारों के सही इरादे को प्रभावी बनाती है कि वे मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करके त्वरित, प्रभावी और प्रभावी तरीके से मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों का समाधान करें।⁶⁹ संसद ने मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायालयों की पर्यवेक्षी भूमिका को न्यूनतम करने के लिए धारा 5 को अधिनियमित किया, और केवल मध्यस्थता अधिनियम के भाग I के अंतर्गत "इस तरह से प्रदान की गई" सीमा तक। ऐसा करने में, विधायिका ने मध्यस्थता कार्यवाही में अदालतों या न्यायिक अधिकारियों की भूमिका को पूरी तरह से बाहर नहीं किया, बल्कि इसे उन परिस्थितियों तक सीमित कर दिया जहाँ मध्यस्थता प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए न्यायिक अधिकारियों के समर्थन की आवश्यकता होती है।⁷⁰ मध्यस्थता अधिनियम में कुछ स्थितियों में विधि द्वारा आवश्यक होने पर आवश्यक सहायता और सहायता प्रदान करके "मध्यस्थता प्रक्रिया का समर्थन" करने के लिए अदालतों की भूमिका की परिकल्पना की गई है।

75. धारा 5 "किसी भी चीज के बावजूद" अभिव्यक्ति के साथ शुरू होती है।

उस समय लागू किसी अन्य विधि में निहित।" द नॉन-ऑबस्टैंट

खंड मॉडल विधि के अनुच्छेद 5 में संसद का जोड़ है। यह एक व्यापक आयाम का है और मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करने के विधायी इरादे को निर्धारित करता है। धारा 5 के संदर्भ में, इसका अर्थ है कि मध्यस्थता अधिनियम के भाग 1 में निहित प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू किसी भी अन्य विधि की परवाह किए बिना पूर्ण प्रभाव और संचालन दिया जाना चाहिए। अब यह विधि का एक स्थापित प्रस्ताव है कि विधायिका किसी भी अन्य विधि के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए गैर-अस्थाई खंडों का उपयोग करती है, जो गैर-अस्थाई खंड को शामिल करने वाले विधि के संचालन के रास्ते में खड़े होते हैं।⁷²

76. इस तरह के प्रावधान को विधि के अन्य प्रावधानों पर हावी करने के लिए एक गैर-अस्थाई खंड एक प्रावधान में जोड़ा गया है।⁷³ में।

69 भारतीय खाद्य निगम बनाम भारतीय मध्यस्थता परिषद (2003) 6 एस. सी. सी. 564

70 भारत संघ बनाम लोकप्रिय निर्माण कंपनी, (2001) 8 एस. सी. सी. 470; पी आनंद गजपति राजू बनाम पी. वी. जी. राजू, (2000) 4 एससीसी 539

71 स्विस् टाइमिंग लिमिटेड बनाम राष्ट्रमंडल खेल 2010 आयोजन समिति, (2014) 6 एससीसी 677

72 बिहार राज्य बनाम बिहार राज्य M.S.E.S.K.K. महासंघ, (2005) 9 एससीसी 129 73 पोत एम. वी. पोलारिस गैलेक्सी बनाम बैंक कैंटोनल डी जिनेवा, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1293 में रुचि रखने वाले मालिक और पक्ष

चंदावरकर सीता रत्न राव बनाम आशालता एस. गुरम, 74 न्यायमूर्ति सव्यसाची

मुखर्जी ने गैर-अस्थाई खंड के उद्देश्य को निम्नलिखित शब्दों में समझाया:

“67. "इस अधिनियम में या किसी अधिनियम में या किसी विशेष अधिनियम में या उस समय लागू किसी विधि में या किसी अनुबंध में किसी विशेष प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद" अभिव्यक्ति के साथ शुरू होने वाला एक खंड अधिक बार शुरुआत में किसी धारा के साथ जोड़ा नहीं जाता है, ताकि अधिनियम के प्रावधान या अबाधित खंड में उल्लिखित अनुबंध के मामले में धारा के अधिनियमन करने वाले हिस्से को अधिनियम के प्रावधान या अनुबंध पर एक अधिस्थापक प्रभाव दिया जा सके। यह कहने के बराबर है कि अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद या किसी भी अनुबंध या दस्तावेज़ के बावजूद जिसके बाद अधिनियम का उल्लेख किया गया है, उसका पूर्ण संचालन होगा या गैर-अवरोध खंड में अपनाए गए प्रावधान अधिनियम के संचालन के लिए एक बाधा नहीं होंगे। ”

77. यद्यपि एक गैर-अस्थाई खंड को पूरे जोश के साथ संचालित करने की अनुज्ञात जानी चाहिए, लेकिन इसका प्रभाव विधायिका द्वारा इच्छित सीमा तक सीमित है।

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम सिडको लेदर लिमिटेड, 75 इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ है।

अभिनिर्धारित किया कि एक गैर-अस्थाई खंड की व्याख्या इसे विधायी नीति से जोड़कर की जानी चाहिए। इस प्रकार, भले ही एक गैर-अस्थाई खंड का विस्तार व्यापक हो, इसके प्रभाव की सीमा को विधायी इरादे और विधायी नीति को ध्यान में रखते हुए मापा जाना चाहिए।⁷⁶ इस सुलझी हुई कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार के लिए जो मुद्दा उत्पन्न होता है, वह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 में निहित गैर-अस्थाई खंड का दायरा है।

78. मॉर्गन सिक्क्योरिटीज एंड क्रेडिट (पी) लिमिटेड बनाम मोदी रबर लिमिटेड, 77

दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों पर हावी होंगे। 78 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 में निहित गैर-अस्थाई खंड पर ध्यान देते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

गैर-अस्थाई खंड का "सीमित अनुप्रयोग है जिसका उद्देश्य न्यायिक सीमा तक है

74 (1986) 4 एससीसी 447 75 (2006) 10 एससीसी 452

76 जेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम अमरलाल बी. जुमानी, (2012) 3 एससीसी 255

77 (2006) 12 एससीसी 642 78 "एस. आई. सी. ए".

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1134

हस्तक्षेप।" यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एस. आई. सी. ए. पर मध्यस्थता अधिनियम प्रबल नहीं होगा क्योंकि एस. आई. सी. ए. अधिनियम "एक उच्च लक्ष्य प्राप्त करना" चाहता है।" दूसरे शब्दों में, गैर-अस्थायी खंड का दायरा न्यायिक अधिकारियों के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करने तक सीमित है, जब तक कि यह मध्यस्थता अधिनियम के भाग I के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है।

79. आदर्श विधि के अनुच्छेद 5 के समान, धारा 5 इस भाग द्वारा शासित मामलों में "अभिव्यक्ति का उपयोग करती है।" इस अभिव्यक्ति का उपयोग मध्यस्थता अधिनियम के भाग I द्वारा स्पष्ट रूप से शासित मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे को सीमित करता है। भाग I द्वारा शासित मामलों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं (i) धारा 8 जो न्यायिक अधिकारियों को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने का आदेश देती है जब प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता हो; (ii) धारा 9 जो अदालतों को मध्यस्थता समझौते के लिए किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर अंतरिम उपाय जारी करने की अनुमति देती है; (iii) धारा 11 जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ों को मध्यस्थता समझौते के लिए पक्षों द्वारा किए गए आवेदन पर मध्यस्थों की नियुक्ति करने का अधिकार देती है; (iv) धारा 27 जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण को साक्ष्य लेने में सहायता के लिए अदालत से अनुरोध करने की अनुमति देती है; और (v) धारा 34 जो अदालत को उसमें उल्लिखित सीमित आधारों के आधार पर मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने का अधिकार देती है।

80. धारा 5 के दो पहलू हैं-सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पक्ष मध्यस्थता अधिनियम के भाग I के अंतर्गत स्पष्ट रूप से अनुज्ञात या निपटाए गए मामलों में मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायिक अधिकारियों को निहित करता है। इस दृष्टिकोण का दूसरा पक्ष यह है कि न्यायिक अधिकारियों को उन स्थितियों में मध्यस्थता कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित किया गया है जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण को विशेष अधिकार क्षेत्र दिया गया है। यह धारा 5 का नकारात्मक पहलू है। गैर-अस्थायी खंड मध्यस्थता के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए मामलों के संबंध में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा को सीमित करता है।

एक्ट करें। 79 भावेन निर्माण बनाम सरदार सरोवर नर्मदा निगम

लिमिटेड, 80 इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि "गैर -

मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत विचार नहीं किए गए अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए, यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. मॉडल विधि और नियमों को अपनाने के लिए प्रस्तावना में दिए गए विधानमंडल के इरादे को बनाए रखने के लिए अवरोध खंड प्रदान किया गया है।

79 सिक्योर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गोदरेज एंड बॉयस एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड (2004) 3 एस. सी. सी. 447

80 (2022) 1 एससीसी 75

/

[2023] 15 एस सी आर।

81. मध्यस्थता अधिनियम के अधिनियमन के पीछे मुख्य उद्देश्यों में से एक मध्यस्थता प्रक्रिया में अदालतों की पर्यवेक्षी भूमिका को केवल विधायिका द्वारा निर्धारित परिस्थितियों तक सीमित करना था। उदाहरण के लिए, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण

मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय लेने सहित अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय ले सकता है।" ई. एफ. ई. सी. टी

धारा 16 के न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यह है कि न्यायिक अधिकारी मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यद्यपि धारा 8 और 11 न्यायालयों को मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने या मध्यस्थों की नियुक्ति करने की अनुमति देती है, धारा 5 न्यायालयों को मध्यस्थता समझौतों के अस्तित्व और वैधता से संबंधित ठोस आपत्तियों से निपटने से प्रतिबंधित करती है। धारा 8 या धारा 11 के स्तर पर एक रेफरल न्यायालय केवल प्रथम दृष्टया निर्धारण में प्रवेश कर सकती है। प्रथम दृष्टया निर्धारण का विधायी अधिदेश यह सुनिश्चित करता है कि रेफरल अदालतें मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को कुचल न दें।

82. धारा 5 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के अंतर्गत न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा की व्याख्या करने में सहायक है। धारा 5 में न्यायिक गैर-हस्तक्षेप का एक सामान्य नियम है। इसलिए, मध्यस्थता अधिनियम के प्रत्येक प्रावधान का अर्थ धारा 5 को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए ताकि न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप के विधायी इरादे को सही प्रभाव दिया जा सके।

iii. मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है

83. गिरनार ट्रेडर्स बनाम महाराष्ट्र राज्य, 81 क संविधान

इस न्यायालय की पीठ ने कहा कि एक स्व-निहित संहिता उस उद्देश्य के संबंध में एक पूर्ण विधान है जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया है। इस तरह की स्व-निहित संहिता उस विधि द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से निपटने के लिए एक पूर्ण तंत्र प्रदान करती है और अन्य विधानों पर इसकी निर्भरता या तो अनुपस्थित है या न्यूनतम है।

84. इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ, फ्यूस्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम. जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, 82 ने मध्यस्थता अधिनियम की प्रकृति को निम्नलिखित शब्दों में समझाया:

81 (2011) 3 एस. सी. सी. 82 (2011) 8 एस. सी. सी. 333 1135

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते 1136 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

“89. इस प्रकार, यह देखा जाना चाहिए कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 को अपनी स्थापना से लेकर 2004 तक (पी. एस. सतप्पन [(2004) 11 एस. सी. सी. 672] में) एक स्व-निहित संहिता माना गया था। अब, यदि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 को मध्यस्थता से संबंधित मामलों पर एक स्व-निहित संहिता माना गया था, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, जो इसे लाने के लिए मध्यस्थता से संबंधित विधि को समेकित करता है, संशोधन करता है और डिजाइन करता है, जितना संभव हो सके, अनसिट्रल मॉडल के अनुरूप होना चाहिए। एक बार जब यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-निहित संहिता और संपूर्ण है, तो न्यायमूर्ति तुलजापुरकर की स्पष्ट अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए यह भी अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि यह इसके साथ एक नकारात्मक महत्व रखता है कि केवल ऐसे कार्य जो अधिनियम में उल्लिखित हैं, किए जाने की अनुमति है और जिन कार्यों या चीजों का उसमें उल्लेख नहीं है, उन्हें करने की अनुमति नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक पत्र पेटेंट अपील को सामान्य सिद्धांतों में से एक के आवेदन द्वारा बाहर रखा जाएगा कि जहां विशेष अधिनियम एक स्व-निहित कोड निर्धारित करता है, तो सामान्य विधि प्रक्रिया की प्रयोज्यता को निहित रूप से बाहर रखा जाएगा। ”

85. मध्यस्थता अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ मध्यस्थों की नियुक्ति, मध्यस्थता की शुरुआत, निर्णय लेने और मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देने के साथ-साथ ऐसे निर्णयों के निष्पादन से संबंधित मामलों के संबंध में एक स्व-निहित संहिता है।⁸³ जब एक स्व-निहित संहिता एक प्रक्रिया निर्धारित करती है, तो एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया की प्रयोज्यता को निहित रूप से बाहर रखा जाएगा।⁸⁴ मध्यस्थता विधि पर एक स्व-निहित और विस्तृत संहिता होने के नाते, मध्यस्थता अधिनियम में यह अनिवार्यता है कि विधि के अंतर्गत जो अनुमत है वह केवल संकेतित तरीके से ही किया जाना चाहिए, न कि अन्यथा। तदनुसार, मध्यस्थता अधिनियम द्वारा शासित मामलों जैसे कि मध्यस्थता समझौता, मध्यस्थों की नियुक्ति और मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अपनी अधिकारिता पर निर्णय लेने की क्षमता का मूल्यांकन विधि के अंतर्गत निर्दिष्ट तरीके से किया जाना चाहिए। परिणाम यह है कि मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत जो उल्लेख नहीं है, उसे करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, अन्य कानूनों के प्रावधान मध्यस्थता अधिनियम के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

83 पासल विंड सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड बनाम जीई पावर कन्वर्जन (इंडिया) (पी) लिमिटेड, (2021) 7 एससीसी 1; कांडला एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम ओसीआई कॉर्पोरेशन, (2018) 14 एससीसी 715 84 सुबल पॉल बनाम मलिना पॉल, (2003) 10 एससीसी 361

iv. आधुनिक मध्यस्थता के सिद्धांत

86. डाक टिकट अधिनियम और भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1899 उसी दिन यानी 1 जुलाई 1899 को लागू हुए। मध्यस्थता अधिनियम, 1899, जिसे एक सदी से भी पहले अधिनियमित किया गया था, के घोषित उद्देश्य के रूप में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप नहीं था। हालांकि, एक सदी के दौरान मध्यस्थता पर विधि में भारी बदलाव आया है।

87. मध्यस्थता अधिनियम आधुनिक मध्यस्थता के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक तटस्थ तृतीय-पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा अपने विवादों को हल करने के लिए पक्षों के आपसी इरादे को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है, जिसका निर्णय सभी पक्षों के लिए अनिवार्य और बाध्यकारी है। मध्यस्थता विधि पक्षों को मध्यस्थता प्रक्रियाओं को तैयार करने की अनुमति देता है, जो मध्यस्थता प्रक्रिया की दक्षता और समीचीनता सुनिश्चित करता है। व्यावसायिक और वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा मध्यस्थता को पसंद करने का एक कारण यह है कि यह बोझिल न्यायिक प्रक्रियाओं को रोकता है, जो अक्सर महंगी, जटिल और अंतहीन साबित हो सकती हैं। अधिकांश कानूनी क्षेत्राधिकारों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मध्यस्थता का समर्थन करने वाले कानूनी दृष्टिकोणों को भी मान्यता दी है और अपनाया है। इस प्रक्रिया में, राष्ट्रीय न्यायालयों ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण की पृथक्करण क्षमता अनुमान और क्षेत्राधिकार क्षमता जैसे सिद्धांतों को प्रभावी बनाया है। आधुनिक मध्यस्थता विधि मध्यस्थता प्रक्रिया में राष्ट्रीय न्यायालयों की भूमिका को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन मध्यस्थता समझौतों से संबंधित विवादों और मुद्दों के साथ-साथ पक्षों के मूल अधिकारों पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण को प्राथमिकता देता है। मध्यस्थता अधिनियम आधुनिक मध्यस्थता विधि के इन पहलुओं को प्रतिबिंबित करता है। इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मध्यस्थता अधिनियम की व्याख्या इस तरह से करे जो भारत में आधुनिक मध्यस्थता के सिद्धांतों को जीवन प्रदान करे।

एफ *। मध्यस्थता समझौते पर विधि

88. एक मध्यस्थता समझौता मध्यस्थता की नींव है क्योंकि यह मध्यस्थता के लिए अपने विवादों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षों की सहमति को अभिलेख करता है।⁸⁵

बिहार राज्य खनिज विकास निगम बनाम एनकॉन बिल्डर्स, 86

इस न्यायालय ने मध्यस्थता समझौते के आवश्यक तत्वों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया:

* एड। ध्यान दें: पार्ट एफ

85 रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (7 वां संस्करण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2023) 49

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1138 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

ए। कुछ चिंतनशील संबंध के संबंध में वर्तमान या भविष्य का अंतर होना चाहिए;

बी। ऐसे विवादों को एक निजी न्यायाधिकरण द्वारा निपटाने का पक्षकारों का इरादा होना चाहिए;

ग. पक्षकारों को ऐसे न्यायाधिकरण के निर्णय से बाध्य होने के लिए लिखित रूप में सहमत होना चाहिए; और

घ. पक्षकारों को विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए।

89. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (बी) एक "मध्यस्थता समझौते" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ धारा 7 में निर्दिष्ट एक समझौता है। धारा 7 एक "मध्यस्थता समझौते" का अर्थ है पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता जो सभी या कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं या जो एक अवज्ञाकारी कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वह संविदात्मक हो या नहीं। यह प्रावधान करता है कि एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है। इसके अलावा, धारा 7 अनिवार्य करती है कि एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा। धारा 7 (4) के अनुसार, एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि यह निम्नलिखित में निहित है: (क) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़; (ख) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से संचार सहित पत्रों, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान-प्रदान जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करता है; या (ग) दावे और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान जिसमें समझौते के अस्तित्व का आरोप एक पक्ष द्वारा लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है। धारा 7 (5) में प्रावधान है कि मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के लिए एक अनुबंध में एक संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि उस मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाया जाए।

i. मध्यस्थता समझौते की पृथकता

90. अंतर्निहित अनुबंध से मध्यस्थता समझौते की पृथकता या पृथकता की अवधारणा एक कानूनी निर्णय है जो एक मध्यस्थता समझौते की अलग प्रकृति को स्वीकार करता है। मध्यस्थता समझौते की अंतर्निहित अनुबंध से अलग प्रकृति मध्यस्थता विधि की आधारशिलाओं में से एक है। जैसा कि रेडफर्न और हंटर बताते हैं, एक मध्यस्थता समझौता न्यायिक रूप से उस अंतर्निहित अनुबंध से स्वतंत्र है जिसमें यह निहित है।⁸⁷

/

[2023] 15 एस सी आर।

पृथक्करण की अवधारणा अंतर्निहित अनुबंध को अलग करने के लिए पक्षों के अनुमानित इरादे को दर्शाती है, जो एक मध्यस्थता समझौते से पक्षों के मूल अधिकारों और दायित्वों को पकड़ती है, जो अंतर्निहित अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए एक प्रक्रियात्मक ढांचा प्रदान करती है। इस धारणा के सिद्धांत और व्यवहार में विभिन्न परिणाम हैं, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक मध्यस्थता समझौता अंतर्निहित अनुबंध की अयोग्यता या समाप्ति से बच जाता है।

91. श्वबेल, सोबोटा और मेंटन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर एक पुस्तक में बताते हैं कि पृथक्ता अनुमान 88 चार कारकों पर आधारित है: पहला, अनुबंध की वैधता पर विवाद सहित अपने बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के मध्यस्थता की आवश्यकता के लिए पक्षों का इरादा; दूसरा, एक अनिच्छुक पक्ष को अंतर्निहित अनुबंध की अयोग्यता का आरोप लगाकर अपनी पिछली प्रतिबद्धता से बचने से रोकना; तीसरा, चूंकि मध्यस्थता समझौते और अंतर्निहित अनुबंध को दो अलग-अलग समझौतों के रूप में माना जाता है, इसलिए अंतर्निहित अनुबंध में औपचारिकताओं को पूरा करने में अपर्याप्तता के परिणामस्वरूप मध्यस्थता समझौते की अयोग्यता नहीं होगी; और चौथा, यदि पृथक्करण की धारणा को खारिज कर दिया जाता है, तो अदालतों को मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के बजाय विवादों के गुण-दोष पर निर्णय लेना होगा।

92. पृथक्करण की धारणा के लिए तर्क एक मध्यस्थता समझौते के लिए पक्षों की संविदात्मक स्वतंत्रता में निहित है जो अदालतों के बहिष्कार के लिए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही द्वारा अपने विवादों को निपटाने के लिए है। व्यावसायिक समझ और अपेक्षा के सामान्य सिद्धांत के अनुसार, पक्षकार अंतर्निहित अनुबंध के अंतर्गत मूल अधिकारों और दायित्वों पर अपने सभी विवादों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा हल करने का इरादा रखते हैं।⁸⁹ इसलिए, पृथक्करण की धारणा यह सुनिश्चित करती है कि एक मध्यस्थता समझौता पार्टियों के सच्चे इरादे को प्रभावी बनाने और मध्यस्थता कार्यवाही की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए एक अनुबंध की समाप्ति, अस्वीकृति या हताशा से बचता है।⁹³ स्विट्जरलैंड पृथक्करण की धारणा को मान्यता देने वाले पहले क्षेत्राधिकारों में से एक था।¹⁹³³ में स्विस् फेडरल ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए एक निर्णय में, यह देखा गया था कि "जहां मध्यस्थता खंड है मूल अनुबंध के रूप में उसी दस्तावेज़ में निहित है जिससे यह संबंधित है

88 स्टीफन श्वबेल, ल्यूक सोबोटा और रयान मेंटन, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता: तीन प्रमुख समस्याएं (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, दूसरा संस्करण, 2020) 4.

89 मुल्हेम पाइपकोटिंग्स जीएमबीएच बनाम वेलस्पन फिट्रेड लिमिटेड, 2013 एससीसी ऑनलाइन बम 1048 1139

इन आर्डर:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1140 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

और इसलिए बाहर से मुख्य समझौते के एक हिस्से के रूप में दिखाई देता है, यह अभी भी मुख्य समझौते के एक एकल प्रावधान का गठन नहीं करता है, बल्कि एक विशेष प्रकृति का एक स्वतंत्र समझौता है।” 90 हालांकि, गैरी बॉर्न अंक देते हैं

यद्यपि एक मध्यस्थता समझौते को अंतर्निहित अनुबंध से अलग किया जा सकता है, लेकिन यह कभी भी ऐसे अनुबंध से स्वतंत्र या स्वायत्त नहीं हो सकता है।⁹¹ यह काफी हद तक इस तथ्य के कारण है कि कुछ स्थितियों में, अंतर्निहित अनुबंध में दोष भी मध्यस्थता समझौते को अमान्य कर सकते हैं।⁹⁴ पृथक्करण की धारणा की रूपरेखा को ठीक से समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में इसकी उत्पत्ति और विकास को समझना आवश्यक है। इस तरह का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथक्करण की धारणा पर इस न्यायालय का कोई भी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की सहायता से होना चाहिए।

घ. यूनाइटेड किंगडम

95. हेमन बनाम डार्विन्स में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय के साथ शुरू होने वाले अंग्रेजी विधि में पृथक्ता की धारणा धीरे-धीरे विकसित हुई।⁹² हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या एक अंतर्निहित अनुबंध में निहित एक मध्यस्थता समझौता एक अस्वीकृत उल्लंघन के लिए इस तरह के अनुबंध की समाप्ति से बच सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक मध्यस्थता समझौता मूल अनुबंध के लिए संपार्श्विक है और इसकी समाप्ति से बच सकता है। लॉर्ड मैकमिलन ने कहा कि एक मध्यस्थता समझौता अन्य सामान्य अनुबंधों से भौतिक रूप से अलग है, इसका कारण यह है कि सामान्य अनुबंधों के अंतर्गत दायित्वों का उल्लंघन (सामान्य रूप से) विशिष्ट रूप से लागू नहीं किया जा सकता है और उनके उल्लंघन के परिणामस्वरूप केवल नुकसान होता है, लेकिन एक मध्यस्थता समझौते को मध्यस्थता अधिनियमों की मशीनरी द्वारा विशिष्ट रूप से लागू किया जा सकता है। लॉर्ड मैकमिलन ने निष्कर्ष निकाला कि किसी अनुबंध का खंडन या उल्लंघन मध्यस्थता समझौते को समाप्त नहीं करता है, क्योंकि यह उल्लंघन से उत्पन्न बकाया दावों को हल करने के उद्देश्य से जीवित रहता है:

“तदनुसार, मेरी राय है कि जिसे आम तौर पर अस्वीकार या अनुबंध का पूर्ण उल्लंघन कहा जाता है, चाहे वह दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया हो या नहीं, अनुबंध को निरस्त नहीं करता है, हालांकि यह हो सकता है

90 7 अक्टूबर 1933 का निर्णय, टोबलर बनाम जस्टिजकमिशन डेस कैन्टन्स श्विज़, डी. एफ. टी. 59। 177 (1933)

91 गैरी बॉर्न (संख्या 62) 377

92 [1942] एसी 356

/

[2023] 15 एस सी आर।

घायल पक्ष को उन दायित्वों को पूरा करने के कर्तव्य से मुक्त करें जो उसे अस्वीकार करने वाले पक्ष को किए गए अनुबंध द्वारा हैं। अनुबंध अस्तित्व से बाहर नहीं है, हालांकि प्रत्येक पक्ष द्वारा दूसरे के पक्ष में किए गए दायित्वों का आगे का सभी प्रदर्शन बंद हो सकता है। यह उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले दावों को मापने के उद्देश्य से जीवित रहता है, और मध्यस्थता खंड उनके निपटान के तरीके को निर्धारित करने के लिए जीवित रहता है। अनुबंध के उद्देश्य विफल हो गए हैं, लेकिन मध्यस्थता खंड अनुबंध के उद्देश्यों में से एक नहीं है। "96. बाद के फैसलों में, अंग्रेजी अदालतों ने दोहराया कि

पृथक्ता अनुमान। हार्बर एस्योरेंस कं. (यू. के.) लिमिटेड बनाम कांसा जनरल इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 93, अपील न्यायालय ने फैसला सुनाया

कि एक मध्यस्थता समझौता "के लिए एक स्व-निहित अनुबंध संपार्श्विक है

जिसमें अनुबंध शामिल है।" पृथक्करण की धारणा को यू. के. मध्यस्थता अधिनियम 1996 94 की धारा 7 में भी निम्नलिखित शब्दों में निहित किया गया है:

“जब तक पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, एक मध्यस्थता समझौता जो किसी अन्य समझौते (चाहे लिखित रूप में हो या न हो) का हिस्सा बनाता है या बनाने का इरादा रखता है, उसे अमान्य, अस्तित्वहीन या अप्रभावी नहीं माना जाएगा क्योंकि अन्य समझौता अमान्य है, या अस्तित्व में नहीं आया है या अप्रभावी हो गया है, और उस उद्देश्य के लिए इसे एक अलग समझौते के रूप में माना जाएगा। ”

97. चिट्ठी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स में कहा गया है कि यूके आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 7 स्थापित सामान्य विधि सिद्धांत को बनाए रखती है जो एक मध्यस्थता समझौते को उस अनुबंध से अलग मानती है जिसका वह हिस्सा है। 95 चिट्ठी के अनुसार, एक मध्यस्थता समझौते को अंतर्निहित अनुबंध से अलग और अलग मानने के दो परिणाम होते हैं: पहला, एक मध्यस्थता समझौता केवल उन आधारों पर अमान्य या अमान्य हो सकता है जो सीधे उससे संबंधित हैं; और दूसरा, यदि मध्यस्थता समझौता वैध और बाध्यकारी है और इसकी शर्तों में पर्याप्त रूप से व्यापक है, तो अंतर्निहित अनुबंध की वैधता, अस्तित्व या प्रभावशीलता से संबंधित मुद्दे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मूल अधिकार क्षेत्र में हैं। 96

93 [1993] प्र. 701

94 “यूकेजी मध्यस्थता अधिनियम ”

95 चिट्ठी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, ह्यूग बील (संस्करण), (32 वां संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल, 2015) पैरा 32-028

96 आई. बी. आई. डी. 1141

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते 1142 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

98. प्रीमियम नाफ्टा प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम फिली शिपिंग कंपनी लिमिटेड, 97

हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने आगे यू. के. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 में पृथक्ता अनुमान की व्याख्या की। उस मामले में, मुद्दा यह था कि क्या कोई पक्ष एक अंतर्निहित अनुबंध में निहित मध्यस्थता समझौते से बंधा था जो कथित रूप से धोखाधड़ी और रिश्वत द्वारा प्राप्त किया गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए लिखते हुए लॉर्ड हॉफ मैन ने माना कि इसे पृथक्करण की धारणा को देखते हुए लागू किया जा सकता है। विधि विधि ड ने माना कि यूके मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में एक मध्यस्थता समझौता अंतर्निहित अनुबंध से एक "अलग समझौता" है और इसलिए, केवल उन आधारों पर अमान्य या अमान्य हो सकता है जो सीधे मध्यस्थता समझौते से संबंधित हैं। लॉर्ड हॉफ मैन, हार्बर एस्योरेंस (ऊपर) में अपने पिछले निर्णय पर आधारित, यह मानते हुए कि धारा 7 किसी भी अप्रत्यक्ष चुनौती से मध्यस्थता समझौते की रक्षा करती है।

ई. संयुक्त राज्य अमेरिका

99. अमेरिकी संघीय मध्यस्थता अधिनियम यह मानता है कि एक मध्यस्थता समझौता अंतर्निहित अनुबंध से अलग और अलग हो सकता है। 98 पृथक्करण की धारणा को बाद में अमेरिकी अदालतों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थता दोनों के संबंध में दोहराया गया था। प्राइमा पेंट में

निगम बनाम फ्लड एंड कोंक्लिन एम. एफ. जी. कं., 99 का सर्वोच्च न्यायालय

संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह देखते हुए पृथक्करण की धारणा को खारिज कर दिया कि

“संघीय विधि के मामले के रूप में मध्यस्थता खंड उन अनुबंधों से 'अलग' हैं जिनमें वे अंतर्निहित हैं।” इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए,

न्यायालय ने मध्यस्थता समझौते को अंतर्निहित अनुबंध पर निर्देशित चुनौतियों से बचाने के लिए पक्षों की अनुमानित इच्छा पर जोर दिया। प्राइमा पेंट (उपरोक्त) में निर्धारित विधि की स्थिति को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बकये में दोहराया गया था।

कैशिंग इंक बनाम कार्डेग्रा 100 और रेंट-ए-सेंटर, वेस्ट, इंक।

जैक्सन। 101 किराया-ए-केंद्र (ऊपर) में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पृथक्करण नियम का अनुप्रयोग अनुबंध के शेष भाग के सार पर निर्भर नहीं करता है।

97 [2007] यूकेएचएल 40

98 गैरी बोर्न (संख्या 62) 382 99 388 यू. एस. 395 (1967)

100 546 अमेरिका 440,440 (2006) 101 2 561 अमेरिका 63 (2010)

च. सिंगापुर

100. सिंगापुर मध्यस्थता अधिनियम, 2001 की धारा 21 के माध्यम से सिंगापुर में घरेलू मध्यस्थता व्यवस्था के अंतर्गत पृथकता के सिद्धांत को वैधानिक रूप से मान्यता दी गई है।

102 प्रावधान यह है कि

मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है, उसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक समझौते के रूप में माना जाएगा।” पृथकता

बी. एन. ए. बनाम बी. एन. बी. में सिंगापुर उच्च न्यायालय द्वारा अनुमान को आगे समझाया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि "पक्षकार अपनी मध्यस्थता का इरादा रखते हैं

प्रभावी बने रहने के लिए समझौता यदि मूल अनुबंध का कोई प्रावधान जिसमें यह एकीकृत है, तथ्य या विधि की कुछ परिस्थितियों में, उनके मध्यस्थता समझौते को अमान्य करने के लिए काम कर सकता है।” 103 इस प्रकार, सिंगापुर उच्च

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पृथक्करण की धारणा का उद्देश्य एक मध्यस्थता समझौते को अवैधता से बचाना है जो मूल अनुबंध को चुनौती देने से उत्पन्न हो सकता है।

छ. अंतर्राष्ट्रीय समझौते

101. न्यूयॉर्क कन्वेंशन स्पष्ट रूप से पृथकता अनुमान के लिए प्रदान नहीं करता है। कन्वेंशन का अनुच्छेद II मध्यस्थता की अवहेलना करता है

एक अनुबंध या एक मध्यस्थता समझौते में एक मध्यस्थ खंड, पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित या पत्रों के आदान-प्रदान में निहित या

तार।” इसके अलावा, अनुच्छेद 5 (1) (ए) में प्रावधान है कि मध्यस्थता पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन को अस्वीकार किया जा सकता है जहां मध्यस्थता

समझौता "उस विधि के अंतर्गत मान्य नहीं है जिसके अधीन पक्षों ने इसे किया है या उस पर किसी भी संकेत में विफल रहने पर, उस देश के विधि के अंतर्गत जहां

पुरस्कार दिया गया।” यह प्रावधान इस आधार पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समझौतों को अंतर्निहित अनुबंध की तुलना में अलग-अलग राष्ट्रीय कानूनों और कानूनी नियमों के अधीन किया जा सकता है, और इसलिए, एक मध्यस्थता समझौता अनुमानित रूप से अंतर्निहित अनुबंध से अलग है। गैरी बोर्न के अनुसार, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद II और अनुच्छेद V (1) (a) से संकेत मिलता है कि कन्वेंशन एक मध्यस्थता समझौते को अंतर्निहित अनुबंध से अलग मानता है। 104

102 मध्यस्थता अधिनियम 2001 (2001 का संख्या 37) 103 [2019] एस. जी. एच. सी.

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते 1144 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

102. आदर्श विधि का अनुच्छेद 16 एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अपनी अधिकारिता पर शासन करने की क्षमता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 (1) प्रदान करता है: “मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय ले सकता है, जिसमें मध्यस्थता के अस्तित्व या वैधता के संबंध में कोई भी आपत्ति शामिल है।

समझौता। उस उद्देश्य के लिए, एक मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है, उसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक समझौते के रूप में माना जाएगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, न्यायिक रूप से मध्यस्थता खंड की अयोग्यता को लागू करेगा। ”

(जोर दिया गया)

103. UNCITRAL मध्यस्थता नियम, 2021 के नियम 23 में यह भी प्रावधान है कि “एक मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है, उसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र समझौते के रूप में माना जाएगा।” न्यूयॉर्क कन्वेंशन के विपरीत, मॉडल विधि स्पष्ट रूप से पृथक्करण की धारणा को मान्यता देता है।

104. UNCITRAL कार्य समूह के अनुसार, योग्यता-क्षमता के सिद्धांत के पूरक के लिए अनुच्छेद 16 (1) के अंतर्गत पृथक्करण की धारणा को शामिल किया गया है। पृथक्करण की धारणा आगे यह सुनिश्चित करती है कि अंतर्निहित अनुबंध की अयोग्यता पक्षकारों द्वारा अनुबंध की अकृतता या उसके अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किसी भी अन्य मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है, जब तक कि यह

यह भी माना जाता है कि जो दोष अनुबंध को रद्द करने का कारण बनता है, वह भी

स्वयं मध्यस्थता खंड।” 105 अनुच्छेद 16 (1) (ऊपर निकाला गया) का अंतिम वाक्य मध्यस्थता खंडों की संविदात्मक वैधता के सामान्य सिद्धांत को बताता है। 106 यह इंगित करता है कि अंतर्निहित अनुबंध की अयोग्यता आवश्यक रूप से अनुबंध में निहित मध्यस्थता समझौते की अयोग्यता को शामिल नहीं करेगी। तदनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता केवल तभी लागू की जाएगी जब अयोग्यता पैदा करने वाले दोष को मध्यस्थता समझौते में निर्देशित किया जाता है। 107

105 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर एक मॉडल विधि के मसौदा पाठ पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी, ए/सी. एन. 9/264 (25 मार्च 1985) 38.

106 गैरी बोर्न (संख्या 62) 403

107 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर आदर्श विधि पर मामला विधि का पाचन (2012) 76।

ज. भारत

105. मध्यस्थता अधिनियम में आदर्श विधि की तर्ज पर धारा 16 (1) में पृथक्करण की धारणा को भी शामिल किया गया है। धारा 16 (1) इस प्रकार है:

“16. मध्यस्थता न्यायाधिकरण की अपनी अधिकारिता पर निर्णय लेने की क्षमता-(1) मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपनी अधिकारिता पर निर्णय ले सकता है, जिसमें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय देना शामिल है, और उस उद्देश्य के लिए -

(क) एक मध्यस्थता समझौता जो एक अनुबंध का हिस्सा है, उसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र समझौते के रूप में माना जाएगा; और

(ख) मध्यस्थता न्यायाधिकरण का यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, न्यायिक रूप से मध्यस्थता खंड की अयोग्यता को लागू नहीं करेगा। "106. मॉडल विधि के अनुच्छेद 16 (1) के साथ-साथ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत शामिल पृथक्ता अनुमान, "उस उद्देश्य के लिए" अभिव्यक्ति द्वारा योग्य है।" एक सादे अध्ययन से यह सुझाव मिल सकता है कि धारा 16 ने केवल अधिकार क्षेत्र संबंधी विवादों पर क्षमता के आवंटन के विशेष उद्देश्य के लिए पृथक्करण की धारणा को शामिल किया है। हालाँकि, UNCITRAL मॉडल विधि पर केस विधि ज़ के डाइजेस्ट में कहा गया है कि

“ दूसरे वाक्य में उपयोग की गई भाषा पृथक्करण की धारणा के अनुप्रयोग को नहीं रोकती है जब एक क्षेत्राधिकार प्रश्न पहले उठाया जाता है।

एक न्यायालय ।” 108 गैरी बॉर्न सुझाव देते हैं कि बेहतर दृष्टिकोण यह है कि अनुच्छेद 16 (1) में निहित पृथक्करण की धारणा संविदात्मक के एक सामान्य नियम को बताती है।

वैधता "जो सभी उद्देश्यों के लिए लागू होती है।" 109 न्यायिक दृष्टिकोण है कि

भारतीय न्यायालयों से यह भी पता चलता है कि एक मध्यस्थता समझौते को मूल वैधता के सामान्य नियम के रूप में अंतर्निहित अनुबंध से अलग और अलग माना जाता है।

107. भारत में पृथक्ता की धारणा में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। प्रारंभ में, भारतीय अदालतों ने एक मध्यस्थता समझौते को अंतर्निहित अनुबंध के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था।

108 आइबीआईडी।

109 गैरी बॉर्न (संख्या 62) 403 1145

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते 1146 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

इस तरह का अनुबंध। उदाहरण के लिए, भारत संघ बनाम किशोरीलाल गुप्ता, 110 में

इस न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा था कि क्या मूल अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड बाद के अनुबंध के अधिनियमन के बाद बचा रहा। न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने हेमन (उपरोक्त) पर विचार किया, लेकिन इसे इस आधार पर अलग किया कि यह केवल अस्वीकृति से संबंधित है, जहां पक्षों के अधिकार और दायित्व अनुबंध की समाप्ति से बचते हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसी स्थितियों में जहां मूल अनुबंध को बाद के अनुबंध द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मूल अनुबंध में मध्यस्थता खंड भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने बहुमत की ओर से बोलते हुए कहा कि प्रथम, एक मध्यस्थता खंड एक अनुबंध की संपार्श्विक अवधि है जो इसकी मूल शर्तों से अलग है, लेकिन फिर भी यह इसका एक अभिन्न हिस्सा है; दूसरा, अंतर्निहित अनुबंध का अस्तित्व एक मध्यस्थता खंड के संचालन के लिए एक आवश्यक शर्त है; तीसरा, यदि अंतर्निहित अनुबंध इस अर्थ अंतर्गत गैर-अस्तित्व अंतर्गत था कि यह कभी भी कानूनी रूप से अस्तित्व अंतर्गत नहीं आया था या शुरू से ही शून्य था, तो मध्यस्थता खंड भी काम नहीं कर सकता था; चौथा, यदि पक्ष एक वैध रूप से निष्पादित अनुबंध को समाप्त करते हैं और इसे एक नए अनुबंध के साथ प्रतिस्थापित करते हैं, तो मूल अनुबंध का मध्यस्थता खंड भी इसके साथ नष्ट हो जाता है; और पांचवां, अस्वीकृति जैसी स्थितियों अंतर्गत।

108. दामोदर घाटी निगम बनाम के. के. कर, 111 में दो-न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने कहा कि यह याचिका कि एक अनुबंध अमान्य, अवैध या धोखाधड़ी है, मध्यस्थता खंड के साथ पूरे अनुबंध को प्रभावित करता है। हालाँकि, 1996 में मध्यस्थता अधिनियम के अधिनियमन ने भारतीय न्यायालयों को अधिक प्रोत्साहन के साथ पृथक्करण की धारणा को प्रभावी बनाने में सक्षम बनाया। धारा 16 (1) (बी), जो यह प्रावधान करती है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, न्यायिक रूप से मध्यस्थता खंड की अयोग्यता को लागू नहीं करेगा, किशोरीलाल गुप्ता (ऊपर) और दामोदर घाटी निगम (ऊपर) में निर्णयों को निरर्थक बनाता है। नतीजतन, भले ही अंतर्निहित अनुबंध को अमान्य घोषित किया जाता है, लेकिन यह न्यायिक रूप से मध्यस्थता समझौते की अयोग्यता में परिणाम नहीं देगा।

110 1959 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 6 111 (1974) 1 एस. सी. सी. 141

109. फर्म अशोक ट्रेडर्स बनाम गुरुमुख दास सलूजा, 112 में

इस न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा था कि क्या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत एक गैर-पंजीकृत आयोग के भागीदार द्वारा या फर्मों के रजिस्टर में भागीदार के रूप में नहीं दिखाए गए व्यक्ति द्वारा दायर एक आवेदन भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 69 (3) को देखते हुए बनाए रखने योग्य था। धारा 69 (3) एक अनुबंध से उत्पन्न अधिकार को लागू करने के लिए एक मुकदमे की संस्था के खिलाफ एक प्रतिबंध बनाता है जब तक कि

एफ. आई. आर. एम. पंजीकृत नहीं है और मुकदमा करने वाले व्यक्ति को फर्मों के रजिस्टर में भागीदार के रूप में दिखाया गया है या दिखाया गया है। इस न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की समग्र योजना पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि "मध्यस्थता खंड से अलग किया जा सकता है।

साझेदारी विलेख के अन्य खंड "और" अपने आप में एक समझौते का गठन करते हैं। "

110. राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति में।मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया

लिमिटेड वी.गेन ट्रेडिंग कं., 113 इस न्यायालय के समक्ष धारा 11 के अंतर्गत एक आवेदन में यह मुद्दा था कि क्या कोई मध्यस्थता खंड समाप्त हो जाता है यदि ऐसे खंड वाले अनुबंध को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसका नकारात्मक उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि भले ही अंतर्निहित अनुबंध समाप्त हो जाए, लेकिन इस तरह के अनुबंध में निहित मध्यस्थता समझौता पक्षों के बीच विवादों के समाधान के उद्देश्य से बना रहता है। इसी तरह, पी में

मनोहर रेड्डी और ब्रदर्स।बनाम महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम।, **114** इस न्यायालय ने बकये चेक कैशिंग इंक. (ऊपर) को संदर्भित किया

यह देखते हुए कि एक अंतर्निहित अनुबंध में निहित एक मध्यस्थता समझौता एक संपार्श्विक अवधि है जो अनुबंध की समाप्ति से बच सकता है।

111. मैग्मा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड बनाम पोटलुरी माधविलता, 115

इस न्यायालय ने मंजूरी के साथ हेमन (उपरोक्त) का हवाला देते हुए कहा कि अंतर्निहित अनुबंध की समाप्ति एक मध्यस्थता समझौते को निष्क्रिय नहीं करती है। यह भी देखा गया कि मध्यस्थता समझौता अंतर्निहित अनुबंध के "संबंध में", "संबंध में" या "तहत" उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के उद्देश्य से बना रहता है। मैग्मा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (उपरोक्त) में "के संबंध में", "के संबंध में" या "के तहत" अभिव्यक्तियों पर जोर देने से संकेत मिलता है कि मध्यस्थता समझौते का उद्देश्य किसी भी विवाद को निपटाने के लिए पक्षों के आपसी इरादे को मूर्त रूप देना है।

112 (2004) 3 एससीसी 155 113 (2007) 5 एससीसी 692 114 (2009) 2 एससीसी 494 115 (2009) 10 एससीसी 103 1147

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1148 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

अंतर्निहित अनुबंध के अंतर्गत मूल दायित्वों का सम्मान। इसलिए, यह एक तार्किक निष्कर्ष है कि पक्ष पारस्परिक रूप से एक मध्यस्थता समझौते को अंतर्निहित अनुबंध से अलग और अलग करने का इरादा रखते हैं, ताकि भले ही अंतर्निहित अनुबंध समाप्त हो जाए, मध्यस्थता

समझौता किसी भी बकाया विवाद को हल करने के लिए जीवित रहे जो अनुबंध के अंतर्गत मूल दायित्वों से उत्पन्न हो सकता है।

112. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस पहलू पर अपने निष्कर्ष तैयार करते हैं। पहला, धारा 16 में निहित पृथक्ता अनुमान न केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता निर्धारित करने के उद्देश्य से लागू होता है। यह एक मध्यस्थता समझौते की मूल स्वतंत्रता पर सामान्य नियम को समाहित करता है। दूसरा, एक मध्यस्थता समझौते के पक्ष पारस्परिक रूप से मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ उनके बीच मूल संविदात्मक विवादों के बारे में प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान करने का इरादा रखते हैं। अलगाव की धारणा एक अंतर्निहित अनुबंध में निहित एक मध्यस्थता समझौते की वैधता सुनिश्चित करके इसे प्रभावी बनाती है, इस तरह के अनुबंध की अयोग्यता, अवैधता या समाप्ति के बावजूद। तीसरा, जब पक्ष एक मध्यस्थता समझौते वाले अनुबंध में अपने हस्ताक्षर जोड़ते हैं, तो उन्हें प्रभावी रूप से स्वतंत्र रूप से मध्यस्थता समझौते में अपने हस्ताक्षर जोड़ने के रूप में माना जाता है। इसका कारण यह है कि पक्ष एक अंतर्निहित अनुबंध में निहित एक मध्यस्थता समझौते को अनुबंध की अन्य शर्तों से अलग मानने का इरादा रखते हैं; और चौथा, एक मध्यस्थता समझौते की वैधता, अंतर्निहित अनुबंध की अयोग्यता के सामने, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता का निर्धारण करके अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने की अनुमति देती है। इस प्रक्रिया में, पृथक्करण की धारणा योग्यता-क्षमता के सिद्धांत को प्रभावी बनाती है।

113. कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अब हम एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) में निर्णय की शुद्धता का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। संविधान पीठ ने पृथक्करण की धारणा को स्वीकार किया, लेकिन स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 और 35 के संदर्भ में इसे लागू करने से इनकार कर दिया। न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणी इस प्रकार है:

“157. [...] इस सिद्धांत का विकास कि मध्यस्थता अनुबंध से एक अलग और विशिष्ट समझौता है, यह इंगित करेगा कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 और 35 के अर्थ के भीतर, न्यायालय के कर्तव्य के संदर्भ में इसके अनुरूप कार्य करने में कोई भूमिका नहीं होगी। ”

/

[2023] 15 एस सी आर।

114. विधि की उपरोक्त स्थिति पृथक्करण की धारणा के विपरीत है जो एक मध्यस्थता समझौते को अंतर्निहित अनुबंध से अलग मानती है।

जी *। योग्यता-योग्यता का सिद्धांत

115. कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ (जिसे योग्यता-क्षमता के रूप में भी जाना जाता है) का सिद्धांत, जैसा कि मूल रूप से जर्मनी में विकसित किया गया था, पारंपरिक रूप से यह संकेत देने के लिए समझा जाता था कि मध्यस्थों को अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर एक अंतिम निर्णय देने का अधिकार है, जिसमें किसी भी न्यायालय द्वारा निर्णय की कोई बाद की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती है।¹¹¹⁶ हालांकि, कई क्षेत्राधिकार एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार पर निर्णय देने की अनुमति देते हैं, जो ठोस न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

117

116. यह सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि न्यायिक शक्तियों वाले विधि की प्राधिकरण को अपना अधिकार क्षेत्र तय करने का अधिकार है।¹¹¹⁸ इसी तरह, यह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता विधि का एक सामान्य नियम है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अपना अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने की शक्ति है। एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अपनी अधिकारिता निर्धारित करने की क्षमता मध्यस्थता न्यायशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह पृथक्करण की धारणा को प्रभावी बनाता है। पृथक्करण की धारणा मध्यस्थता समझौते को अंतर्निहित अनुबंध के दोषों से बचाती है, और इस तरह इस तरह के अनुबंध को समाप्त करने के बाद भी अंतर्निहित अनुबंध के अंतर्गत पक्षों के मूल अधिकारों और दायित्वों पर न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का निर्वाह सुनिश्चित करती है। योग्यता-क्षमता का सिद्धांत न्यायाधिकरण को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता सहित अंतर्निहित अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने की अनुमति देता है।

आई. तुलनात्मक विश्लेषण

117. सक्षमता-सक्षमता का सिद्धांत अब सभी प्रमुख क्षेत्राधिकारों का एक हिस्सा है। यू. के. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 30 में यह प्रावधान है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण निम्नलिखित के संबंध में अपने स्वयं के मूल अधिकार क्षेत्र पर निर्णय ले सकता है: पहले, क्या कोई वैध मध्यस्थता समझौता है; दूसरा, क्या

* एड। ध्यान दें: पार्ट जी

116 अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर फौचार्ड, गेलार्ड, गोल्डमैन (इमैनुएल गेलार्ड और जॉन सैवेज द्वारा संपादित, 1999) 396

117 गैरी बोर्न (संख्या 62) 1143

118 1 दिसंबर, 1926 के ग्रीक-तुर्की समझौते की व्याख्या, सलाहकार राय, श्रृंखला बी-संख्या 16 (28 अगस्त, 1928)।

1149

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1150 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

न्यायाधिकरण का उचित रूप से गठन किया गया है और तीसरा, मध्यस्थता समझौते के अनुसार मध्यस्थता के लिए क्या मामले प्रस्तुत किए गए हैं। एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता क्षमता का आधार फिली शिपिंग कंपनी में लॉर्ड हॉफ मैन के निम्नलिखित अवलोकन से स्पष्ट किया जा सकता है।

सीमित (ऊपर): “मेरी राय में मध्यस्थता खंड का निर्माण इस धारणा से शुरू होना चाहिए कि तर्कसंगत व्यवसायियों के रूप में पक्षों ने उस संबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का इरादा किया होगा जिसमें उन्होंने प्रवेश किया है या जिस संबंध में प्रवेश करने का इरादा है, उसी द्वारा तय किया जाना चाहिए।

न्यायाधिकरण।” दल्लाह रियल एस्टेट एंड टूरिज्म होलिंग कंपनी बनाम धार्मिक मामलों के मंत्रालय, पाकिस्तान सरकार, 119 में संयुक्त राज्य

राज्य सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में न्यायाधिकरण के अपने दृष्टिकोण का कोई कानूनी या प्रमाणिक मूल्य नहीं है जब मुद्दा न्यायाधिकरण द्वारा वैध अधिकार के प्रयोग से संबंधित है। इस प्रकार, यू. के. की स्थिति यह है कि हालांकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को इस बात पर विचार करने का अधिकार है कि क्या उसका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इसका निर्धारण अदालतों की जांच के अधीन है।

118. संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालतों ने योग्यता-क्षमता के सिद्धांत को पृथक्करण की धारणा के साथ जोड़ा है। प्राइमा पेंट (ऊपर) में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि इस आशय का दावा किया जाता है कि अंतर्निहित अनुबंध धोखाधड़ी से प्रेरित किया गया था, तो इस मुद्दे का निर्धारण अदालतों द्वारा किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अन्य सभी मुद्दों को निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए

मध्यस्थता न्यायाधिकरण “न केवल कानून के स्पष्ट अर्थ का सम्मान करता है, बल्कि कांग्रेस के स्पष्ट रूप से स्पष्ट उद्देश्य का भी सम्मान करता है कि मध्यस्थता प्रक्रिया, जब किसी अनुबंध के लिए पक्षों द्वारा चुनी जाती है, तो त्वरित हो, और अदालतों में देरी और बाधा के अधीन नहीं हो।” बकये चेक कैशिंग में

(ऊपर), संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए प्राइमा पेंट (ऊपर) को दोहराया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पहली बार में अंतर्निहित अनुबंध की वैधता के मुद्दे पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार, अमेरिका में स्थिति यह है कि अदालतों को केवल यह जांचना चाहिए कि क्या मध्यस्थता समझौते में कोई अयोग्यता निर्देशित की गई है, और अंतर्निहित अनुबंध की वैधता सहित अन्य सभी मुद्दों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए।

119. सिंगापुर के विधि अंतर्गत मध्यस्थता अधिनियम, 2001 के अनुच्छेद 21 (1) में अब तक के घरेलू मामलों में योग्यता-क्षमता के सिद्धांत को शामिल किया गया है।

/

[2023] 15 एस सी आर।

मध्यस्थता का संबंध है। यह प्रावधान करता है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय ले सकता है, जिसमें एक याचिका भी शामिल है कि उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और मध्यस्थता कार्यवाही के किसी भी चरण में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता पर कोई आपत्ति नहीं है। सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का संचालन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिनियम, 1994 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 120 आई. आई. ए. की धारा 3 में कहा गया है कि आदर्श विधि में विधि का बल है।

सिंगापुर में। मालिनी वेंचुरा बनाम नाइट कैपिटल पीटीई लिमिटेड, 121 में निर्गम

सिंगापुर उच्च न्यायालय के समक्ष यह था कि क्या मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के संदर्भ में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को निर्धारित करने की प्रधानता है। न्यायालय ने आदर्श विधि के अनुच्छेद 16 (1) के दायरे और उद्देश्य का विश्लेषण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं, यह निर्धारित करने में मध्यस्थता न्यायाधिकरण की पहली प्राथमिकता है और न्यायालय का विचार इस मुद्दे की न्यायाधिकरण की अपनी जांच के बाद आना चाहिए। यह आगे देखा गया कि "के संबंध में न्यायाधिकरण की शक्तियाँ

मुद्दा व्यापक है क्योंकि यह न केवल वैधता पर विचार कर सकता है बल्कि मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व पर भी विचार कर सकता है।" इस प्रकार, सिंगापुर उच्च न्यायालय

सक्षमता-सक्षमता के सिद्धांत को पूर्ण प्रभाव दिया है क्योंकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के संबंध में भी मुद्दों को निर्धारित करने के लिए पहली प्राथमिकता मिलती है, जबकि अदालतों का अधिकार क्षेत्र प्रथम दृष्टया निर्धारण तक सीमित है।

ii. भारत

120. भारत में पिछली मध्यस्थता व्यवस्था, यानी 1940 के अधिनियम अंतर्गत मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता को निर्धारित करने का मुद्दा विशेष रूप से अदालतों के अधिकार क्षेत्र में था। उस प्रभाव के लिए, 1940 के अधिनियम की धारा 33 ने मध्यस्थता समझौते के किसी भी पक्ष को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता को चुनौती देने वाले न्यायालयों के समक्ष आवेदन करने की अनुज्ञात। इसे ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के बारे में प्रश्न का निर्णय केवल अदालतों में आवेदन द्वारा किया जाना था, न कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा। 122 यह स्थिति अब वर्तमान में पूरी तरह से रूपांतरित हो गई है।

120 “आई. आई. ए ”

121 [2015] एसजीएचसी 225

122 धनराजमल गोबिंदराम बनाम शामजी कालिदास एंड कंपनी, **1961** एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. **28**; खरदाह कंपनी लिमिटेड बनाम.रेमन एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, **1962** एससीसी ऑनलाइन एससी **28**.

1151

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1152 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

कानून।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16, जो आदर्श विधि के अनुच्छेद 16 पर आधारित है, भारतीय मध्यस्थता विधि में योग्यता-क्षमता के सिद्धांत को मान्यता देती है। धारा 16 माध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय लेने सहित अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने का अधिकार देती है। महत्वपूर्ण रूप से, पक्षों को धारा 16 (2) और 16 (3) के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या अयोग्यता जैसे आधारों पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने का अधिकार है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में चुनौती पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है, और जहां वह चुनौती को अस्वीकार करता है, वह मध्यस्थता कार्यवाही के साथ आगे बढ़ सकता है और एक मध्यस्थता पुरस्कार दे सकता है। यह प्रक्रियात्मक क्षमता-क्षमता का सिद्धांत है जो अपने अधिकार क्षेत्र की चुनौतियों को सुनने और निर्णय लेने के लिए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की शक्ति को मान्यता देता है। एक बार जब मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक मध्यस्थ निर्णय देता है, तो धारा 16 (6) पीड़ित पक्ष को धारा 34 के अंतर्गत निर्णय अपास्त करते हुए करने के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। धारा 16 (5) और 16 (6) आगे दर्शाती हैं कि संसद ने मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान हस्तक्षेप करने के लिए अदालतों के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है-न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद ही अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। इस प्रकार, धारा 16 का उद्देश्य क्षमता-क्षमता के सिद्धांत के प्रक्रियात्मक और मूल पहलुओं को पूरा प्रभाव देना है।

121. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 मध्यस्थता पुरस्कारों अपास्त करते हुए करने के लिए आवेदनों से संबंधित है। धारा 34 (2) में प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा एक मध्यस्थता पुरस्कार को केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब आवेदन करने वाला पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड के आधार पर निम्नलिखित में से कोई भी आधार स्थापित करता है:

((i) कोई दल किसी असमर्थता अंतर्गत था; या

((ii) मध्यस्थता समझौता उस विधि के अंतर्गत मान्य नहीं है जिसके अधीन पक्षों ने इसे किया है या उस पर कोई संकेत देने में विफल रहने पर, उस समय लागू विधि के अंतर्गत ; या

((iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह अपना मामला पेश करने में असमर्थ था; या

((iv) मध्यस्थता पुरस्कार एक ऐसे विवाद से संबंधित है जिस पर मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर विचार नहीं किया गया है या विफल नहीं हुआ है, या इसमें प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल हैं।

/

[2023] 15 एस सी आर।

मध्यस्थता के लिए, बशर्ते कि यदि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णयों को उन लोगों से अलग किया जा सकता है जो इस तरह से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो मध्यस्थता पुरस्कार के केवल उस हिस्से को अलग किया जा सकता है जिसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं; या

((v) मध्यस्थता न्यायाधिकरण या मध्यस्थता प्रक्रिया की संरचना पक्षकारों के समझौते के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा समझौता भाग I के किसी प्रावधान के साथ नहीं था जिससे पक्षकार अवमूल्यन नहीं कर सकते थे, या ऐसे समझौते में विफल रहना, भाग I के अनुसार नहीं था।

इसके अलावा, न्यायालय एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग कर सकती है यदि वह यह मानती है कि: ((i) विवाद का विषय उस समय लागू विधि के अंतर्गत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है; या

((ii) मध्यस्थता निर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के अनुरूप है। 122. धारा 34 अंतर्गत मध्यस्थता पुरस्कार अपास्त करते हुए करने के लिए आधार निर्दिष्ट हैं। इस प्रावधान के तहत एक पक्ष को एक या एक से अधिक ऐसे आधारों के अस्तित्व को साबित करने और साबित करने के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता होती है। 123 मध्यस्थता अधिनियम की योजना से पता चलता है कि हालांकि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को क्षमता-क्षमता के सिद्धांत के आधार पर अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों को निर्धारित करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन न्यायाधिकरण का निर्णय उस स्तर पर न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है जब किसी पुरस्कार को चुनौती दी जाती है। इसके अलावा, एक आधार जिसके आधार पर एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग किया जा सकता है, वह यह है कि मध्यस्थता समझौता विधि के अंतर्गत मान्य नहीं है। यह इंगित करता है कि मध्यस्थता अधिनियम पूर्व-मध्यस्थता स्तर पर मध्यस्थता समझौते की वैधता का निर्धारण करने वाले न्यायालय पर विचार नहीं करता है।

123. भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड बनाम भद्रा

उत्पाद, 124 इस न्यायालय के समक्ष मुद्दों में से एक यह था कि क्या सीमा के मुद्दे पर कोई निर्णय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाएगा, और इसलिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 द्वारा कवर किया जाएगा। इस न्यायालय ने धारा 16 (1) को यह देखने के लिए संदर्भित किया कि "मध्यस्थ न्यायाधिकरण कर सकता है

अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर नियम, जो यह स्पष्ट करता है कि यह संदर्भित करता है कि क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच शुरू कर सकता है

123 फिज़ा डेवलपर्स एंड इंटर-ट्रेड (पी) लिमिटेड बनाम एएमसीआई (आई) (पी) लिमिटेड, (2009) 17 एससीसी 796

124 (2018) 2 एससीसी 534 1153

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1154 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

विवाद के पक्षकार।" भद्रा उत्पादों (ऊपर) में, यह माना गया था कि

सीमा का मुद्दा न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है जो कार्यवाही का परीक्षण करता है।

124. उत्तराखंड में पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड बनाम उत्तरी

कोल फील्ड, 125 इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या मध्यस्थों की नियुक्ति के स्तर पर एक रेफरल अदालत को सीमा के मुद्दे पर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी या इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाएगा। इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि योग्यता-क्षमता के सिद्धांत का उद्देश्य "

न्यायिक हस्तक्षेप को कम से कम करें, ताकि मध्यस्थता प्रक्रिया को सीमा पर विफल नहीं किया जा सके, जब एक पक्ष द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई जाती है। "

इसके अलावा, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 16 बहुत व्यापक दायरे का एक समावेशी प्रावधान है:

" 7.13. धारा 16 के प्रावधानों और पूर्व-संदर्भ स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करने की विधायी नीति को देखते हुए, सीमा के मुद्दे पर मध्यस्थ द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। उप-धारा

(1) धारा 16 में प्रावधान है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में "किसी भी आपत्ति सहित" अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय ले सकता है। धारा **16** एक समावेशी प्रावधान है, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता से संबंधित सभी प्रारंभिक मुद्दों को समझेगा।

सीमा का मुद्दा एक अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है, जिसका निर्णय धारा 16 के अंतर्गत मध्यस्थ द्वारा किया जाना आवश्यक होगा, न कि अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत पूर्व-संदर्भ चरण में उच्च न्यायालय द्वारा। एक बार जब मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व विवादित नहीं हो जाता है, तो क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियों सहित सभी मुद्दों पर मध्यस्थ द्वारा निर्णय लिया जाना है।” (जोर दिया गया) 125। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार के लिए जो मुद्दा आता है वह यह है कि क्या मुद्रांकन का मुद्दा एक अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है। क्षेत्राधिकार को आम तौर पर किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण की किसी कारण को सुनने और निर्धारित करने और ऐसे कारण के संबंध में किसी भी न्यायिक शक्ति का निर्णय लेने या प्रयोग करने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है।¹²⁶ क्षेत्राधिकार एक न्यायालय के अधिकार को संदर्भित करता है या

125 (2020) 2 एससीसी 455

126 सुख लाल शेख बनाम तारा चंद ता, 1905 एस. सी. सी. ऑनलाइन काल 164

/

[2023] 15 एस सी आर।

न्यायाधिकरण उन मामलों का निर्णय करता है जो उसके समक्ष मुकदमेबाजी में हैं या अपने निर्णय के लिए औपचारिक तरीके से उसके समक्ष प्रस्तुत मामलों का संज्ञान लेता है।
आधिकारिक तौर पर

न्यासी, पश्चिम बंगाल बनाम सचिंद्र नाथ चटर्जी, 127 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

कि किसी न्यायालय के लिए किसी विशेष मामले का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र होने के लिए, उसे न केवल लाए गए मुकदमे का परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, बल्कि उसे अधिकार भी होना चाहिए

मांगे गए आदेशों को पारित करने के लिए। एन. टी. पी. सी. बनाम सीमेंस एटकिंजेसलचाफ्ट, 128 में यह

न्यायालय ने कहा कि दावे के गुण-दोष में जाने से कोई भी इनकार अधिकार क्षेत्र के दायरे में हो सकता है। तदनुसार, यह देखा गया कि सीमा का मुद्दा अधिकार क्षेत्र में जाता है क्योंकि यदि किसी दावे को सीमा द्वारा वर्जित किया जाता है, तो एक न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।

126. डाक टिकट अधिनियम की धारा 35 में कहा गया है कि एक बिना मोहर वाले उपकरण पर तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि उस पर विधिवत मुहर न लगाई जाए। प्रश्न यह है कि क्या एक न्यायाधिकरण पक्षों के बीच दावों को निपटाने के लिए अपने

अधिकार क्षेत्र का प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकता है जब तक कि अंतर्निहित साधन पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार का दायरा इतना व्यापक है कि मुद्रांकन की पर्याप्तता के मुद्दे सहित इसके अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सभी प्रारंभिक मुद्दों को समझा जा सके।

127. यदि मुद्रांकन का मुद्दा किसी मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया जाता है, तो मुद्रांकन अधिनियम की धारा 33 और 35 यह स्पष्ट करती है कि "पक्षों की सहमति" से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को किसी दस्तावेज को जब्त करने और उसकी जांच करने का अधिकार है। साक्ष्य प्राप्त करने के लिए "पक्षों की सहमति से" अधिकार रखने वाले व्यक्ति में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण शामिल है जिसका गठन पक्षों की सहमति से किया जाता है।

iii. नकारात्मक योग्यता-योग्यता

128. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता विधि के साथ-साथ घरेलू विधि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अदालतों के बजाय अपने अधिकार की चुनौतियों पर शुरू में निर्णय लेने की अनुमति देकर प्राथमिकता देते हैं। इस दृष्टिकोण के पीछे नीतिगत विचार दो गुना है: सबसे पहले, अनुबंध से उत्पन्न होने वाले मूल अधिकारों और दायित्वों के बारे में अपने सभी विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ को चुनने के पक्षों के आपसी इरादे को पहचानना; और दूसरा, दोनों पक्षों को मध्यस्थता करने से रोकना।

127 (1969) 3 एससीआर 128 (2007) 4 एससीसी 451 1155

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1156 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

अदालतों के समक्ष समानांतर कार्यवाही शुरू करना और मध्यस्थता प्रक्रिया में देरी करना। यह योग्यता-योग्यता के सिद्धांत का सकारात्मक पहलू है। 129. इसके विपरीत, नकारात्मक पहलू राष्ट्रीय न्यायालयों की बात करता है। यह न्यायालयों को निर्देश देता है कि वे मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता से संबंधित मुद्दों में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को स्थगित करके रेफरल स्तर पर अपने हस्तक्षेप को सीमित करें। इस प्रकार, सक्षमता-सक्षमता के सिद्धांत के नकारात्मक पहलू से पता चलता है कि न्यायालयों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने से बचना चाहिए, इससे पहले कि मध्यस्थों को स्वयं ऐसा करने का अवसर मिले। 129 मध्यस्थता न्यायाधिकरणों को पहले अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने की अनुमति देना और बाद में अदालतों को यह निर्धारित करने की अनुमति देना कि क्या न्यायाधिकरण ने अपनी शक्तियों का उचित रूप से प्रयोग किया है, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के साथ-साथ अदालतों की शक्ति और अधिकार दोनों की रक्षा करता है। इस सिद्धांत के नकारात्मक पहलू को भारतीय अदालतों द्वारा स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, इस

सिद्धांत को एक नियम के रूप में अस्वीकार किया जा सकता है जिसके तहत मध्यस्थों को अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों को सुनने का पहला अवसर मिलना चाहिए, जो अदालतों द्वारा बाद में समीक्षा के अधीन है।

130. क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेट वाटर

प्यूरिफिकेशन इंक., 131 इस न्यायालय के समक्ष मुद्दों में से एक यह था कि क्या धारा 45 के अंतर्गत रेफरल चरण में न्यायालय को मध्यस्थता समझौते की वैधता निर्धारित करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय ने माना कि योग्यता-योग्यता के सिद्धांत के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। यह देखा गया कि सकारात्मक पहलू मध्यस्थ को अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने में सक्षम बनाता है, जबकि नकारात्मक पहलू अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से वंचित करता है। हालाँकि, इस न्यायालय ने भाग II में धारा 16 के समान प्रावधान के अभाव पर ध्यान दिया ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि रेफरल अदालत को सीमा स्तर पर ही धारा 45 के अवयवों का परीक्षण करने की आवश्यकता है।

131. इसके बाद, विद्या द्रोलिया (ऊपर) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि योग्यता-योग्यता के सिद्धांत के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों अर्थ हैं। निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

129 जॉर्ज ए बर्मन, 'द गेटवे प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन' (2012) 37 येल जर्नल ऑफ इंटरनेशनल विधि 1,16.

130 फौचर्ड (संख्या 116) 401

131 (2013) 1 एस. सी. सी. 641

/

[2023] 15 एस सी आर।

“129. सक्षमता-सक्षमता के सिद्धांतों के सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ होते हैं। एक सकारात्मक निहितार्थ के रूप में, मध्यस्थ न्यायाधिकरणों को अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में निर्णय लेने और गैर-मध्यस्थता प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए विधि द्वारा सक्षम और अधिकृत घोषित किया जाता है। व्यक्त नकारात्मक प्रभाव के मामले में, कानून शासित होगा और इसका पालन किया जाना चाहिए। निहित नकारात्मक प्रभाव न्यायालय द्वारा रेफरल स्तर पर आवश्यक निहितार्थ द्वारा हस्तक्षेप को कम करता है और बाधित करता है ताकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में निर्णय लेने और गैर-मध्यस्थता प्रश्नों पर निर्णय लेने की अनुमति मिल सके। नकारात्मक प्रभाव अधिनियम के अनुसार, रेफरल स्तर पर अदालतों को गुण-दोष पर निर्णय नहीं लेना है, सिवाय इसके कि जब कानून द्वारा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा अनुमति दी जाए, तो ऐसे गैर-मध्यस्थता के प्रश्न। अदालतों पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण की इस तरह की प्राथमिकता आंशिक और सीमित हो

सकती है जब कानून "पहली नज़र" रेफरल चरण में कुछ या प्रतिबंधित जांच का प्रावधान करता है। इसलिए हम कानून, यानी मध्यस्थता अधिनियम के संदर्भ में योग्यता-क्षमता के सिद्धांतों की जांच करेंगे।

132. आर्सेलरमिचल निप्पाँन स्टील (इंडिया) लिमिटेड बनाम एस्सार बल्क

टर्मिनल लिमिटेड, 132 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नकारात्मक क्षमता-क्षमता अदालतों को उन विवादों की सुनवाई करने से रोकती है जिन्हें पक्षों ने पारस्परिक रूप से मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने का इरादा किया है। जैसा कि पूर्ववर्ती धाराओं में कहा गया है, मुद्रांकन का मुद्दा एक अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है। नकारात्मक क्षमता-क्षमता के सिद्धांत के लिए अदालतों को पहले मामले में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लेने के लिए मुद्रांकन के मुद्दे को छोड़ने की आवश्यकता होती है।

एच *। मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक हस्तक्षेप

133. जब पक्ष एक मध्यस्थता समझौते में प्रवेश करते हैं, तो यह उनका आपसी और स्पष्ट इरादा होता है कि वे अपने विवादों को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण में प्रस्तुत करें। मध्यस्थता विधि पक्षकारों को मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रियात्मक तंत्र अपनाने के लिए स्वायत्तता प्रदान करके इस पहलू को मान्यता देता है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समझौतों के साथ-साथ राष्ट्रीय मध्यस्थता कानूनों द्वारा भी पार्टियों की स्वायत्तता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। उदाहरण के लिए, आदर्श विधि के अनुच्छेद 11 (2) में कहा गया है कि मध्यस्थता समझौते के पक्ष मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए निशुल्क हैं। ऐसी स्थिति में जहां पक्षों की सहमत प्रक्रिया विफल हो जाती है, आदर्श विधि

* एड। ध्यान दें: भाग एच 132 (2022) 1 एससीसी 712 1157

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1158 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

राष्ट्रीय न्यायालयों को एक पक्ष के अनुरोध पर मध्यस्थों की नियुक्ति करने की अनुमति देता है। मध्यस्थों की न्यायिक नियुक्ति का सहारा अक्सर पक्षों द्वारा अंतिम उपाय के रूप में लिया जाता है जब उनकी सहमत प्रक्रिया अव्यवहारिक हो जाती है। मध्यस्थों की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रीय न्यायालयों के पास एक मध्यस्थ की नियुक्ति में गतिरोध को हल करने के लिए निहित है। 133

134. जैसा कि इस निर्णय के पूर्ववर्ती खंडों में चर्चा की गई है, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 किसी न्यायिक प्राधिकरण को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती है जब तक कि भाग I के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है। वर्तमान कार्यवाही में, धारा 8 और 11 के अंतर्गत प्रदान की गई अदालतों या न्यायिक अधिकारियों द्वारा शक्तियों का प्रयोग हमारे विचार के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है।

135. फौचार्ड के अनुसार, एक मध्यस्थता समझौते में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। सकारात्मक प्रभाव यह है कि पक्षों को अपने मध्यस्थता के दायरे में आने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थता के समक्ष प्रस्तुत करने के अपने वचन का सम्मान करना चाहिए। पक्ष में, मध्यस्थता समझौते का नकारात्मक प्रभाव यह है कि अदालतों को ऐसे विवादों की सुनवाई करने से प्रतिबंधित किया गया है।¹³⁴ अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने इस सिद्धांत को मान्यता दी है कि न्यायालयों के पास मध्यस्थता समझौते के तहत आने वाले विवादों को सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद II (3) में कहा गया है कि "एक संविदाकारी राज्य का न्यायालय,

जब किसी ऐसे मामले में कार्रवाई की जाती है जिसके संबंध में पक्षों ने इस अनुच्छेद के अर्थ के भीतर एक समझौता किया है, तो पक्षकारों में से किसी एक के अनुरोध पर, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा, जब तक कि यह यह सुनिश्चित नहीं करता है कि उक्त समझौता अमान्य, निष्क्रिय या निष्पादित करने में असमर्थ है। "

136. भारतीय संदर्भ में, धारा 8 में यह प्रावधान है कि जब किसी ऐसे मामले में न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्रवाई की जाती है जो मध्यस्थता समझौते का विषय है, तो ऐसा न्यायिक प्राधिकरण मध्यस्थता समझौते के लिए किसी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर या उसके माध्यम से या उसके अंतर्गत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को विवाद के सार पर अपना पहला बयान जमा करने की तारीख से पहले पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजेगा। धारा 8 न्यायिक प्राधिकारी को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का आदेश देती है "जब तक कि यह

यह माना जाता है कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है।" धारा 8 है मॉडल विधि के अनुच्छेद 8 के आधार पर जो प्रदान करता है कि पहले एक "अदालत"

133 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर आदर्श विधि पर मामला विधि का पाचन (2012) 60

134 फौचार्ड (संख्या 116) 402

/

[2023] 15 एस सी आर।

जो एक मामले में एक कार्रवाई की जाती है जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा "जब तक कि यह नहीं मानता है कि समझौता अमान्य, निष्क्रिय या निष्पादित करने में असमर्थ है। "

यह स्पष्ट है कि धारा 8 ने "न्यायालय" के बजाय विस्तृत शब्द "न्यायिक प्राधिकरण" का उपयोग करके अनुच्छेद 8 से प्रस्थान किया है। एक विस्तृत आवेदन प्रदान करने के लिए विधायिका के इरादे का भी अनुमान लगाया जा सकता है।

इस तथ्य से कि यह अभिव्यक्ति "जब तक कि यह समझ में नहीं आता है कि समझौता अमान्य, निष्क्रिय या निष्पादित होने में असमर्थ है" का कोई स्थान नहीं है।

धारा 8 में। 135-137।मॉडल विधि पर UNCITRAL कार्य समूह टिप्पणी के अनुसार, मॉडल विधि का अनुच्छेद 8 एक मध्यस्थता समझौते के "नकारात्मक प्रभाव" को सुनिश्चित करता है।¹³⁶ इसके अलावा, अनुच्छेद 8 पक्षों को अदालतों के बहिष्कार के लिए मध्यस्थता के लिए अपने विवादों को प्रस्तुत करने के इरादे को प्रभावी बनाता है, भले ही ऐसा बहिष्कार समझौते में व्यक्त किया गया हो। इसी तरह के कानून को अंग्रेजी 137 और फ्रांसीसी 138 राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश राष्ट्रीय कानून न्यायालयों को मध्यस्थता समझौतों के अस्तित्व और वैधता की समीक्षा करने का अधिकार देते हैं। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 9 (4) में प्रावधान है कि एक न्यायालय कानूनी कार्यवाही पर तब तक रोक लगा सकती है जब तक कि यह संतुष्ट न हो कि मध्यस्थता समझौता "अमान्य है।

निष्क्रिय, या प्रदर्शन करने में असमर्थ।" इसी प्रकार, का अनुच्छेद 1458

135 ए. अय्यासामी बनाम ए. परमशिवम, (2016) 10 एससीसी 386

136 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर एक मॉडल विधि के मसौदा पाठ पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी, ए/सी. एन. 9/264 (25 मार्च 1985) 38.

137 यूके मध्यस्थता अधिनियम का अनुच्छेद 9 (1): इसमें लिखा है: "(1) मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष जिसके खिलाफ किसी ऐसे मामले के संबंध में कानूनी कार्यवाही (चाहे दावा या प्रतिदावे के माध्यम से) की जाती है, जिसे समझौते के अंतर्गत मध्यस्थता के लिए भेजा जाना है, (कार्यवाही के अन्य पक्षों को नोटिस देने पर) उस न्यायालय में आवेदन कर सकता है जिसमें कार्यवाही को उस मामले से संबंधित कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए लाया गया है।

[...]

(4) इस धारा के अंतर्गत एक आवेदन पर न्यायालय तब तक रोक लगाएगी जब तक कि यह संतुष्ट नहीं हो जाता कि मध्यस्थता समझौता अमान्य, निष्क्रिय या निष्पादित करने में असमर्थ है। "

138 फ्रांसीसी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1981 का अनुच्छेद 1458। इसमें लिखा है: "यदि मध्यस्थता समझौते के आधार पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित किसी विवाद को राज्य न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, तो वह खुद को अक्षम घोषित करेगा।

यदि विवाद अभी तक मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं है, तो राज्य न्यायालय भी खुद को अक्षम घोषित करेगा, जब तक कि मध्यस्थता समझौता स्पष्ट रूप से अमान्य न हो। "

1159

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1160 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

फ्रांसीसी सिविल संहिता में यह प्रावधान है कि एक राज्य न्यायालय मध्यस्थता समझौते से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने में अक्षम है, जब तक कि मध्यस्थता समझौता "स्पष्ट रूप से

अमान्य" न हो।" इस प्रकार, समीक्षा का मानक जिसे न्यायालय को पूर्व-मध्यस्थ स्तर पर अपनाना चाहिए, क्षेत्राधिकारों में काफी भिन्न होता है।

138. मध्यस्थता कार्यवाही के सुचारू संचालन में प्रमुख बाधाओं में से एक विवाद उत्पन्न होने के बाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन सुनिश्चित करने में पक्षों की अक्षमता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पक्षों के बीच इस तरह की असहमति मध्यस्थता कार्यवाही को पटरी से नहीं उतारती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के साथ-साथ राष्ट्रीय कानून न्यायिक अधिकारियों को मध्यस्थों की नियुक्ति में पक्षों की सहायता करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, घरेलू मध्यस्थता के संदर्भ में फ्रांसीसी नागरिक संहिता के अनुच्छेद 1444 में कहा गया है कि "[i] यदि कोई विवाद है।

किसी पक्ष के व्यवहार या नियुक्ति पद्धति के कार्यान्वयन के कारण मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।" 139 उक्त प्रावधान आगे

प्रावधान है कि राष्ट्रपति घोषणा करेगा कि नियुक्ति का कोई आधार नहीं है

यदि मध्यस्थता खंड स्पष्ट रूप से अमान्य या अनुचित है

एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करें।" मध्यस्थता समझौते की वैधता निर्धारित करने की सीमा तक न्यायिक हस्तक्षेप प्रदान करने का आधार यह सुनिश्चित करना है कि अदालतें ऐसी स्थितियों में मध्यस्थों को यांत्रिक रूप से नियुक्त नहीं करती हैं जहां मध्यस्थता का कोई संविदात्मक आधार नहीं है।¹⁴⁰

139. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित है। यह मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए पक्षों की स्वायत्तता को मान्यता देता है। धारा 11 में न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता केवल तभी होती है जब नियुक्ति प्रक्रिया का पालन करने में पक्षकारों के बीच गतिरोध या विफलता हो। इस प्रक्रिया में, धारा 11 का उद्देश्य उन स्थितियों में मध्यस्थता द्वारा अपने विवादों को निपटाने के लिए पक्षों के आपसी इरादे को प्रभावी बनाना है जहां पक्ष मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहते हैं। तीन मध्यस्थों के साथ एक मध्यस्थता में, प्रत्येक पक्ष को एक-एक मध्यस्थ नियुक्त करने की आवश्यकता होती है, और बाद में दोनों मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे। धारा 11 (6) प्रदान करती है

139 अनुच्छेद 1444, फ्रांसीसी सिविल प्रक्रिया संहिता।¹⁴⁰ फौचार्ड (संख्या 116) 495

/

[2023] 15 एस सी आर।

पक्षकारों द्वारा सहमत मध्यस्थता प्रक्रिया का पालन करने में विफलता पर, जैसा भी मामला हो, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। धारा 11 (6) नियुक्ति प्रक्रिया में तीन संभावित दोषों को सूचीबद्ध करती है, अर्थात्: यदि पहला, एक पक्ष सहमत प्रक्रिया द्वारा आवश्यक कार्य करने में विफल रहता है; दूसरा, पक्ष या दो नियुक्त मध्यस्थ उस प्रक्रिया के अंतर्गत उनसे अपेक्षित समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं; या तीसरा, एक संस्था सहित एक व्यक्ति, उन्हें सौंपे गए किसी भी कार्य को या सहमत प्रक्रिया के अंतर्गत करने में विफल रहता है।

140. धारा 11 (6) का इस न्यायालय के समक्ष एक लंबा और उतार-चढ़ाव वाला इतिहास रहा है, विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश या मध्यस्थ की नियुक्ति में उनके नामित व्यक्ति के कार्य की प्रकृति के संबंध में। एस. पी. बी. एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, 141, इस न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 11 (6) के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। इस प्रक्रिया में, इस न्यायालय ने धारा 11 (6) के अंतर्गत रेफरल अदालत की शक्तियों और अधिकार के दायरे का विश्लेषण किया। इसके अलावा, इस न्यायालय ने नोट किया कि धारा 8 और 11 प्रकृति में पूरक हैं। नतीजतन, यदि धारा 8 के अंतर्गत कार्य करने वाले न्यायिक प्राधिकरण को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने से पहले अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर अनिवार्य रूप से निर्णय लेना है, तो धारा 11 के अंतर्गत संदर्भ पर भी जांच का वही मानक लागू माना गया था। अंत में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 11 (6) के अंतर्गत रेफरल स्तर पर मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को सभी प्रारंभिक मुद्दों को निर्धारित करने का अधिकार था:

“47 (iv) मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश को इस निर्णय के पूर्व भाग में बताए गए प्रारंभिक पहलुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। ये अनुरोध, एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व, एक जीवित दावे के अस्तित्व या अन्यथा, अपनी शक्ति के प्रयोग के लिए शर्त के अस्तित्व और मध्यस्थ या मध्यस्थों की योग्यता पर विचार करने के लिए उनकी अपनी अधिकारिता होगी। मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश को आवश्यकता पड़ने पर अधिनियम की धारा 11 (8) के संदर्भ में योग्य मध्यस्थ को नामित करने के मामले में किसी संस्था की राय लेने का अधिकार होगा, लेकिन मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश केवल मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश की ही हो सकती है। ”

141 (2005) 8 एससीसी 618 1161

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1162 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

141. राष्ट्रीय बीमा में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा रेफरल स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा की जांच की गई थी।

कं. लिमिटेड बनाम।बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड 142 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की जाती है, रेफरल न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित श्रेणियों के मुद्दे उत्पन्न होंगे: (i) वे मुद्दे जिनका निर्णय मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को करना है। ये मुद्दे थे: पहले, क्या आवेदन करने वाले पक्ष ने उपयुक्त उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है; और दूसरा, क्या कोई वैध मध्यस्थता समझौता है और क्या अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आवेदन करने वाला पक्ष इस तरह के समझौते का पक्षकार है;

((ii) वे मुद्दे जिन्हें मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित सदस्य तय करने के लिए चुन सकता है या उन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय पर छोड़ सकता है। ये मुद्दे थे: पहले, क्या दावा एक मृत (लंबे समय से प्रतिबंधित) दावा है या एक जीवित दावा है; और दूसरा, क्या पक्षों ने अपने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके या बिना किसी आपत्ति के वित्तीय भुगतान प्राप्त करके अनुबंध/लेनदेन का समापन किया है; और

(iii) वे मुद्दे जो मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को विशेष रूप से मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ना चाहिए। ये मुद्दे थे: प्रथमतः, क्या किया गया दावा मध्यस्थता खंड के अंतर्गत आता है (उदाहरण के लिए, एक ऐसा मामला जो विभागीय प्राधिकरण के अंतिम निर्णय के लिए आरक्षित है और जिसे मध्यस्थता से अलग या बाहर रखा गया है); और दूसरा, मध्यस्थता में शामिल गुण या कोई दावा।

142. पटेल इंजीनियरिंग (ऊपर) और बोघारा पॉलीफैब (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसलों ने पूर्व-मध्यस्थ स्तर पर अधिक न्यायिक हस्तक्षेप की अनुज्ञात। वास्तव में, रेफरल अदालतों को प्रारंभिक मुद्दों से संक्षिप्त रूप से निपटने के बजाय लघु-परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। यह भारत के विधि आयोग द्वारा भी नोट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप एक व्यापक समस्या है।

142 (2009) 1 एस. सी. सी. 267

/

[2023] 15 एस सी आर।

भारत के कारण मध्यस्थता प्रक्रिया में देरी नहीं हो सकती है। 143 विधि आयोग ने माना कि मध्यस्थता अधिनियम के कार्यान्वयन में एक समस्या यह थी कि धारा 11 के आवेदनों को अदालतों द्वारा वर्षों तक लंबित रखा गया था। स्थिति को सुधारने के लिए, विधि आयोग ने "मुख्य न्यायाधीश" में निहित नियुक्ति की शक्ति की तत्कालीन मौजूदा योजना को "उच्च न्यायालय" और "सर्वोच्च न्यायालय" में बदलने का प्रस्ताव रखा। इसने यह भी स्पष्ट किया कि मध्यस्थों की नियुक्ति की शक्ति को न्यायिक अधिनियम नहीं माना जाना चाहिए।

143. विशेष रूप से, विधि आयोग ने कहा कि मध्यस्थता से पहले के स्तर पर, यानी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन से पहले न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, इसने धारा 8 के अंतर्गत रेफरल चरण में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे को सीमित करने का प्रस्ताव किया और

11 मध्यस्थता अधिनियम की उन स्थितियों के लिए जहां न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण यह मानता है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या अमान्य है।" द.

विधि आयोग ने धारा 11 के अंतर्गत उप-धारा 6 ए को शामिल करने का सुझाव दिया

जो पढ़ेगा: " उच्च न्यायालय या उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अंतर्गत उसके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्थान द्वारा कोई नियुक्ति केवल तभी नहीं की जाएगी जब उच्च न्यायालय यह मानता है कि मध्यस्थता

अस्तित्व में नहीं है या शून्य है।" विधि आयोग की सिफारिशों के आलोक में, संसद ने धारा 11 (6-ए) को शामिल करने के लिए मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 144 पारित किया।

144. 2015 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण अंतर्गत कहा गया है कि उप-धारा (6 ए) को धारा 11 अंतर्गत जोड़ा गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय निम्नलिखित आवेदनों पर विचार करते समय

उप-धारा (4) से (6) "मध्यस्थता की परीक्षा के लिए मान्य नहीं होगी।

समझौता।" 2015 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के साथ, धारा 11 के अंतर्गत रेफरल चरण में प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति को एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के लिए आश्वस्त किया गया था। यह भी शामिल है

एक गैर-अस्थाई खंड जिसमें "किसी भी निर्णय , डिक्री या आदेश को शामिल किया गया है न्यायालय ।" गैर-अस्थाई खंड के आधार पर, धारा 11 (6 ए) ने विधि की एक नई स्थिति निर्धारित की है, जो पटेल इंजीनियरिंग (उपरोक्त) में इस न्यायालय के पिछले फैसलों द्वारा निर्धारित स्थिति के आधार को छीन लेती है और

143 भारत का विधि आयोग, 246 वीं रिपोर्ट (2014) 144 "2015 संशोधन अधिनियम"

1163

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1164 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

बोधारा पॉलीफैब (ऊपर)। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संसद ने "या अमान्य है" अभिव्यक्ति को शामिल नहीं किया जैसा कि विधि आयोग द्वारा सुझाव दिया गया था। यह

इंगित करता है कि संसद का इरादा पूर्व-मध्यस्थता स्तर पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को यथासंभव न्यूनतम स्तर तक सीमित करना था।

145. 2015 के संशोधन अधिनियम के प्रभाव और प्रभाव को बाद में इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया था। ड्यूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम गंगावरम पोर्ट लिमिटेड, 145 में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने उल्लेख किया कि धारा 11 (6 ए) को शामिल करने में विधायिका का इरादा रेफरल अदालत के अधिकार क्षेत्र के दायरे को केवल एक पहलू तक सीमित करना था-एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व। मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए, न्यायालय को केवल यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या अंतर्निहित अनुबंध में एक खंड है जो समझौते के पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवादों से संबंधित मध्यस्थता का प्रावधान करता है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 11 (6 ए) में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप के सिद्धांत को शामिल किया गया है:

“59. 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के अंतर्गत शक्ति का दायरा एस. बी. पी. एंड कंपनी और बोधारा पॉलीफैब में निर्णयों को देखते हुए काफी व्यापक था। यह स्थिति 2015 में लाए गए संशोधन तक जारी रही। संशोधन के बाद, अदालतों को केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है-कुछ भी अधिक नहीं, कुछ भी कम नहीं। विधायी नीति और उद्देश्य अनिवार्य रूप से मध्यस्थ की नियुक्ति के स्तर पर न्यायालय के हस्तक्षेप को कम करना है और धारा 11 (6-ए) में शामिल इस इरादे का सम्मान किया जाना चाहिए।” 146. 2017 में, भारत में मध्यस्थता तंत्र के संस्थागतकरण की समीक्षा करने के लिए उच्च-स्तरीय समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि 2015 के संशोधन ने धारा 11 के आवेदनों के त्वरित निपटान की सुविधा प्रदान की, लेकिन वे मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करने में विफल रहे। तदनुसार, उच्च स्तरीय समिति ने धारा 11 में संशोधन की सिफारिश की ताकि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय या अन्य सभी मध्यस्थता के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा नामित मध्यस्थ संस्थानों द्वारा केवल मध्यस्थों की नियुक्ति का प्रावधान किया जा सके। उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, संसद ने

145 (2017) 9 एस. सी. सी. 729

/

[2023] 15 एस सी आर।

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2019, 146 में धारा 11 (6 ए) को हटा दिया गया है ताकि मध्यस्थों की नियुक्ति मध्यस्थ संस्थानों पर छोड़ दी जा सके। 2019 के संशोधन अधिनियम की धारा 1 (2) में प्रावधान है कि संशोधित प्रावधान आधिकारिक राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा संपादित अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे, हालांकि, 2019 के संशोधन

अधिनियम की धारा 3, जिसने धारा 11 (6 ए) को हटाकर धारा 11 में संशोधन किया था, को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। तब तक धारा 11 (6 ए) काम करती रहेगी।

147. मायावती ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड बनाम प्रद्युत देब बर्मन, 147 ए

इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने ज्यूरॉ फेलगुएरा (ऊपर) में तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि धारा 11 (6 ए) के अंतर्गत जांच "विश्वसनीय" है।

एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करने के लिए और है

संकीर्ण अर्थों में समझा जाए।” इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि 2015 के संशोधन अधिनियम से पहले विधि की स्थिति, जैसा कि इसके निर्णयों द्वारा निर्धारित किया गया है

पटेल इंजीनियरिंग (ऊपर) और बोधारा पॉलीफैब (ऊपर) में न्यायालय ने

विधायी रूप से अस्वीकृत। इस प्रकार, इस न्यायालय ने पूर्व-मध्यस्थ स्तर पर न्यायालयों की भूमिका को न्यूनतम करने में विधायिका के इरादे को प्रभावी बना दिया।

148. इसके बाद, विद्या द्रोलिया (ऊपर) मामले में, इस न्यायालय की एक अन्य तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मायावती ट्रेडिंग (ऊपर) के फैसले को खारिज कर दिया कि पटेल इंजीनियरिंग (ऊपर) को विधायी रूप से खारिज कर दिया गया है। विद्या द्रोलिया (ऊपर) में, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दों में से एक यह था कि क्या न्यायालय संदर्भ स्तर पर या मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थता न्यायाधिकरण गैर-मध्यस्थता के प्रश्न का निर्णय करेगा। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए अपना विश्लेषण शुरू किया कि एक मध्यस्थता समझौते को एक समझौते के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अनुबंध अधिनियम के अधिदेश को पूरा करना होगा।

149. निर्णय के दौरान, विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) में इस न्यायालय के समक्ष प्रश्नों में से एक धारा 11 में दिखाई देने वाले "अस्तित्व" शब्द की व्याख्या थी। यह माना गया था कि अस्तित्व और वैधता आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, यह देखा गया कि एक मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है यदि यह अवैध है या अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। इसलिए, इस न्यायालय ने वैध मध्यस्थता समझौते के आदेश को पढ़ा

146 “2019 संशोधन अधिनियम” 147 (2019) 8 एस. सी. सी. 714 1165

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1166 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

धारा 11 के अधिदेश में धारा 8 में निहित है, अर्थात् "मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व।"

150. शुरुआत में, विद्या द्रोलिया (ऊपर) ने उल्लेख किया कि "धारा 11 है

2019 के अधिनियम 33 के माध्यम से 9 से 8 तक प्रभावी अधिनियम के साथ एक और संशोधन किया गया -

2019. " उक्त खंड को हटाने के उद्देश्य को आगे निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया है:

"145. 2019 के अधिनियम 33 द्वारा उप-धारा (6-ए) को हटाना विनिर्दिष्ट सी उद्देश्य और उद्देश्य के साथ था और 2019 के अधिनियम 33 द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 की उप-धाराओं (12), (13) और (14) के प्रतिस्थापन द्वारा संबंधित है, जो उप-धारा (3-ए) के माध्यम से निर्धारित करता है कि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय को उन मध्यस्थ संस्थानों को नामित करने की शक्ति होगी जिन्हें परिषद द्वारा धारा 43-1 के अंतर्गत इस तरह से वर्गीकृत किया गया है, बशर्ते कि एक श्रेणीबद्ध मध्यस्थ संस्था उपलब्ध न हो, संबंधित उच्च न्यायालय कार्य के निर्वहन के लिए मध्यस्थों का एक पैनल बनाए रखेगा और उसके बाद उच्च न्यायालय मध्यस्थता संस्थान का कर्तव्य निभाएगा। इसलिए यह स्वीकार करना गलत होगा कि उप-धारा (6-ए) को हटाए जाने के बाद

धारा 11 पटेल एंग में अनुपात।लिमिटेड [एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम.पटेल एंग।

लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618] लागू होगा। "

151. विद्या द्रोलिया (ऊपर) इस धारणा पर आगे बढ़ती हैं कि 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 11 (6 ए) को क़ानून की पुस्तकों से प्रभावी रूप से हटा दिया गया था। न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में भी इसका उल्लेख किया गया है, जैसा कि निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट होता है:

" 154.1.पटेल इंग में निर्णय का अनुपात।लिमिटेड [एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम.पटेल एंग।लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618] मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के अंतर्गत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे पर, 2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधनों को पोस्ट करें (23-10-2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ) और यहां तक कि संशोधनों को पोस्ट करें।

2019 के अधिनियम 33 के अनुसार (9-8-2019 से प्रभावी होने के साथ), अब लागू नहीं है। "

(जोर दिया गया) 152।हमारी राय है कि विद्या द्रोलिया (ऊपर) में न्यायालय का उपरोक्त आधार गलत है क्योंकि धारा 11 (6 ए) को हटाने को अधिसूचित नहीं किया गया है और इसलिए उक्त प्रावधान बना हुआ है।

/

[2023] 15 एस सी आर।

पूरी ताकत से। चूंकि धारा 11 (6 ए) केंद्र सरकार की अधिसूचना लंबित रहने तक लागू है, इसलिए इस न्यायालय पर विधायी इरादे को सही प्रभाव देने का दायित्व है।

153. 2015 के संशोधन अधिनियम ने धारा 8 और धारा 11 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा के लिए अलग-अलग मानदंड निर्धारित किए हैं। जहां धारा 8 रेफरल न्यायालय से एक वैध मध्यस्थता समझौते के प्रथम दृष्टया अस्तित्व को देखने की अपेक्षा करती है, धारा 11 एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करती है। यद्यपि दोनों धाराओं 8 और 11 के पीछे का उद्देश्य और उद्देश्य पक्षों को अपनी संविदात्मक समझ का पालन करने के लिए मजबूर करना है, उक्त प्रावधानों के अंतर्गत रेफरल अदालतों की शक्ति का दायरा अलग होना अभिप्रेत है। यही बात इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश से अपील की अनुमति देती है जो धारा 8 के अंतर्गत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने से इनकार करता है, लेकिन धारा 11 से नहीं। इस प्रकार, 2015 के संशोधन अधिनियम ने पटेल इंजीनियरिंग (उपरोक्त) के उस कथन को विधायी रूप से खारिज कर दिया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 8 और धारा 11 प्रकृति में पूरक हैं। तदनुसार, दोनों प्रावधानों को एक समान मानक निर्धारित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

154. विधायिका ने धारा 11 (6 ए) के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच के लिए संदर्भ का दायरा निर्धारित किया। "परीक्षा" शब्द का उपयोग अपने आप में यह दर्शाता है कि शक्ति का दायरा प्रथम दृष्टया निर्धारण तक सीमित है। चूंकि मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है, इसलिए मध्यस्थता समझौते के "अस्तित्व" की आवश्यकता मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 से प्रभावी होती है। ड्यूरो फेलगुएरा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा कि रेफरल अदालतों को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए केवल एक पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है-क्या अंतर्निहित अनुबंध में एक मध्यस्थता समझौता है जो समझौते के पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवादों से संबंधित मध्यस्थता का प्रावधान करता है। इसलिए, धारा 11 (6 ए) के अंतर्गत जांच का दायरा धारा 7 के आधार पर मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व तक सीमित होना चाहिए। इसी तरह, एक मध्यस्थता समझौते की वैधता, धारा 7 को देखते हुए, औपचारिक वैधता की आवश्यकता तक सीमित होनी चाहिए जैसे कि समझौते को लिखित रूप में होने की आवश्यकता। यह व्याख्या धारा 16 के अंतर्गत मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले मध्यस्थता समझौते के मूल अस्तित्व और वैधता के मुद्दे को छोड़कर क्षमता-क्षमता के सिद्धांत को सही प्रभाव भी देती है। हम तदनुसार 1167 को स्पष्ट करते हैं।

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1168 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और धारा 11 के संदर्भ में विद्या द्रोलिया (उपर्युक्त) में निर्धारित विधि की स्थिति।

155. मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को साबित करने का भार आम तौर पर उस पक्ष पर होता है जो इस तरह के समझौते पर भरोसा करना चाहता है। भारत जैसे क्षेत्राधिकारों में, जो क्षमता-क्षमता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, केवल मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का प्रथम दृष्टया प्रमाण रेफरल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देकर लघु-परीक्षण करने के लिए रेफरल न्यायालय उपयुक्त मंच नहीं है। साक्ष्य के आधार पर मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता का निर्धारण मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए। विधि की इस स्थिति का अंदाजा क़ानून की सादे भाषा से भी लगाया जा सकता है।

156. धारा 11 (6 ए) में "मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। "परीक्षा" शब्द का उपयोग करने का तात्पर्य यह है कि विधायिका का इरादा है कि रेफरल न्यायालय को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के लिए पक्षों के बीच लेनदेन का निरीक्षण या जांच करनी होगी। इसके अलावा, "परीक्षा" शब्द का अर्थ श्रमसाध्य या विवादित जांच नहीं है।¹⁴⁸ दूसरी ओर, धारा 16 में प्रावधान है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र पर "निर्णय" दे सकता है, जिसमें मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व और वैधता भी शामिल है। एक "निर्णय" पक्षों से साक्ष्य स्वीकार करने के बाद विवादों के निर्णय को संदर्भित करता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि रेफरल न्यायालय को केवल मध्यस्थता समझौतों के अस्तित्व की जांच करने की आवश्यकता है, जबकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता से संबंधित मुद्दों सहित अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेना चाहिए। एक समान दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया था

शिन-एत्सु केमिकल कं. लिमिटेड बनाम अक्ष ऑप्टिफी ब्रे लिमिटेड. 149

157. शिन-एत्सु (ऊपर) में, इस न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की असंशोधित धारा 45 द्वारा विचार किए गए निर्णय की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए कहा गया था जब मध्यस्थता समझौते के संबंध में आपत्ति थी।

"शून्य और शून्य, निष्क्रिय या प्रदर्शन करने में असमर्थ" होने को उठाया जाता है न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष। बहुमत के लिए लिखते हुए, न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्णा

148 पी रामनाथ अय्यर, द विधि लेक्सिकन (दूसरा संस्करण, 1997) 666 149 (2005) 7 एस. सी. सी. 234

/

[2023] 15 एस सी आर।

अभिनिर्धारित किया कि धारा 45 में न्यायिक प्राधिकारी को अंतिम निर्धारण देने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने कहा कि:

“74. इस दृष्टिकोण को अपनाने के अलग-अलग फायदे हैं कि धारा 45 के लिए न्यायालय द्वारा निर्णयात्मक निर्णय की आवश्यकता नहीं है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के मध्यस्थता नियमों के अंतर्गत (जैसा कि वर्तमान मामले में 1-1-1998 से प्रभावी होने के साथ लागू है), निश्चित रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपनी अधिकारिता पर शासन करने की शक्ति निहित है। यहां तक कि अगर न्यायालय का विचार है कि मध्यस्थता समझौता दूषित नहीं है या यह विशुद्ध रूप से प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण के आधार पर अमान्य, निष्क्रिय या अप्रवर्तनीय नहीं है, तो भी मध्यस्थ को इस मुद्दे का पूरी तरह से परीक्षण करने और उस पर अंतिम निर्णय देने से कुछ भी नहीं रोकता है। यदि मध्यस्थ समझौते को वैध ठहराता है, तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि मध्यस्थता आगे बढ़ेगी और निर्णय दिया जाएगा। हालाँकि, यदि मध्यस्थ समझौते को अमान्य, निष्क्रिय या शून्य बनाता है, तो इसका मतलब है कि जो पक्ष मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ना चाहता था, उसे मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ने का अवसर दिया गया था, और मध्यस्थ ने मुद्दे को पूरी तरह से देखने के बाद पाया है कि मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है। चूंकि मध्यस्थ का निर्णय एक प्रवर्तनीय निर्णय नहीं होगा, इसलिए अधिनियम की धारा 48 (1) (ए) के अंतर्गत उपलब्ध न्यायिक मध्यस्थता का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

158. जब रेफरल अदालत प्रथम दृष्टया राय देती है, तो न तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण, और न ही मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने वाला न्यायालय इस तरह के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से बाध्य होगा। यदि एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बारे में एक प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण रेफरल न्यायालय द्वारा लिया जाता है, तो यह अभी भी मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मुद्दे की गहराई से जांच करने की अनुमति देता है। इस तरह के कानूनी दृष्टिकोण से रेफरल न्यायालय को प्रथम दृष्टया गैर-मौजूद मध्यस्थता समझौतों को समाप्त करने में मदद मिलेगी। यह मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरणों की अधिकार क्षेत्र की क्षमता की भी रक्षा करेगा।

आई *। मध्यस्थता अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम और अनुबंध अधिनियम का सामंजस्यपूर्ण निर्माण

159. विधियों की व्याख्या के प्रमुख सिद्धांतों में से एक विधायी इरादे की खोज करना और उसे प्रभावी बनाना है। यदि कोई कानून दो व्याख्याओं के लिए अतिसंवेदनशील है, तो न्यायालय को उस निर्माण को अस्वीकार करना होगा जो

* एड। ध्यान दें: भाग I 1169

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1170 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर. के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते।

यह कानून के स्पष्ट इरादे को विफल कर देगा। 150 न्यायालय को न केवल व्याख्या किए जाने वाले खंड पर, बल्कि कानून की संपूर्णता पर भी विचार करके कानून के इरादे का पता लगाना होता है। विधायिका अक्सर विधायी नीति को प्रभावी बनाने के लिए एक कानून बनाती

है। किसी क़ानून को लागू करते समय, विधायिका अक्सर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि किसी क़ानून के प्रावधान उसी क़ानून के प्रावधानों या किसी अन्य क़ानून के प्रावधानों का खंडन नहीं करते हैं। हालाँकि, कानूनों के बीच विसंगतियाँ या विरोधाभास फिर भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में, इस तरह के कानूनों के काम करने के बीच सामंजस्य लाने का काम न्यायालय पर छोड़ दिया जाता है।

160. सुल्ताना बेगम बनाम प्रेम चंद जैन, 151 में इस न्यायालय ने विश्लेषण किया इस न्यायालय के सुसंगत निर्णय और विधियों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए:

ए। यह न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे अधिनियम की दो धाराओं के बीच आमने-सामने के टकराव से बचें और उन प्रावधानों का इस तरह से अर्थ निकालें जो एक-दूसरे के साथ परस्पर मेल खाते प्रतीत होते हैं ताकि उनमें सामंजस्य स्थापित हो सके।

बी। कानून के एक खंड के प्रावधानों का उपयोग अन्य प्रावधानों को विफल करने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय, अपने प्रभाव के बावजूद, उनके बीच सुलह करना असंभव न मान ले।

ग. जब किसी अधिनियम में दो मिश्रित प्रावधान हैं, जिनका एक-दूसरे के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है, तो उनकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि, यदि संभव हो, तो दोनों को प्रभावी अधिनियम दिया जाना चाहिए। यह सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम का सार है;

घ. अदालतों को यह भी ध्यान रखना होगा कि एक व्याख्या जो प्रावधानों में से एक को "मृत पत्र" या "बेकार लकड़ी" में बदल देती है, सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है; और

ङ. सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ किसी भी वैधानिक प्रावधान को नष्ट करना या उसे अनुचित बनाना नहीं है।

150 सी. आई. टी. बनाम हिंदुस्तान बल्क कैरियर, (2003) 3 एस. सी. सी. 57

151 (1997) 1 एस. सी. सी. 373

161. कांडला निर्यात निगम बनाम ओ. सी. आई. निगम 152 में,

इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या एक अपील जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत बनाए रखने योग्य नहीं थी, फिर भी वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 13 (1) के अंतर्गत बनाए रखने योग्य थी। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 में प्रावधान है कि निम्नलिखित से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी: (ए) धारा 45 के अंतर्गत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें; और (बी) धारा 48 के अंतर्गत एक विदेशी पुरस्कार लागू करें। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम,

2015 की धारा 13 (1) किसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक न्यायालय या वाणिज्यिक प्रभाग के निर्णय से व्यथित किसी भी व्यक्ति को उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के समक्ष अपील करने की अनुमति देती है।

162. इस न्यायालय ने दोनों कानूनों के उद्देश्यों को यह देखने के लिए संदर्भित किया कि मध्यस्थता अधिनियम पक्षों के बीच विवादों के त्वरित समाधान को प्रभावी बनाने के लिए है, जबकि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 महत्वपूर्ण राशि से जुड़े वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान के लिए है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि विदेशी मध्यस्थता के मामलों में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 13 (1) के अंतर्गत एक और अपील का प्रावधान विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों को तेजी से लागू करने के उद्देश्य के खिलाफ होगा। इसलिए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 का कोई भी निर्माण, जिससे विदेशी अधिनिर्णय को तेजी से लागू करने के बजाय और देरी होगी, को रोका जाना चाहिए:

“यहां तक कि दोनों कानूनों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करने पर भी, यह स्पष्ट है कि विशेष क़ानून यानी मध्यस्थता अधिनियम को प्रभावी बनाकर उनका सबसे अच्छा सामंजस्य किया जाता है, जबकि अधिक सामान्य क़ानून, अर्थात् वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम को मध्यस्थता के अलावा अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ”

163. शिल्पी इंडस्ट्रीज बनाम केरल राज्य सड़क परिवहन

निगम, 153 इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 18 (3) के अंतर्गत शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में एक प्रति-दावा बनाए रखने योग्य था। धारा 18 (3) में प्रावधान है कि जहां किसी भी पक्ष द्वारा शुरू की गई सुलह की कार्यवाही सफल नहीं होती है और पक्षों के बीच किसी भी समझौते के बिना समाप्त हो जाती है, तो सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद या तो निर्णय लेगी।

152 (2018) 14 एस. सी. सी. 715

153 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 439 1171

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1172 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर. के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते।

विवाद को मध्यस्थता के लिए या इसे किसी संस्था या केंद्र को भेजें। उक्त प्रावधान में आगे कहा गया है कि मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान तब विवादों पर लागू होंगे जैसे कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 (1) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी।

164. इस न्यायालय ने नोट किया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 23 (2 ए) प्रत्यर्थी को एक जवाबी दावा प्रस्तुत करने या एक सेट-ऑफ का अनुरोध करने का अधिकार देती है, जिस पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि एमएसएमई अधिनियम की धारा 18 (3) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि धारा 18 (3) के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही इस तरह की जाएगी जैसे कि वे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 (1) के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में हों, इसलिए एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक प्राधिकरणों के समक्ष जवाबी दावा करने का अधिकार मौजूद है। इस तरह दोनों कानूनों में सामंजस्य स्थापित किया गया।

165. वर्तमान संदर्भ में, इस न्यायालय के समक्ष चुनौती मध्यस्थता अधिनियम और स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों को सुसंगत बनाना है। मध्यस्थता अधिनियम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ मध्यस्थता की एक प्रभावी प्रक्रिया सुनिश्चित करना और मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायालयों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करना है। दूसरी ओर, स्टाम्प अधिनियम का उद्देश्य राज्य के लिए राजस्व सुनिश्चित करना है। यह विधियों की व्याख्या का एक प्रमुख सिद्धांत है कि यदि संभव हो तो दोनों विधियों में निहित प्रावधानों की व्याख्या सामंजस्यपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए ताकि दोनों विधियों को पूर्ण प्रभाव दिया जा सके।¹⁵⁴ एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या प्रदान करने में, इस न्यायालय को इस तथ्य का संज्ञान लेना होगा कि वह कानूनों के उद्देश्य को विफल नहीं करता है या उन्हें अप्रभावी नहीं बनाता है।¹⁵⁵ इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष चुनौती मध्यस्थता अधिनियम और स्टाम्प अधिनियम दोनों की व्यवहार्यता और प्रभावशीलता को संरक्षित करने की है।¹⁵⁶

आई. मध्यस्थता समझौतों के संबंध में मध्यस्थता अधिनियम को प्राथमिकता दी जाएगी

166. जैसा कि पूर्ववर्ती खंडों में चर्चा की गई है, मध्यस्थता अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ भारत में मध्यस्थता से संबंधित विधि को समेकित करने के लिए अधिनियमित एक विधि है। कई कारणों से मध्यस्थता समझौतों के संबंध में स्टाम्प अधिनियम और अनुबंध अधिनियम पर इसकी प्रधानता होगी।

¹⁵⁴ जगदीश सिंह बनाम उपराज्यपाल, दिल्ली, (1997) 4 एस. सी. सी. 435 ¹⁵⁵ तमिलनाडु राज्य बनाम एम. के. कंदस्वामी, (1975) 4 एस. सी. सी. 745 ¹⁵⁶ सी. आई. टी. बनाम हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स, (2003) 3 एस. सी. सी. 57

ए। मध्यस्थता अधिनियम एक विशेष विधि है और भारतीय अनुबंध अधिनियम और स्टाम्प अधिनियम सामान्य विधि हैं।

167. यह तुच्छ विधि है कि एक सामान्य विधि को एक विशेष विधि को रास्ता देना चाहिए। निर्माण का यह नियम जनरलिया स्पेशलिबस नॉन सिद्धांत से उपजा है।

अपमानजनक। एल. आई. सी. बनाम डी. जे. बहादुर, 157 में इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

“52. यह निर्धारित करने में कि कोई क़ानून विशेष है या सामान्य, ध्यान मुख्य विषय-वस्तु और विशेष परिप्रेक्ष्य पर होना चाहिए। कुछ उद्देश्यों के लिए, एक अधिनियम सामान्य हो सकता है और कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए यह विशेष हो सकता है और हम विधि के अन्य बिंदुओं से निपटने के दौरान अंतर को धुंधला नहीं कर सकते हैं। ”

सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम.टी. थंकम, 158 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

“13. ... एक बार जब न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है कि एक विशेष क़ानून के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में उसकी अधिकारिता को छीन लिया गया है, तो दीवानी न्यायालय को पहले यह देखना चाहिए कि क्या विशेष क़ानून के अंतर्गत प्रक्रिया के संदर्भ में अधिकार क्षेत्र को हटा दिया गया है या उसका अनुपालन किया गया है। सामान्य विधि को विशेष विधि के अधीन होना चाहिए-सामान्य विशेष गैर अपमानजनक। ऐसी स्थिति में, दृष्टिकोण यह देखने के लिए नहीं होगा कि सामान्य विधि के अंतर्गत दीवानी न्यायालय में अभी भी अधिकार क्षेत्र है या नहीं। इस तरह के दृष्टिकोण केवल विवादों के समाधान में देरी करेंगे और शिकायत के निवारण को जटिल बना देंगे और निश्चित रूप से न्यायालय में अनावश्यक रूप से विचाराधीनता को बढ़ा देंगे। ”

169. इन उदाहरणों से विधि की निम्नलिखित स्थिति सामने आती है: ए। मुख्य विषय-वस्तु के साथ-साथ विशेष परिप्रेक्ष्य या ध्यान यह पता लगाने के लिए मार्ग को रोशन करता है कि कोई विधि सामान्य विधि है या विशेष विधि ; और

बी। न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या किसी विशेष विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में उसके अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया है।

170. यह निर्धारित करने के लिए कि इस न्यायालय का सामना करने वाले तीन विधि ों में से कौन सा एक विशेष विधि है, यह आवश्यक है कि पहले उनके विषय-वस्तु का उल्लेख किया जाए:

157 (1981) 1 एस. सी. सी. 315 158 (2015) 14 एस. सी. सी. 444 1173

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1174

ए। स्टाम्प एक्ट एक विधि है जो सभी प्रकार के उपकरणों के लिए स्टाम्प शुल्क के भुगतान को नियंत्रित करता है। मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची I विभिन्न प्रकार के उपकरणों को निर्धारित करती है जो उक्त विधान के दायरे में आते हैं।

बी। अनुबंध अधिनियम, जैसा कि नाम से पता चलता है, सामान्य रूप से अनुबंधों के संबंध में नियम निर्धारित करता है। एक मध्यस्थता समझौता कई अलग-अलग प्रकार के अनुबंधों में से एक है जिस पर यह लागू होता है; और

ग. मध्यस्थता अधिनियम में घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों के प्रवर्तन और सुलह से संबंधित विधि शामिल हैं।

171. दूसरा, इस मामले का "विशेष परिप्रेक्ष्य" इस बात से संबंधित है कि क्या एक अनस्टैम्ड मध्यस्थता समझौते को स्टाम्प-शुल्क के भुगतान के लंबित रहने तक अप्रवर्तनीय बना दिया गया है ताकि मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने के लिए रेफरल न्यायालय पर एक प्रतिबंध लगाया जा सके। मुद्दा यह नहीं है कि क्या सभी समझौते स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अप्रवर्तनीय हैं, बल्कि यह है कि क्या विशेष रूप से मध्यस्थता समझौते अप्रवर्तनीय हैं।

172. इस मामले के संदर्भ में मध्यस्थता अधिनियम एक विशेष विधि है क्योंकि यह मध्यस्थता समझौतों सहित मध्यस्थता पर विधि को नियंत्रित करता है-इस क़ानून की धारा 2 (1) (बी) और धारा 7 एक मध्यस्थता समझौते की अवहेलना नहीं करती है। इसके विपरीत, स्टाम्प अधिनियम ने समग्र रूप से 'उपकरणों' 159 और अनुबंध अधिनियम ने 'समझौतों' 160 और 'अनुबंधों' की अवहेलना की। 161

173. यह न केवल 'मध्यस्थता समझौते' की अवज्ञा है, बल्कि मध्यस्थता अधिनियम के अन्य प्रावधानों और जिस उद्देश्य के लिए इसे अधिनियमित किया गया था, वह इसे एक विशेष विधि बनाता है। जैसा कि इस न्यायालय ने भावेन में कहा है

निर्माण।(ऊपर), "मध्यस्थता अधिनियम अपने आप में एक संहिता है।" 162 यह प्रदान करता है

एक विस्तृत तंत्र के लिए जिसके द्वारा मध्यस्थता का संचालन किया जा सकता है, ताकि अदालतों के त्वरित और प्रभावी विकल्प के रूप में इसकी सफलता सुनिश्चित की जा सके। मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण

159 धारा 2 (14), स्टाम्प अधिनियम 160 धारा 2 (ई), अनुबंध अधिनियम 161 धारा 2 (एच), अनुबंध अधिनियम 162 अनुच्छेद 12 पर लागू है।

/

[2023] 15 एस सी आर।

यह अभिलेख करता है कि इस विधि का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और वाणिज्यिक मध्यस्थता और सुलह के साथ-साथ घरेलू मध्यस्थता और सुलह को भी व्यापक रूप से शामिल करना था।

बी। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5

174. उपरोक्त खंडों में, हमने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 के दायरे पर चर्चा की है। यह मध्यस्थता अधिनियम के भाग I द्वारा शासित विभिन्न मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा

को प्रतिबंधित करता है। 163 एहि प्रावधानमे गैर-बाध्यकारी खंड विशेष महत्वक अछि। यह इंगित करता है कि धारा 5 में नियम (और परिणामस्वरूप, मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान) को उस समय लागू किसी भी अन्य विधि पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसलिए, न्यायालयों द्वारा किसी भी हस्तक्षेप (एक समझौते को जब्त करने सहित जिसमें एक मध्यस्थता खंड निहित है) की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब मध्यस्थता अधिनियम ऐसे कदम के लिए प्रावधान करता है, जो वह नहीं करता है। धारा 5 में गैर-अस्थाई खंड को देखते हुए धारा 33 और 35 को धारा 11 (या यथास्थिति धारा 8) के अंतर्गत कार्यवाही में काम करने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है। यह मामला होने के कारण, हम एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) के निर्णय से सहमत नहीं हैं, कि न्यायालय को धारा 11 के अंतर्गत एक कार्यवाही में धारा 5 में प्रतिबंध के बावजूद स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 और 35 को प्रभावी बनाना चाहिए। न्यायालय ने कहा:

“129. इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 5 एक गैर-बाध्यकारी खंड का प्रावधान करती है। यह अधिनियम में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर न्यायिक हस्तक्षेप के खिलाफ प्रावधान करता है। अनापत्ति खंड किसी भी विधि की उपस्थिति के बावजूद ऐसा घोषित करने का इरादा रखता है जो अन्यथा हस्तक्षेप के लिए प्रावधान कर सकता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि स्टाम्प अधिनियम, विशेष रूप से, धारा 33 और 35 के संचालन में कोई भूमिका नहीं होगी। हमारा स्पष्ट मत है कि धारा 5 का उद्देश्य स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 और 35 के प्रभाव को हटाना नहीं है। धारा 33 और 35 को प्रभावी बनाने का तात्पर्य रखने वाली धारा 11 के अंतर्गत न्यायालय पर अधिनियम की धारा 5 के विपरीत न्यायिक हस्तक्षेप का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

163 सी. डी. सी. वित्तीय सेवा (मॉरीशस) लिमिटेड बनाम बी. पी. एल. कम्युनिकेशंस लिमिटेड, (2003) 12 एस. सी. सी. 140; एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड बनाम जूट कॉर्प. ऑफ इंडिया लिमिटेड, (2007) 14 एस. सी. सी. 680; एसोसिएट बिल्डर बनाम डी. डी. ए., (2015) 3 एस. सी. सी. 49; भावेन कंस्ट्रक्शन बनाम सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, (2022) 1 एस. सी. सी. 75 1175

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1176 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच मध्यस्थता

175. धारा 5 को एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) में दी गई व्याख्या द्वारा प्रभावी रूप से वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने का कारण प्रदान करने में विफल रही कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कार्यवाही में स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 और 35 के संचालन को बाहर करने का प्रभाव नहीं है। धारा 5 में गैर-अस्थाई खंड ठीक यही करता है। गैर-अस्थाई खंड के प्रभावी अधिनियम के अलावा, मध्यस्थता अधिनियम एक विशेष विधि है। हमें इस तथ्य से भी अवगत होना चाहिए कि मध्यस्थता अधिनियम का एक उद्देश्य मध्यस्थता प्रक्रिया में अदालतों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करना था। 164

176. हमीद जोहारन बनाम अब्दुल सलाम, 165 में इस न्यायालय ने

मुद्रांक अधिनियम और सीमा अधिनियम 1963 के बीच परस्पर क्रिया पर निम्नलिखित टिप्पणियां:

“38. ... सीमा अधिनियम को लागू करने में विधायिका के इरादे को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। न्यायालय के आदेश द्वारा व्याख्या का परिणाम मूर्खता नहीं हो सकती है और जहां भी इस तरह की बेतुकी बात की संभावना है, उसे प्रोत्साहित करने के बजाय उसे पीछे हटाना न्यायिक शक्ति का एक स्पष्ट प्रयोग होगा। भारतीय स्टाम्प अधिनियम का पूरा उद्देश्य कुछ देय राशि उपलब्ध कराना और राजस्व एकत्र करना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है और इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी तरह से अलग क्षेत्र में काम करने वाले किसी अन्य क़ानून पर प्रभाव को ओवरराइड किया जाए। ”

ग. संसद स्टाम्प अधिनियम के बारे में तब जानती थी जब उसने मध्यस्थता अधिनियम लागू किया था।

177. संसद स्टाम्प अधिनियम के बारे में तब जानती थी जब उसने मध्यस्थता अधिनियम लागू किया था। फिर भी, उत्तरार्द्ध एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में मुद्रांकन को निर्दिष्ट नहीं करता है। इसके अलावा, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6-ए) के तहत न्यायालय को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करने की आवश्यकता होती है। यह प्रावधान स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 (2) के विपरीत है जिसमें "जांच" शब्द का भी उपयोग किया गया है। धारा 33 (2) में उस व्यक्ति से यह जांच करने की आवश्यकता है जिसके सामने कोई उपकरण प्रस्तुत किया गया है, कि क्या उस पर उस मूल्य और विवरण की मुहर लगी है जो विधि द्वारा आवश्यक है जब ऐसे उपकरण को निष्पादित किया गया था या पहली बार निष्पादित किया गया था।

164 उद्देश्यों और कारणों के विवरण, मध्यस्थता अधिनियम 165 (2001) 7 एस. सी. सी. 573

/

[2023] 15 एस सी आर।

हालाँकि संसद धारा 33 (2) के अधिदेश से अवगत थी, लेकिन धारा 11 के अंतर्गत कार्य करने वाले न्यायालय को भी धारा 33 (2) द्वारा आवश्यक जाँच करने की आवश्यकता नहीं थी।

ii. विचाराधीन तीनों अंतर्गत नूनों अंतर्गत सामंजस्यपूर्ण निर्माण

ए। योग्यता-योग्यता सिद्धांत का प्रभाव

178. ए. अय्यासामी बनाम ए. परमशिवम, 166 में इसकी दो-न्यायाधीशों की पीठ

हममें से एक न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता को विवादों के समाधान के लिए एक "वन-स्टॉप फोरम" प्रदान करना चाहिए और यह

अभिनिर्धारित किया कि (ए) न्यायालय ों को मध्यस्थता समझौतों के पक्षों की वाणिज्यिक समझ को प्रभावी बनाना चाहिए कि मध्यस्थता प्रभावी है; और (बी) यह न्यायिक हस्तक्षेप को कम करके किया जा सकता है:

“48. न्यायिक निर्णय लेने का मार्गदर्शन करने वाला मूल सिद्धांत यह है कि मध्यस्थता अनिवार्य रूप से एक निजी न्यायाधिकरण के माध्यम से अपने विवादों को हल करने के लिए अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा एक दायित्व की स्वैच्छिक धारणा है। पक्षों की मंशा उनके समझौते की शर्तों में व्यक्त की जाती है।

जहाँ वाणिज्यिक संस्थाएं और व्यवसाय के व्यक्ति इस तरह के लेन-देन में प्रवेश करते हैं, वे मध्यस्थ की प्रभावशीलता के ज्ञान के साथ ऐसा करते हैं।

प्रक्रिया। वाणिज्यिक समझ के संदर्भ में प्रतिबिंबित किया जाता है

पक्षों के बीच समझौता। न्यायालय का कर्तव्य उस व्यावसायिक समझ को व्यावसायिक प्रभाव की भावना प्रदान करना है।

...

53. ... भारत में न्यायशास्त्र को मध्यस्थता के संस्थागत प्रभाव को मजबूत करने की दिशा में विकसित होना चाहिए। दलों द्वारा अपने सभी दावों को हल करने के लिए एक पूर्ण उपाय के रूप में चुने गए मंच के लिए बचाव केवल एक हिस्सा है

उस विकास की। अदालतों के हस्तक्षेप को कम करना फिर से उसी सिद्धांत की मान्यता है। "

(जोर दिया गया)

179. एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) में बहुमत का निर्णय यह मानता है कि साक्ष्य में दस्तावेज़ की अस्वीकृति इसे अप्रवर्तनीय बनाती है।

166 (2016) 10 एससीसी 386 1177

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1178 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

तथापि, सक्षमता-सक्षमता के सिद्धांत का प्रभाव यह है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपनी प्रवर्तनीयता निर्धारित करने की शक्ति और अधिकार निहित है। प्रवर्तनीयता का प्रश्न बना रहता है, दोष का इलाज लंबित रहता है जो उपकरण को अस्वीकार्य बनाता है। एक न्यायाधिकरण या उसके सदस्यों की नियुक्ति करके, यह न्यायालय (या उच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो) केवल धारा 16 में निहित सिद्धांत को प्रभावी बना रहा है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति का आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि वह समझौता जिसमें मध्यस्थता खंड निहित है और साथ ही मध्यस्थता समझौता स्वयं प्रवर्तनीय है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण इन प्रश्नों का सटीक उत्तर देगा।

180. अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में, समझौते अनुबंध हैं यदि वे हैं:

ए। अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्षों की निशुल्क सहमति से बनाया गया; बी। वैध विचार के लिए;

ग. एक वैध उद्देश्य के साथ; और

घ. इसके प्रावधानों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किया गया है।

181. ये आवश्यकताएँ किसी भी लागू विधि को लागू नहीं करती हैं और स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं होती हैं, जो: 167

ए। अनुबंध लिखित रूप में किए जाने की आवश्यकता है;

बी। गवाहों की उपस्थिति में अनुबंध किए जाने की आवश्यकता होती है; या ग। दस्तावेजों के पंजीकरण से संबंधित कानून।

182. इसके अलावा, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करती है।

183. यह मध्यस्थता न्यायाधिकरण है न कि न्यायालय जो यह परीक्षण कर सकता है कि क्या एक वैध अनुबंध और एक वैध मध्यस्थता समझौते की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यदि न्यायाधिकरण यह मानता है कि इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, तो वह आगे विवाद की सुनवाई करने से इनकार कर देगा। यदि यह मानता है कि एक वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है, तो यह आकलन कर सकता है कि अंतर्निहित समझौता एक वैध अनुबंध है या नहीं।

167 धारा 10, अनुबंध अधिनियम

/

[2023] 15 एस सी आर।

184. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 को लागू करके, संसद ने (बोलने के तरीके से) मध्यस्थता समझौते को प्रारंभिक रूप से लागू करने की अनुमति दी है, भले ही वह केवल एक समझौता हो। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के बाद या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत मध्यस्थों की नियुक्ति के बाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास पक्षों के बीच विवाद में सभी प्रश्नों और मुद्दों को निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा। स्टाम्प शुल्क की प्राप्ति में राजस्व की वैध चिंताओं को विफल नहीं किया जाता है क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में कार्य करने का अधिकार क्षेत्र है।

185. योग्यता-क्षमता के सिद्धांत का परिणाम यह है कि अदालतें केवल इस बात की जांच कर सकती हैं कि क्या मध्यस्थता समझौता समीक्षा के प्रथम दृष्टया मानक के आधार पर मौजूद है या नहीं। इस आधार पर कि स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है या अपर्याप्त है, मध्यस्थता न्यायाधिकरण की अधिकारिता पर आपत्तियों की प्रकृति ऐसी है जिस पर प्रथम दृष्टया निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इस तरह की आपत्तियों के लिए साक्ष्य और प्रस्तुतियों पर विस्तृत विचार और विधि के साथ-साथ तथ्यों के बारे में जानकारी की आवश्यकता होगी। धारा 8 या धारा 11 के स्तर पर मोहर लगाने के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय को बाध्य करना मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्निहित विधायी इरादे को विफल कर देगा।

186. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के अंतर्गत अदालतों को कुछ शक्तियां सौंपने का उद्देश्य मध्यस्थता को सुविधाजनक बनाना और सक्षम बनाना है और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि पक्ष मध्यस्थता समझौतों का पालन करें। उनके बीच जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, वे मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में बने हुए हैं (मध्यस्थता खंड द्वारा परिभाषित इसकी अधिकारिता के दायरे के अधीन)। पक्षकारों के बीच मूल विवाद पर देश की अदालतों के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल दो चरणों में संभव है:

ए। यदि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत अंतरिम उपायों के लिए आवेदन किया जाता है; या

बी। यदि पुरस्कार को धारा 34 के अंतर्गत चुनौती दी जाती है।

स्टाम्प शुल्क के भुगतान से संबंधित मुद्दे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के प्रेषण के अंतर्गत आते हैं। पूर्ववर्ती खंडों में चर्चा से यह भी स्पष्ट होता है कि अदालतों को धारा 9 के अंतर्गत अंतरिम उपाय देने के चरण में मुद्रांकन के मुद्दे से निपटने की आवश्यकता नहीं है।

1179

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1180 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

187. हस्तक्षेप करने वालों में से एक, सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र ने प्रस्तुत किया कि एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) में निर्णय ने प्रथम दृष्टया मानक को यह कहते हुए उलट दिया कि न्यायालय किसी विवाद को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेज सकती है यदि उस पर विधिवत मुहर लगाने की आपत्तियां "उसके चेहरे पर, पूरी तरह से आधारहीन" हैं।" हम इस निवेदन से सहमत हैं।

188. एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति हो जाने के बाद, यह विधि के अनुसार कार्य करेगा और यदि वह ऐसा करने के लिए उचित समझता है तो स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत समझौते को जब्त करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसके पास धारा 35 के संदर्भ में पक्षों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद धारा 35 के अंतर्गत प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। इस तरह, योग्यता-योग्यता सिद्धांत को जीवन

दिया जाता है और मध्यस्थता कार्यवाही निचली अदालतों के समक्ष मुकदमों या अन्य, इसी तरह की कार्यवाहियों के लिए एक तेज़ विकल्प बनी रह सकती है।

बी। डाक टिकट अधिनियम की धारा **33** और **35** में "होगा" शब्द का प्रभाव

189. डाक टिकट अधिनियम की धारा 33 और 35 में "होगा" शब्द का उपयोग किया गया है। हालांकि यह सामान्य रूप से इंगित करता है कि प्रावधान अनिवार्य है, इसे इस रूप में पढ़ा जा सकता है

निर्देशिका.सैनिक मोटर्स बनाम राजस्थान राज्य, 168 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

“‘विल’ शब्द आमतौर पर अनिवार्य है, लेकिन कभी-कभी इसकी व्याख्या नहीं की जाती है यदि संदर्भ या इरादा अन्यथा मांग करता है। ”

190. यू. पी. राज्य बनाम बाबू राम उपाध्याय, 169 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

विधियों के निर्माण के लिए जिन सिद्धांतों में अनिवार्य शब्द "होगा" का उपयोग किया गया था, वे इस प्रकार थे:

“29. व्याख्या के प्रासंगिक नियमों को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है: जब कोई कानून "होगा" शब्द का उपयोग करता है, तो प्रथम दृष्टया, यह अनिवार्य है, लेकिन न्यायालय कानून के पूरे दायरे को सावधानीपूर्वक ध्यान में रखते हुए विधायिका के वास्तविक इरादे का पता लगा सकता है। विधानमंडल के वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, कानून की प्रकृति और रूपरेखा पर विचार कर सकता है, और उन परिणामों पर विचार कर सकता है जो इसे एक या दूसरे तरीके से समझने से होंगे,

168 1961 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 15 169 1960 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 5

/

[2023] 15 एस सी आर।

अन्य प्रावधानों का प्रभाव जिसके द्वारा प्रश्न प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता से बचा जाता है, ऐसी परिस्थिति, अर्थात्, कि कानून प्रावधानों का पालन न करने की आकस्मिकता के लिए प्रावधान करता है, यह तथ्य कि प्रावधानों का पालन न करने पर कोई जुर्माना लगाया जाता है या नहीं, इसके गंभीर या तुच्छ परिणाम जो इसके कारण होते हैं, और सबसे बढ़कर, क्या कानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा या आगे बढ़ेगा। "

191. इसलिए इस न्यायालय को यह आकलन करने के लिए धारा 33 और 35 की व्याख्या करनी चाहिए कि क्या वे धारा 8 या धारा 11 के अंतर्गत कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले न्यायालय के संबंध में अनिवार्य हैं:

ए। क्या संदर्भ इंगित करता है कि प्रावधान निर्देशिका है; बी। कानून का दायरा;

ग. कानून की प्रकृति और रूप-रेखा;

घ. इसे किसी न किसी रूप में समझने से होने वाले परिणाम;

ई. अन्य प्रावधानों का प्रभाव;

च. गैर-अनुपालन के परिणाम; और

छ. क्या विधान के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा।

192. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में दिए गए निर्णय एकल कानून में एकल प्रावधान के संदर्भ में दिए गए थे। वर्तमान जैसे मामलों में अतिरिक्त कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, जहां एक ही मुद्दे (या वर्तमान मामले में मध्यस्थता समझौते जैसे एकल समझौते) के संबंध में कई कानून काम करते प्रतीत होते हैं। विचारकों की इस सूची में, जिसे अदालत के मूल्यांकन को सजीव करना चाहिए कि क्या कोई प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशिका, हम यह जोड़ेंगे कि सभी कानूनों के दायरे, प्रकृति और डिजाइन पर विचार किया जाना चाहिए जो एक साथ काम करते प्रतीत होते हैं। उनकी परस्पर क्रिया और विधायिका के इरादे का मूल्यांकन ऐसे सभी कानूनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इस प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या लागू होने वाले विधानों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा।

1181

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1182 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

ग. डाक टिकट अधिनियम का उद्देश्य संरक्षित है।

193. एन एन ग्लोबल 2 (ऊपर) में, बहुमत के निर्णय का अवलोकन इस प्रकार किया गया:

“92. जबकि मुद्रांक अधिनियम राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक अधिनियम है, यह एक ऐसा विधि है, जिसका उद्देश्य प्रभावी होना है। जिस समय पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाना है, उसके लिए स्टाम्प अधिनियम की धारा 17 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। ऐसा कोई लाभ नहीं हो सकता है, जो इसे एक व्यापक अधिनियम कहता है, इसका उद्देश्य यह है कि इसे पूरे जोश के साथ लागू किया जाए। न्यायालय का कर्तव्य एक ऐसी व्याख्या को अपनाना होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप विधि को लागू किया जाए, न कि विधि को दंड से मुक्त करने की अनुमति दी जाए। एक बार जब इस सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है, तो न्यायालय का कार्य कम कठिन हो जाता है।”

194. वर्तमान निर्णय में इस न्यायालय द्वारा स्टाम्प अधिनियम को दी गई व्याख्या विधि की धज्जियां उड़ाने की अनुमति नहीं देती है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों से बंधा हुआ है, जिसमें इसकी ज़ब्ती और स्वीकार्यता से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। इस निर्णय में विधि की व्याख्या यह सुनिश्चित करती है कि मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, जबकि स्टाम्प अधिनियम के उद्देश्य से विचलित नहीं होता है।

195. राजस्व के हितों को किसी भी प्रश्न से खतरे में नहीं डाला जाता है क्योंकि देय शुल्क का भुगतान संबंधित समझौते को स्वीकार्य बनाने और पक्षों के बीच निर्णय लेने से पहले किया जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि समझौते को किस स्तर पर जब्त किया जाएगा और यह नहीं कि क्या इसे बिल्कुल भी जब्त किया जाएगा। अदालतें अपने कर्तव्य का त्याग नहीं कर रही हैं बल्कि इसके बजाय निम्नलिखित को प्रभाव दे रही हैं:

ए। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप का सिद्धांत;

बी। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 पर लागू प्रथम दृष्टया मानक; और

ग. स्टाम्प अधिनियम का उद्देश्य राजस्व के हितों की रक्षा करना है न कि वादियों को तकनीकीता के ऐसे हथियार से लैस करना जिसके द्वारा वे न्यायालय के निर्णय में देरी करते हैं।

घ. विधि की व्याख्या को स्टाम्प अधिनियम के अलावा मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावी बनाना चाहिए।

/

[2023] 15 एस सी आर।

196. एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) में संविधान पीठ का निर्णय विशेष रूप से स्टाम्प अधिनियम के उद्देश्य के लिए प्रभावी है। यह स्टाम्प अधिनियम के उद्देश्य को प्राथमिकता देता है, यानी मध्यस्थता अधिनियम की कीमत पर राजस्व एकत्र करना। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, मध्यस्थता अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाणिज्यिक और अन्य दोनों पक्षों के लिए एक त्वरित और प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली उपलब्ध हो। एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) में स्टाम्प अधिनियम को दी गई व्याख्या से इस उद्देश्य के कमजोर होने का खतरा है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (या जैसा भी मामला हो धारा 8) के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति के चरण में एक मध्यस्थता खंड वाले समझौते को जब्त करने से मध्यस्थता शुरू होने में देरी होगी। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अदालतों पर अनगिनत मामलों का बोझ है। प्रत्येक मामले के आगे बढ़ने की गति में देरी का यह अपरिहार्य परिणाम है। दूसरी ओर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण कम मात्रा में मामलों से निपटते हैं। वे अपने समक्ष एक ही मामले के निर्णय के लिए विस्तारित अवधि समर्पित करने में सक्षम हैं।

यदि किसी विशेष मामले में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा कोई समझौता जब्त किया जाता है, तो यह बहुत अधिक संभव है कि स्टाम्प-शुल्क और जुर्माना (यदि कोई हो) के भुगतान की प्रक्रिया और स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अन्य प्रक्रियाएं अदालतों की तुलना में तेजी से पूरी की जाएं।

जे *।एस. एम. एस. टी एस्टेट और गरवारे बॉल रोप गलत तरीके से तय किए गए थे।एस. एम. एस. चाय एस्टेट

197. वर्तमान मुद्दे की उत्पत्ति एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (उपरोक्त) में इस न्यायालय के दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से हुई है। उस मामले में, अपीलार्थी और प्रतिवादी ने अपीलार्थी के पक्ष में दो चाय बागानों के संबंध में एक पट्टा विलेख निष्पादित किया। पट्टा विलेख में मध्यस्थता द्वारा पक्षों के बीच विवादों के निपटारे का प्रावधान किया गया था। जब अपीलार्थी ने मध्यस्थता खंड को लागू करने की मांग की, तो प्रत्यर्थी ने इस आधार पर इसका विरोध किया कि पट्टा विलेख अपंजीकृत था और उस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई थी, और इसलिए अमान्य, अप्रवर्तनीय और बाध्यकारी नहीं था। उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया। अपील पर, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दे इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आए: पहला, क्या एक अपंजीकृत (लेकिन अनिवार्य रूप से पंजीकृत) लिखत में निहित एक मध्यस्थता समझौता वैध और लागू करने योग्य है; और दूसरा, क्या एक अपंजीकृत लिखत में एक मध्यस्थता समझौता, जिस पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, वैध और लागू करने योग्य है। 198. प्रथम मुद्दे के संबंध में, न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 का विश्लेषण किया। पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 में प्रावधान है कि

* एड। ध्यान दें: पार्ट जे 1183

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1184 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

अपंजीकृत दस्तावेज़ को ऐसी संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी लेन-देन या ऐसी शक्ति प्रदान करने के प्रमाण के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसे पंजीकृत नहीं किया गया हो। हालांकि, धारा 49 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि एक अपंजीकृत साधन का उपयोग किसी भी संपार्श्विक लेनदेन के साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है जिसे ऐसे साधन द्वारा लागू करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक अपंजीकृत लिखत में निहित एक मध्यस्थता समझौता विवादों के समाधान से संबंधित एक संपार्श्विक शब्द है, जो अनुबंध के प्रदर्शन से असंबंधित था। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक अपंजीकृत लेकिन अनिवार्य रूप से पंजीकृत दस्तावेज़ में निहित एक मध्यस्थता समझौते पर कार्रवाई की जा सकती है और मध्यस्थता द्वारा विवाद समाधान के उद्देश्य से लागू किया जा सकता है।

199. दूसरे मुद्दे के संबंध में, यह नोट किया गया कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 में पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 जैसा कोई प्रावधान नहीं है जो बिना स्टाम्प वाले उपकरण का उपयोग संपार्श्विक उद्देश्य के लिए करने में सक्षम बनाता है। इसके बाद, इस न्यायालय ने कहा कि धारा 33 प्रत्येक न्यायालय के साथ-साथ एक मध्यस्थ पर भी कर्तव्य डालती है, जिसके समक्ष यह पता लगाने के लिए कि क्या उस पर विधिवत मुहर लगी है, दस्तावेज की जांच करने के लिए स्टाम्प शुल्क के साथ प्रभार्य एक अपंजीकृत लिखत प्रस्तुत की जाती है। यदि न्यायालय या मध्यस्थ इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि दस्तावेज़ पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, तो उसे दस्तावेज़ को अनिवार्य रूप से जब्त करना होगा। न्यायालय ने उस समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित किया जब एक मध्यस्थता एक दस्तावेज में निहित होती है जिस पर निम्नलिखित शर्तों में विधिवत मुहर नहीं लगी होती है:

ए। न्यायालय को किसी भी दस्तावेज को साक्ष्य में स्वीकार करने या ऐसे दस्तावेज पर कार्रवाई करने से पहले यह जांचना चाहिए कि क्या दस्तावेज पर विधिवत मुहर लगी है और क्या यह एक ऐसा दस्तावेज है जो अनिवार्य रूप से पंजीकृत है।

बी। यदि दस्तावेज़ पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, तो डाक टिकट अधिनियम की धारा 35 उक्त दस्तावेज़ पर कार्रवाई करने से रोकती है। नतीजतन, उसमें मध्यस्थता खंड पर भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसके बाद न्यायालय को स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत दस्तावेज़ को जब्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 और 38 के अंतर्गत प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

ग. यदि दस्तावेज़ पर विधिवत मुहर लगी हुई पाई जाती है, या यदि डी. एफ. आई. टी. स्टाम्प शुल्क और जुर्माना का भुगतान किया जाता है, तो या तो न्यायालय के समक्ष या उससे पहले।

/

[2023] 15 एस सी आर।

कलेक्टर (जैसा कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 49 की धारा 35 में विचार किया गया है), और अवज्ञा शुल्क के संदर्भ में दोष ठीक हो जाता है, न्यायालय दस्तावेज़ को विधिवत मुद्रांकित मान सकती है।

200. एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (उपरोक्त) ने अदालतों को धारा 11 के स्तर पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत दस्तावेज़ को जब्त करने की अनुज्ञात। इस प्रकार, न्यायालयों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने से पहले पूर्व-मध्यस्थता स्तर पर हस्तक्षेप करने के लिए अनिवार्य किया गया था। एस. एम. एस. चाय संपदा (ऊपर) 2011 में तय की गई थी। उस समय, पटेल इंजीनियरिंग (ऊपर) और बोघरा पॉलीफैब (ऊपर) ने निर्णय लिया, जिसमें कहा गया था कि रेफरल अदालतों के पास मध्यस्थता समझौतों के अस्तित्व और वैधता सहित बड़ी संख्या में प्रारंभिक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए

व्यापक शक्तियां थीं। जैसा कि उपरोक्त खंडों में चर्चा की गई है, भारत के विधि आयोग ने न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे को सीमित करने की दृष्टि से धारा 8 और 11 में संशोधन की सिफारिश की है।

“ ऐसी स्थितियों में जहां न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण यह मानता है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या अमान्य है। ”

201. भारत के विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, संसद ने धारा 11 (6 ए) को शामिल किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित था। खंड 11 (6 ए) पर विधायी टिप्पणी में कहा गया है

कि धारा (6 ए) को यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उप-धारा (4) से (6) के अंतर्गत आवेदनों पर विचार करते समय मध्यस्थता समझौते की जांच करने के लिए आश्वस्त नहीं होगा।” अधिक

महत्वपूर्ण रूप से, उक्त प्रावधान में एक गैर-अस्थाई खंड है जो कहता है:

“किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद। ”

202. एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम आफताब सिंह, 170 यह न्यायालय था

धारा 8 के उद्देश्य की जांच करना जिसमें धारा 11 (6 ए) में निहित एक समान गैर-अस्थाई खंड शामिल था। इस न्यायालय ने धारा 8 में निहित गैर-अस्थाई खंड के उद्देश्य को निम्नलिखित शब्दों में समझाया: “52. [...] धारा 8 में संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्द "उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद" मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में न्यायिक प्राधिकरण के हस्तक्षेप को कम करने के इरादे से थे। संशोधित धारा 8 (1) के अनुसार,

170 (2019) 12 एससीसी 751 1185

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1186

न्यायिक प्राधिकरण को केवल इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या पक्षों के पास एक वैध मध्यस्थता समझौता है?” न्यायालय पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने से तब तक इनकार नहीं कर सकता जब तक कि वह यह नहीं मानता कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है। संशोधित प्रावधान, इस प्रकार, न्यायिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप को केवल एक पहलू तक सीमित करता है अर्थात् न्यायिक प्राधिकरण द्वारा संदर्भित करने से इनकार करना केवल एक पहलू पर निर्भर करता है, जब यह मानता है कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है। ”

203. एम्मार एम. जी. एफ. लैंड (उपर्युक्त) में, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 8 (1) में निर्दिष्ट "किसी भी निर्णय के बावजूद" अभिव्यक्ति उन न्यायिक उदाहरणों से संबंधित है जो धारा 8 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए न्यायिक प्राधिकरण के विवेकाधिकार और शक्ति को समझाते हैं। इसी तरह, धारा 11 (6 ए) का उद्देश्य मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना था। तदनुसार, धारा 11 (6 ए) में निहित गैर-अस्थाई खंड उन न्यायिक उदाहरणों से संबंधित है जो धारा 11 के स्तर पर मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता की जांच करने और हस्तक्षेप करने के लिए रेफरल अदालतों के विवेकाधिकार और शक्ति में तल्लीन थे। इसमें इस तथ्य पर विचार करते हुए एस. एम. एस. टी. एस्टेट्स (उपरोक्त) शामिल हैं कि इसने रेफरल न्यायालय को मध्यस्थता समझौते वाले अनस्टैम्ड इंस्ट्रुमेंट को जब्त करके मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायिक रूप से हस्तक्षेप करने का आदेश दिया था। इसलिए, हमारा मानना है कि धारा 11 (6 ए) ने भी एस. एम. एस. चाय संपदाओं (उपरोक्त) के आधार को इस हद तक विधायी रूप से बदल दिया कि यह धारा 11 के स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप से संबंधित है।

ii. गारवेयर वॉल रॉप्स

204. गरवारे वॉल रोप्स (उपरोक्त) में, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ को एक अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड के प्रभाव को तय करने के लिए कहा गया था, जिस पर मुहर लगाने की आवश्यकता होती है। चूंकि एस. एम. एस. चाय संपदा (उपरोक्त) का निर्णय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6 ए) के लागू होने से पहले किया गया था, इसलिए इस न्यायालय के समक्ष एक और प्रासंगिक मुद्दा यह था कि क्या इस प्रावधान के लागू होने से एस. एम. एस. चाय संपदा (उपर्युक्त) में निर्णय के लिए आधार इस हद तक हटा दिया गया था कि धारा 11 के अंतर्गत रेफरल अदालत द्वारा नहीं बल्कि मध्यस्थ द्वारा एक बिना मुहर वाले दस्तावेज को जब्त किया जा सकता था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 11 (6 ए) के अंतर्गत रेफरल अदालत स्टाम्प अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों से बंधी होगी ताकि स्टाम्प रहित उपकरण की जांच और उसे जब्त किया जा सके। यह आगे देखा गया कि चूंकि स्टाम्प अधिनियम लागू होता है

/

[2023] 15 एस सी आर।

समग्र रूप से, ऐसे लिखत में निहित मध्यस्थता खंड को विभाजित करना और इसे एक स्वतंत्र अस्तित्व देना संभव नहीं था।

205. इस न्यायालय ने गरवारे वॉल रोप्स (ऊपर) में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 में निहित "अस्तित्व" शब्द के उद्देश्य का आगे विश्लेषण किया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक अनस्टैम्ड इंस्ट्रुमेंट में निहित एक मध्यस्थता समझौता विधि में मौजूद नहीं

होगा। प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे निकाला गया है: “22. जब कोई मध्यस्थता खंड “किसी अनुबंध में” निहित होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि समझौता केवल तभी अनुबंध बन जाता है जब यह विधि द्वारा लागू किया जा सके। हमने देखा है कि कैसे, स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत, एक समझौता एक अनुबंध नहीं बन जाता है, अर्थात्, यह विधि में लागू करने योग्य नहीं है, जब तक कि उस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई जाती है। इसलिए, धारा 11 (6-ए) को जब 1996 के अधिनियम की धारा 7 (2) और अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (एच) के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी समझौते में मध्यस्थता खंड तब मौजूद नहीं होगा जब वह विधि द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यह भी एक संकेतक है कि धारा 11 (6-ए) के संशोधन ने किसी भी तरह से एस. एम. एस. टी एस्टेट को प्रभावित नहीं किया है।”

206. इसके अलावा, इस न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (13) का उल्लेख किया जो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए किसी भी आवेदन के निपटारे के लिए साठ दिनों की समय सीमा प्रदान करता है। धारा 11 (13) को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्टाम्प अधिनियम और मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है। तदनुसार, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार जब उच्च न्यायालय धारा 11 के स्तर पर एक अनस्टैम्ड लिखत को जब्त कर लेता है, तो वह इसे महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारी को सौंप देगा, जिसका निर्णय उन चालीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा, जिन दिनों से ऐसे प्राधिकारी को लिखत प्राप्त होती है। एक बार स्टाम्प शुल्क और जुर्माने का भुगतान हो जाने के बाद, उच्च न्यायालय धारा 11 के आवेदन की सुनवाई और निपटान के लिए तेजी से आगे बढ़ सकता है।

207. गरवारे वॉल रोप्स (ऊपर) में इस न्यायालय के निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: सबसे पहले, एस. एम. एस. टी. एस्टेट्स (उपरोक्त) को निरस्त करने का कोई विधायी इरादा नहीं था क्योंकि न तो 2015 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण और न ही भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट, 2014 में इसका उल्लेख है; दूसरा, धारा 11 के चरण में रेफरल न्यायालय केवल स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बना रही है और पक्षों के बीच किसी भी प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय नहीं ले रही है; तीसरा, पृथक्करण अनुमान केवल सीमित उद्देश्यों के लिए लागू किया जा सकता है। चूंकि स्टाम्प अधिनियम समग्र रूप से लिखत पर लागू होता है, इसलिए मध्यस्थता 1187 को विभाजित करना संभव नहीं है।

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौते [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1188

ऐसे समझौते में निहित खंड; और चौथा, एक अनस्टैम्ड अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड मौजूद नहीं होगा, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धारा 11 (6 ए) ने एस. एम. एस. टी. एस्टेट्स (उपरोक्त) को खारिज नहीं किया है।

208. 2015 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

“(ग) मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन का निपटारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा और साठ दिनों की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

“(iv) यह प्रावधान करना कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करेगा, न कि अन्य मुद्दों की।” 209. उपरोक्त उद्धरण इंगित करता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के चरण में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय “प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करेगा न कि अन्य मुद्दों की।” ये अन्य मुद्दे न केवल मध्यस्थता समझौते की वैधता से संबंधित हैं, बल्कि इसमें कोई अन्य मुद्दे भी शामिल हैं जो मध्यस्थता कार्यवाही में अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप का परिणाम हैं। तदनुसार, “अन्य मुद्दों” में धारा 8 या धारा 11 के चरण में रेफरल न्यायालय द्वारा एक बिना मुहर वाले दस्तावेज की जांच और ज़ब्त करना भी शामिल है। स्टाम्प एक्टनि सिडाव मोनअंतर्गत आनस्टाम्प खालामनाय खाखिनि आनजाद, जब्द खालामनाय आरो बेजों सोमोन्दो लाखिनायनि फारिखान्थिआ मोनअंतर्गत सम-सिमा गोनां फारिखान्थि नडा, आरो बेनिखायनो सालिसगिरिफोरनि गोख्रै आरो सम-सिमा गोनां थिसनथाइखौ रोखा खालामनो थाखाय आरबिट्रेशन एक्टनि मुख ‘जानाय थांखिजों गोरोबनाय नडा। इसलिए, भले ही भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट या 2015 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण विशिष्ट रूप से एस. एम. एस. टी एस्टेट (उपरोक्त) का उल्लेख नहीं करता है, फिर भी यह विधि की स्थिति में कोई अंतर नहीं करता है जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है।

210. गरवारे बॉल रोप्स (ऊपर) पटेल इंजीनियरिंग (ऊपर) पर निर्भर था

यह अवलोकन करना कि “प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार करना कठिन पंथ है कि धारा 16 यह स्पष्ट करती है कि एक मध्यस्थता समझौते का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, और 1996 के अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय इसे लागू किया जाना चाहिए।” इस अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पृथकता अनुमान को एक अनस्टैम्प किए गए उपकरण के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्टाम्प अधिनियम समग्र रूप से उपकरण पर लागू होता है। जैसा कि पूर्ववर्ती खंडों में चर्चा की गई है, पृथकता अनुमान एक मध्यस्थता की वैधता सुनिश्चित करता है।

/

[2023] 15 एस सी आर।

अंतर्निहित अनुबंध की अयोग्यता, अवैधता या गैर-अस्तित्व के बावजूद समझौता।

211. धारा 16 के अंतर्गत एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार का दायरा व्यापक है क्योंकि यह एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता से संबंधित मुद्दों से निपट सकता है। एन. एन. ग्लोबल 2 (उपरोक्त) में अपनी असहमतिपूर्ण राय में, न्यायमूर्ति रॉय ने सही ढंग से कहा है कि चूंकि "[एस] एक्ट 16 विशिष्ट रूप से संबंधित है

अस्तित्व और वैधता दोनों जबकि धारा 11 केवल अस्तित्व से संबंधित है, पूर्व को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।" यह अवलोकन इसके साथ मेल खाता है

मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायालयों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम का घोषित लक्ष्य। 2015 के संशोधन अधिनियम के बाद रेफरल अदालतों को केवल प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता का निर्धारण करने की आवश्यकता होती है। इस तरह के प्रथम दृष्टया निर्धारण का आधार इस तथ्य में निहित है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास बाद में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के मुद्दे पर निर्णय लेने की क्षमता होगी। इसलिए, पृथक्करण की धारणा रेफरल चरण में लागू होती है।

212. इंटरकांटीनेंटल होटल्स ग्रुप (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम वाटरलाइन

होटल्स (पी) लिमिटेड, 171 धारा 11 के आवेदन में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मुद्दा यह था: क्या न्यायालय एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ सकती है जब अंतर्निहित अनुबंध पर गलत तरीके से मुहर लगी हो। उस में

मामले में, यह देखा गया कि हालांकि "स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया है, क्या यह अनुचित या उचित है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बाद के चरण में दिया जा सकता है क्योंकि यह न्यायालय धारा 11 (6) के अंतर्गत इस पहलू की समीक्षा या जांच नहीं कर सकता है। "

213. पूर्ववर्ती खंडों में चर्चा में यह माना गया है कि किसी उपकरण की गैर-मुद्रांकन या असंक्रमित मुद्रांकन इसे अमान्य या अस्तित्वहीन नहीं बनाती है। इसलिए, गरवारे वॉल रोप्स (ऊपर दिए गए) के पैराग्राफ 22 और 29, जिसमें कहा गया था कि एक बिना मुहर वाले या असंवेदनशील वैज्ञानिक रूप से मुहर वाले अनुबंध में निहित एक मध्यस्थता समझौता विधि में मौजूद नहीं होगा, विधि की सही स्थिति को निर्धारित नहीं करता है।

के *। भारत के मुख्य न्यायाधीश योजना, **1996** द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति

214. एन एन ग्लोबल 2 (ऊपर) में, बहुमत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश योजना, 1996 द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति पर विचार किया। 1996 की योजना का 172 पैरा 2 इस प्रकार है:

* एड। ध्यान दें: भाग के 171 (2022) 7 एस. सी. सी. 662 172 "1996 योजना"

इन आरई:मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1190 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

“2. अनुरोध प्रस्तुत करना।- धारा 11 की उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध लिखित रूप में किया जाएगा और इसके साथ-साथ -

(क) मूल मध्यस्थता समझौता या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि; 1996 की योजना में प्रावधान है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए धारा 11 के अंतर्गत एक आवेदन के साथ मूल मध्यस्थता समझौता या विधिवत प्रमाणित प्रतियां होंगी।

215. एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (उपरोक्त) में, यह देखा गया था कि मध्यस्थता खंड वाले समझौते/अनुबंध/साधन की एक प्रमाणित प्रति को मूल पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क का खुलासा करना चाहिए। एन एन ग्लोबल 2 (उपरोक्त) ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है। उस मामले में, इस न्यायालय ने 1996 की योजना के पैराग्राफ 5 का भी उल्लेख किया जो मुख्य न्यायाधीश या पैरा 3 के अंतर्गत उनके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्थान को योजना के अंतर्गत अनुरोध करने वाले पक्ष से आगे की जानकारी या स्पष्टीकरण लेने की अनुमति देता है। नतीजतन, यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 11 के अंतर्गत एक आवेदन पर विचार करने वाला न्यायाधीश स्टाम्प शुल्क के भुगतान के संबंध में और स्पष्टीकरण या जानकारी प्राप्त कर सकता है ताकि इसमें निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

एस. एम. एस. चाय संपदा (ऊपर)।

216. एन एन ग्लोबल 2 (ऊपर) दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को भी संदर्भित करता है।

जुपुडी केशव राव बनाम पुलवर्थी वेंकट सुब्बाराव 173 में इस न्यायालय का

जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 किसी बिना स्टाम्प वाले या बिना ज्ञान के स्टाम्प वाले उपकरण के किसी भी द्वितीयक साक्ष्य को साक्ष्य में अस्वीकार्य बनाती है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि इस तरह के दस्तावेज के किसी भी गौण साक्ष्य पर धारा 35 के संदर्भ में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसके बाद ए.

हरिओम अग्रवाल बनाम प्रकाश चंद मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

मालवीय 174 ने जुपुडी केशव राव (उपरोक्त) की पुष्टि करते हुए कहा कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 और 35 का संबंध उपकरण की किसी भी प्रति से नहीं है। संबंधित अनुच्छेद नीचे निकाला गया है:

“10. इस न्यायालय के निर्णयों और अधिनियम की धारा 33, 35 और 2 (14) के एक सादे पठन से यह स्पष्ट है कि एक उपकरण जिस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है, उसे जब्त किया जा सकता है और जब ऐसे उपकरण के लिए आवश्यक शुल्क और जुर्माना का भुगतान किया गया है तो इसे लिया जा सकता है।

/

[2023] 15 एस सी आर।

स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत साक्ष्य। धारा 33 या 35 लिखत की किसी भी प्रति से संबंधित नहीं हैं और पक्ष को केवल उस दस्तावेज़ पर भरोसा करने की अनुज्ञात जा सकती है जो धारा 2 (14) के अर्थ के भीतर एक साधन है। स्टाम्प एक्ट के उद्देश्यों के लिए दस्तावेज़ की प्रति को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधि अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि दस्तावेज़ की प्रति को ज़ब्त करके मान्य नहीं किया जा सकता है और इसे स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत माध्यमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। "

217. एक मध्यस्थता समझौते या इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि को अमान्य या अप्रवर्तनीय नहीं माना जाता है क्योंकि उस पर बिना मोहर लगी होती है या उस पर वैज्ञानिक रूप से मुहर नहीं लगी होती है। हम तदनुसार स्पष्ट करते हैं कि जुपुडी केशव राव (ऊपर) और हरिओम अग्रवाल (ऊपर) में निर्धारित विधि की स्थिति धारा 11 के चरण (साथ ही धारा 8 के चरण) में एक रेफरल न्यायालय को मध्यस्थता समझौते की प्रमाणित प्रतिलिपि पर कार्य करने और पक्षकारों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजने से बाधित नहीं कर सकती है। 218. पूर्ववर्ती खंडों में चर्चा से संकेत मिलता है कि धारा 11 के स्तर पर रेफरल न्यायालय को बिना मोहर वाले या बिना वैज्ञानिक रूप से मुहर वाले दस्तावेज़ की जांच या ज़ब्त नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण के लिए छोड़ देना चाहिए। जब कोई पक्ष मध्यस्थता समझौता या उसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करता है, तो रेफरल न्यायालय को केवल यह जांचना होता है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं। धारा 11 के अंतर्गत रेफरल न्यायालय को यह जांचने की आवश्यकता नहीं है कि क्या समझौते/उपकरण/अनुबंध की एक प्रमाणित प्रतिलिपि मूल पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान के तथ्य का खुलासा करती है। तदनुसार, हम मानते हैं कि एस. एम. एस. टी एस्टेट (ऊपर) में इस न्यायालय की धारणा, जैसा कि एन. एन. ग्लोबल 2 (ऊपर) में दोहराया गया है, अब विधि में मान्य नहीं है।

एल *। विद्या द्रोलिया मुद्रांकन के मुद्दे से नहीं निपटती हैं।

219. इन कार्यवाहियों की उत्पत्ति एन एन ग्लोबल 1 (ऊपर) में निहित है जो विद्या द्रोलिया (ऊपर) में तथ्य की शुद्धता पर संदेह करती है। एन. एन. ग्लोबल 1 (ऊपर) ने विद्या द्रोलिया (ऊपर) में समन्वय पीठ के पैराग्राफ 146 और 147 में लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर संदेह किया, जहां तीन-न्यायाधीश

बेंच ने गरवारे बॉल रोप (ऊपर) पर भरोसा किया।

220. पैराग्राफ 146 में, यह न्यायालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या धारा 11 (6 ए) में निहित "अस्तित्व" अभिव्यक्ति भी मध्यस्थता समझौते की वैधता का अनुमान लगाती है।

न्यायालय ने इस प्रस्ताव का यह कहते हुए जवाब दिया कि एक मध्यस्थता समझौता केवल "मौजूद" है।

* एड। ध्यान दें: भाग एल 1191

इन आरई: मध्यस्थता और समन्वय अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1192 के अंतर्गत मध्यस्थता समझौतों के बीच हस्तक्षेप

जब यह वैध और लागू करने योग्य हो। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का अर्थ एक मध्यस्थता समझौता है जो मध्यस्थता अधिनियम और अनुबंध अधिनियम दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाद के पैराग्राफ में, इस न्यायालय ने अपने निष्कर्ष को मजबूत करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में, इसने गरवारे सहित इस न्यायालय के विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख किया

दीवार की रस्सी (ऊपर)।

221. पैराग्राफ 147.1 स्पष्ट करता है कि यह केवल एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के बीच संबंध स्थापित करने के उद्देश्यों के लिए गारवेयर वॉल रोप्स (ऊपर) का उल्लेख कर रहा है। संबंधित अनुच्छेद

गारवेयर वॉल रोप्स (ऊपर) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संदर्भित करता है। हुंडई इंग। & कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड **175** जिसमें मध्यस्थता खंड

यह केवल तभी शुरू किया गया था जब किसी एक पक्ष ने अपने दायित्व को स्वीकार या स्वीकार किया हो। उस मामले में, चूंकि संबंधित पक्ष (बीमाकर्ता) ने अपने दायित्व को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए न्यायालय ने माना कि मध्यस्थता खंड विधि में मौजूद नहीं था, हालांकि यह मौजूद था।

वास्तव में। गारवेयर वॉल रोप्स (ऊपर) हुंडई इंग पर निर्भर था। (ऊपर) से

गलत होने के बावजूद, यह अभिनिर्धारित करें कि एक अनस्टैम्पड समझौता विधि के मामले के रूप में तब तक मौजूद नहीं होगा जब तक कि अंतर्निहित लिखत पर विधिवत मुहर नहीं लग जाती। हमारी राय है कि विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) ने किसी भी तरह से मध्यस्थता समझौते पर अंतर्निहित अनुबंध के प्रभाव को निर्धारित नहीं किया है। इसने केवल अपनी व्याख्या को पुष्ट करने के लिए गरवारे वॉल रोप्स (उपरोक्त) का उल्लेख किया कि एक मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है यदि यह अमान्य या अवैध है, जिसे इस निर्णय के उपरोक्त खंडों में स्पष्ट किया गया है।

222. विशेष रूप से, कैरियर संस्थान में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ

एजुकेशनल सोसाइटी बनाम ओम श्री ठाकुरजी एजुकेशनल सोसाइटी 176 ने स्पष्ट किया कि विद्या द्रोलिया (ऊपर) ने गरवारे वॉल रोप्स (ऊपर) का उल्लेख किया है।

केवल 'अस्तित्व' शब्द की व्याख्या करने के लिए, और क्या एक 'अमान्य' मध्यस्थता

समझौते को अस्तित्व में कहा जा सकता है "दो-न्यायाधीशों की पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) ने मध्यस्थता खंड पर अंतर्निहित अनुबंध के प्रभाव के मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

“3. विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के फैसले में बिना मोहर वाले या अधूरे व्यापार के मुद्दे की जांच और निर्णय नहीं लिया गया।

175 (2018) 17 एस. सी. सी. 607

176 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 586

/

[2023] 15 एस सी आर।

मध्यस्थता समझौते पर अंतर्निहित अनुबंध पर मुहर लगा दी। चूंकि इस मुद्दे और प्रश्न का निर्णय विद्या द्रोलिया (ऊपर) में नहीं किया गया है, इसलिए निर्णय इस प्रश्न पर एक मिसाल नहीं है। "

223. हम करियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी (उपरोक्त) में इन टिप्पणियों से सहमत हैं। विद्या द्रोलिया (ऊपर) ने किसी मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता पर बिना मोहर वाले या बिना वैज्ञानिक रूप से मुहर वाले दस्तावेज के प्रभाव के मुद्दे पर विचार नहीं किया। इसलिए, विद्या द्रोलिया (ऊपर) में तर्क इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि गवरि वॉल रोप्स (ऊपर) का निर्णय या तो जांच के पहलू पर और मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में बिना मोहर वाले या बिना मोहर वाले साधन को जब्त करने के बारे में, या बिना मोहर वाले या बिना मोहर वाले अंतर्निहित अनुबंध में निहित मध्यस्थता समझौते की वैधता के बारे में सही निर्णय लिया गया था।

एम *। निष्कर्ष

224. इस निर्णय में प्राप्त निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है: ए। जिन समझौतों पर मुहर नहीं लगी है या अपर्याप्त रूप से मुहर लगी है, वे डाक टिकट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हैं। इस तरह के समझौतों को शुरू से ही अमान्य या अप्रवर्तनीय नहीं माना जाता है। बी. गैर-मुद्रांकन या अपर्याप्त मुद्रांकन एक इलाज योग्य दोष है;

ग. मुद्रांकन के बारे में आपत्ति मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के अंतर्गत निर्धारण के लिए नहीं आती है। संबंधित न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौता मौजूद है। घ. समझौते पर मुहर लगाने के संबंध में कोई भी आपत्ति मध्यस्थता न्यायाधिकरण के दायरे में आती है; और

ड. एन. एन. ग्लोबल 2 (ऊपर) और एस. एम. एस. टी एस्टेट (ऊपर) में निर्णय को खारिज कर दिया गया है। गरवारे वॉल रोप्स (ऊपर) के पैराग्राफ 22 और 29 को उस हद तक खारिज कर दिया गया है।

225. रजिस्ट्री को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष मामलों को रखने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से प्रशासनिक निर्देश लेने का निर्देश दिया जाता है।

* एड। ध्यान दें: भाग एम 1193

इन आरई: आर्बिट्रेशन अंतर्गत कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 [संजीव खन्ना, जे.] 1194 सुप्रीम न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

संजीव खन्ना, जे।

मैं भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा वर्तमान संदर्भ में विचार के लिए उत्पन्न विभिन्न रूपों की विस्तृत व्याख्या में व्यक्त किए गए विचार से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ। उसी के पूरक के रूप में, मैं अंतिम निष्कर्ष के लिए अतिरिक्त औचित्य प्रदान करना चाहूंगा।, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899-1 की धारा 35 के संदर्भ में साक्ष्य में अस्वीकार्य मुद्रांकित या कृत्रिम रूप से मुद्रांकित उपकरणों को शून्य और शून्य नहीं माना जाता है; अंतर्निहित अनुबंध के अंडर-स्टाम्पिंग या नॉन-स्टाम्पिंग के बारे में आपत्ति का कोई असर नहीं होगा जब प्रथम दृष्टया परीक्षण, "मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व", अदालतों द्वारा मध्यस्थता की धारा 8 2 या 11 3 के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेते समय लागू किया जाता है।

1 संक्षेप में, "द स्टाम्प एक्ट"

2 8. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां एक मध्यस्थता समझौता है।—

(1) एक न्यायिक प्राधिकरण, जिसके समक्ष किसी ऐसे मामले में कार्रवाई की जाती है जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, यदि मध्यस्थता समझौते का कोई पक्षकार या उसके माध्यम से या उसके अंतर्गत दावा करने वाला कोई व्यक्ति, विवाद के सार पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करने की तारीख के बाद लागू नहीं होता है, तो, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी अदालत के किसी भी निर्णय, डिक्ली या आदेश के बावजूद, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए तब तक संदर्भित करता है जब तक कि वह यह नहीं मानता है कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मूल मध्यस्थता समझौते या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रतियों के साथ न हो। बशर्ते कि जहां मूल मध्यस्थता समझौता या उसकी प्रमाणित प्रतियां उप-धारा (1) के अंतर्गत मध्यस्थता के संदर्भ के लिए आवेदन करने वाले पक्ष के पास उपलब्ध नहीं हैं, और उक्त समझौते या प्रमाणित प्रतियों को उस समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा बरकरार रखा जाता है, तो इस तरह आवेदन करने वाला पक्ष मध्यस्थता समझौते की एक प्रति और न्यायालय से अनुरोध करने वाली याचिका के साथ ऐसा आवेदन करेगा कि वह दूसरे पक्ष से उस न्यायालय के समक्ष मूल मध्यस्थता समझौते या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रतियों को पेश करने के लिए कहे। (3) इसके बावजूद कि उप-धारा (1) के अंतर्गत एक आवेदन किया गया है और यह मुद्दा न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, एक मध्यस्थता शुरू की जा सकती है या जारी रखी जा सकती है और एक मध्यस्थ पुरस्कार दिया जा सकता है।

3 11. मध्यस्थों की नियुक्ति।—(1) किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति मध्यस्थ हो सकता है, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए।

(2) उप-धारा (6) के अधीन, पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए निशुल्क हैं।

(3) तीन मध्यस्थों के साथ मध्यस्थता में, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी समझौते में विफल रहने पर, प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और दो नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे।

(4) यदि उप धारा (3) में नियुक्ति प्रक्रिया लागू होती है और -

(क) एक पक्ष दूसरे पक्ष से ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर एक मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है; या

(बी) दो नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं, नियुक्ति एक के अनुरोध पर की जाएगी

[उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था] द्वारा;

(5) एकल मध्यस्थ के साथ मध्यस्थता में, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी समझौते में विफल रहने पर, यदि पक्षकार दूसरे पक्षकार से एक पक्षकार द्वारा अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तो नियुक्ति, किसी पक्षकार के अनुरोध पर, उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी।

(6) जहां, पक्षों द्वारा सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत, (ए) एक पक्ष उस प्रक्रिया के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है; या

((ख) पक्षकार या दो नियुक्त मध्यस्थ उस प्रक्रिया के अंतर्गत उनसे अपेक्षित समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं; या

(ग) एक व्यक्ति, एक संस्था सहित, उस प्रक्रिया के अंतर्गत उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को करने में विफल रहता है, एक पक्ष उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति या संस्थान से आवश्यक उपाय करने का अनुरोध कर सकता है, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया पर समझौता नियुक्ति को सुरक्षित करने के लिए अन्य साधन प्रदान नहीं करता है।

(6 क) उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय, उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अंतर्गत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच को स्वीकार नहीं करेगा।

(6(ख) उच्चतम न्यायालय या, यथास्थिति, उच्च न्यायालय द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या संस्था के पदनाम को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक शक्ति के प्रत्यायोजन के रूप में नहीं माना जाएगा।

(7) उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) द्वारा उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था को सौंपे गए मामले पर निर्णय शून्य है और ऐसे निर्णय के खिलाफ पेटेंट पत्र अपील सहित कोई अपील नहीं होगी।

(8) उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था, मध्यस्थ की नियुक्ति से पहले, धारा 12 की उप-धारा (1) के संदर्भ में संभावित मध्यस्थ से लिखित रूप में प्रकटीकरण की मांग करेगा और -

(क) पक्षकारों के समझौते द्वारा मध्यस्थ के लिए आवश्यक कोई भी योग्यता; और (ख) प्रकटीकरण की सामग्री और अन्य विचार जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति को सुरक्षित करने की संभावना रखते हैं।

(9) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में एकमात्र या तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय या उस न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था उन पक्षों की राष्ट्रीयताओं के अलावा किसी अन्य राष्ट्रीयता के मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकता है जहां पक्ष अलग-अलग राष्ट्रीयताओं से संबंधित हैं।

(10) उच्चतम न्यायालय या, यथास्थिति, उच्च न्यायालय ऐसी योजना बना सकता है जो उक्त न्यायालय को उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) द्वारा सौंपे गए मामलों से निपटने के लिए उचित लगे।

(11) जहां उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अंतर्गत अलग-अलग उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों या उनके नामित, अलग-अलग उच्च न्यायालयों या उनके नामितों से एक से अधिक अनुरोध किए गए हैं, वहां संबंधित उप-धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय या उसका नामित व्यक्ति जिसे पहली बार अनुरोध किया गया है, अकेले सक्षम 1195 होगा।

इन आरई:आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 [संजीव खन्ना, जे.] 1196 के अंतर्गत आर्बिट्रेशन समझौतों के बीच हस्तक्षेप

और सुलह अधिनियम, 1996 4; और अंतर्निहित समझौते पर असंवैधानिक मुहर लगाने के बारे में आपत्ति की जांच की जा सकती है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। तदनुसार, एन. एन. ग्लोबल में संविधान पीठ का बहुमत निर्णय

मर्केटाइल (पी) लिमिटेड बनाम इंडो यूनिफ्लेम लिमिटेड 5 को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

2. 'डी. इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899' शीर्षक के अंतर्गत माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित निर्णय, स्टाम्प एक्ट और उसके द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के बारे में समग्र दृष्टिकोण देता है। यह स्टाम्प अधिनियम की धारा 33, 35 और 36 का भी उल्लेख करता है, जिसके बारे में मैं विस्तार से बताना चाहूंगा।

3. डाक टिकट अधिनियम की धारा 33 और 35 को संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“33. उपकरणों की जाँच और ज़ब्त करना।— (1) प्रत्येक

विधि द्वारा या पक्षों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति, और सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति, पुलिस के एक अधिकारी को छोड़कर, जिसके सामने कोई भी उपकरण, जो उसकी राय में, कर्तव्य के साथ, प्रस्तुत किया जाता है या उसके निष्पादन में आता है।

अनुरोध पर निर्णय लेना।

(12) (क) जहां उप-धारा (4), (5), (6), (7), (8) और उप-धारा (10) में निर्दिष्ट मामले किसी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में उत्पन्न होते हैं, वहां उन उप-धाराओं में "उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय" के संदर्भ का अर्थ "सर्वोच्च न्यायालय" के संदर्भ के रूप में किया जाएगा; और

(ख) जहां उप-धारा (4), (5), (6), (8) और उप-धारा (10) में निर्दिष्ट मामले किसी अन्य मध्यस्थता में उत्पन्न होते हैं, वहां उन उप-धाराओं में "उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय" के संदर्भ का अर्थ उस "उच्च न्यायालय" के संदर्भ के रूप में किया जाएगा, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ई) में निर्दिष्ट प्रमुख सिविल न्यायालय स्थित है, और जहां उच्च न्यायालय स्वयं उस खंड में निर्दिष्ट न्यायालय है, उस उच्च न्यायालय के लिए।

(13) इस धारा के अंतर्गत मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन का उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था, जैसा भी मामला हो, द्वारा यथासंभव शीघ्रता से निपटान किया जाएगा और विरोधी पक्ष को नोटिस की सेवा की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर मामले का निपटान करने का प्रयास किया जाएगा।

(14) माध्यस्थ न्यायाधिकरण की फीस के निर्धारण और माध्यस्थ न्यायाधिकरण को इसके भुगतान के तरीके के उद्देश्य से, उच्च न्यायालय चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियम बना सकता है जो आवश्यक हों। स्पष्टीकरण.—संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यह उप-धारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और मध्यस्थता (अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा) में लागू नहीं होगी, ऐसे मामलों में जहां पक्ष एक मध्यस्थ संस्था के नियमों के अनुसार शुल्क के निर्धारण के लिए सहमत हुए हैं।

4 संक्षेप में, "मध्यस्थता अधिनियम" 15 (2023) 7 एससीसी 1.

/

[2023] 15 एस सी आर।

कार्य, यदि उसे यह प्रतीत होता है कि ऐसे उपकरण पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, तो उसे जब्त कर लेगा।

(2) उस उद्देश्य के लिए ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपने समक्ष इस तरह से प्रभार्य और इस तरह से प्रस्तुत या आने वाले प्रत्येक उपकरण की जांच करेगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उस पर भारत में लागू विधि द्वारा आवश्यक मूल्य और विवरण की मुहर लगी है जब ऐसा उपकरण निष्पादित किया गया था या पहली बार निष्पादित किया गया था:

बशर्ते कि -

(क) इसमें निहित किसी भी बात के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि किसी आपराधिक न्यायालय के किसी मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश से दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अध्याय XII या अध्याय XXXVI के अंतर्गत कार्यवाही के अलावा किसी अन्य कार्यवाही के दौरान उसके सामने आने वाले किसी भी दस्तावेज की जांच करने या जब्त करने की आवश्यकता है, यदि वह ऐसा करने के लिए ऐसा नहीं समझता है।

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में, इस धारा के अंतर्गत किसी भी दस्तावेज की जांच करने और उसे जप्त करने का कर्तव्य ऐसे अधिकारी को सौंपा जा सकता है जिसे न्यायालय इस संबंध में नियुक्त करता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, संदेह के मामलों में -

(क) राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि कौन से अधिकारी सार्वजनिक अधिकारी माने जाएंगे; और

(ख) राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि सार्वजनिक कार्यालयों के प्रभारी व्यक्ति कौन माने जाएंगे। "

xx

xx

xx

35. जिन उपकरणों पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, वे साक्ष्य आदि में अस्वीकार्य हैं।—

कर्तव्य के साथ प्रभार्य किसी भी लिखत को किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसे विधि द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है, या उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा पंजीकृत या प्रमाणित किया जाएगा, जब तक कि ऐसे लिखतों पर विधिवत मुहर नहीं लगाई जाती है:

बशर्ते कि -

(क) ऐसा कोई भी लिखत उस शुल्क के भुगतान पर साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जिसके साथ वह प्रभार्य है या किसी ऐसे उपकरण के मामले में, जिस पर जानबूझकर मुहर लगी हो, उस शुल्क को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि, 1197

इन आरई:आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 [संजीव खन्ना, जे.] 1198 के अंतर्गत आर्बिट्रेशन समझौतों के बीच हस्तक्षेप

एक साथ पांच रुपये के जुर्माने के साथ, या, जब उचित शुल्क या उसके अवज्ञाकारी हिस्से की राशि का दस गुना पांच रुपये से अधिक हो जाता है, तो उस शुल्क या हिस्से के दस गुना के बराबर राशि;

(ख) जहां कोई व्यक्ति जिससे मुहर लगी रसीद की मांग की जा सकती थी, ने एक बिना मुहर वाली रसीद दी है और ऐसी रसीद, यदि मुहर लगी है, तो उसके खिलाफ साक्ष्य में स्वीकार्य होगी, तो ऐसी रसीद को देने वाले व्यक्ति द्वारा एक रुपये के जुर्माने के भुगतान पर उसके खिलाफ साक्ष्य में स्वीकार किया जाएगा।

(ग) जहां किसी भी प्रकार का अनुबंध या समझौता दो या दो से अधिक पत्रों वाले पत्राचार से प्रभावित होता है और किसी भी पत्र पर उचित मुहर होती है, तो अनुबंध या समझौते पर विधिवत मुहर लगी हुई मानी जाएगी।

(घ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अध्याय 12 या अध्याय XXXVI के अंतर्गत कार्यवाही के अलावा, इसमें निहित कुछ भी आपराधिक न्यायालय में किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में किसी भी दस्तावेज के प्रवेश को नहीं रोकेगा।

(ङ) इसमें निहित कुछ भी किसी भी न्यायालय में किसी भी दस्तावेज के प्रवेश को नहीं रोकेगा जब ऐसा दस्तावेज सरकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया है या जहां यह धारा 32 या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान द्वारा प्रदान किए गए कलेक्टर के प्रमाण पत्र को धारण करता है। 4. मुद्रांक अधिनियम की धारा 33 को सावधानीपूर्वक कहा गया है, ताकि इसके दायरे और दायरे का अधिक विस्तार न किया जा सके। यह धारा उस व्यक्ति के समक्ष किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने पर लागू होती है जिसे विधि या पक्षों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है। 6 यह तब भी लागू होता है जब किसी सार्वजनिक कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति के सामने कोई उपकरण पेश किया जाता है। उपकरण का उत्पादन ऐसे व्यक्ति या सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा कार्यों के प्रदर्शन के दौरान होना चाहिए। परंतुक में कहा गया है कि धारा 33 में किसी आपराधिक न्यायालय के किसी मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश से किसी दस्तावेज की जांच या ज़ब्त करने की आवश्यकता नहीं मानी जाएगी, यदि वह ऐसा करना उचित नहीं समझता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय X (D) और अध्याय IX) के अध्याय XII या अध्याय XXXVI के अंतर्गत कार्यवाही को छोड़कर। पुलिस अधिकारी डाक टिकट अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत सार्वजनिक अधिकारी नहीं हैं।

6 इसके बाद 'ऐसे व्यक्ति' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

/

[2023] 15 एस सी आर।

5. धारा 33 की उप-धारा (3) में कहा गया है कि संदेह की स्थिति में राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि किन अधिकारियों को सार्वजनिक अधिकारी माना जाएगा और किसे सार्वजनिक अधिकारियों का प्रभारी व्यक्ति माना जाएगा। 6. धारा 33 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, ऐसा व्यक्ति या सार्वजनिक अधिकारी इस तरह से प्रभार्य और इस तरह से उसके सामने पेश किए गए या आने वाले उपकरण की जांच करेगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उस पर भारत में लागू विधि के अनुसार विधिवत मुहर लगाई गई है जब उपकरण को निष्पादित किया गया था या पहली बार निष्पादित किया गया था।

7. धारा 35 में कहा गया है कि एक उपकरण जिस पर विधिवत मुहर नहीं लगी है और शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं है, उसे विधि द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा। "किसी भी उद्देश्य के लिए" शब्दों का अर्थ है कि उपकरण पर संपार्श्विक उद्देश्य के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उपकरण पर ऐसे व्यक्ति या किसी भी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा कार्रवाई, पंजीकरण या प्रमाणीकरण नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस पर विधिवत मुहर नहीं लगी हो। जिन शब्दों पर कार्रवाई की गई है, वे अधिनियमों या कार्यवाही के संदर्भ में हैं जो इस तरह के कार्यालय या सार्वजनिक कार्यालय के समक्ष हैं, जैसा भी मामला हो। 8. धारा 35 एक ही उपकरण पर विधिवत मुहर लगाने के बाद एक बिना मुहर वाले या कम मुहर वाले उपकरण के प्रवेश की अनुमति देती है। प्रावधान (ए) में आरोप योग्य शुल्क और जुर्माने के भुगतान की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि अपर्याप्त रूप से मुहर लगे उपकरण को साक्ष्य में स्वीकार किया जाए, या उस पर कार्रवाई की जाए, पंजीकृत किया जाए या प्रमाणित किया जाए।

9. स्टाम्प अधिनियम की धारा 40 (1) (बी) में उचित शुल्क के भुगतान का प्रावधान है यदि जब्त किए गए उपकरण पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है। धारा 42 (1) में यह प्रमाणित करने का प्रावधान है कि जब्त किए गए लिखत पर उचित शुल्क का भुगतान किया गया है। धारा 42 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि प्रमाणन के बाद दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार्य होगा, और इसे पंजीकृत किया जा सकता है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है और प्रमाणित किया जा सकता है जैसे कि उस पर विधिवत मुहर लगाई गई हो।

10. धारा 33 और 35 तब लागू नहीं होती है जब कोई लिखत पक्षकारों द्वारा स्वयं प्रस्तुत की जाती है या उस पर कार्रवाई की जाती है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके पास विधि द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, या कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक अधिकारी नहीं है। धारा 33 एक पुलिस अधिकारी को किसी उपकरण की जांच करने और उसे जब्त करने के लिए अधिकृत नहीं करती है, भले ही उस पर ज्ञानपूर्वक मुहर लगी हो। एक मजिस्ट्रेट या एक आपराधिक न्यायालय का न्यायाधीश अपने सामने आने वाले किसी दस्तावेज की जांच या ज़ब्त नहीं कर सकता है, और 1199 पर वैज्ञानिक रूप से मुहर लगी हुई जानकारी को स्वीकार कर सकता है।

इन आरई: आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 [संजीव खन्ना, जे.] 1200 के अंतर्गत आर्बिट्रेशन समझौतों के बीच हस्तक्षेप

दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय X (D) और अध्याय IX) के अध्याय XII या अध्याय XXXVI के अंतर्गत कार्यवाही के अलावा साक्ष्य में लिखत। इस प्रकार, एक ही लिखत स्वीकार्य हो सकती है और एक आपराधिक न्यायालय के समक्ष कार्रवाई की जा सकती है, जबकि एक दीवानी न्यायालय, सार्वजनिक कार्यालय आदि के समक्ष अस्वीकार्य है।

11. धारा 33 और 35 में नकारात्मक शर्तें विनिर्दिष्ट हैं, हालांकि इतनी पूर्ण नहीं हैं कि दस्तावेज़ को विधि में अमान्य बना दिया जाए। एक "शून्य अब आरंभ" उपकरण, जो मृत है, विधि की नजर में कोई भौतिकता नहीं है। यह अधिकार प्रदान या प्रदान नहीं कर सकता है, या दायित्व पैदा नहीं कर सकता है। हालांकि, एक उपकरण जो "अस्वीकार्य" है, विधि में मौजूद है, हालांकि ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, या ऐसे व्यक्ति या सार्वजनिक अधिकारी द्वारा पंजीकृत, प्रमाणित या कार्रवाई की जा सकती है जब तक कि उस पर विधिवत मुहर नहीं लग जाती है। जैसा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ठीक ही कहा है, धारा 35 किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता आदि से संबंधित है न कि अयोग्यता से।

12. डाक टिकट अधिनियम की धारा 36 उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां किसी उपकरण के प्रवेश पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, और पढ़ता है:

"36. उपकरण का प्रवेश जहां पूछताछ नहीं की जानी चाहिए।—कहाँ?

एक लिखत को साक्ष्य में स्वीकार किया गया है, इस तरह के प्रवेश को, धारा 61 में दिए गए प्रावधान के अलावा, उसी वाद या कार्यवाही के किसी भी चरण में इस आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा कि लिखत पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है। "

इस प्रकार, जहां किसी दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है, वहां धारा 61 में दिए गए प्रावधान के अलावा, उसी वाद या कार्यवाही के किसी भी चरण में इस आधार पर कि दस्तावेज़ पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, इस तरह के प्रवेश पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। नतीजतन, जहां एक उपकरण को साक्ष्य में स्वीकार किया गया है, ऐसे उपकरण को जब्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे उसी मुकदमे या कार्यवाही के किसी भी चरण में असंवेदनशील मुद्रांकन के आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जा सकता है।

13. एक उपकरण जो शुरुआत से ही शून्य या शून्य है, केवल सहमति या छूट द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता है, जब तक कि सहमति या छूट अयोग्यता के कारण को पूर्ववत नहीं करती है। दूसरी ओर, स्टाम्प अधिनियम की धारा 36 में छूट, रोक और निहित सहमति के सिद्धांत को शामिल किया गया है। इसके अलावा, स्टाम्प अधिनियम के अनुसार उचित स्टाम्पिंग के बाद, बिना स्टाम्प वाले या असंबद्ध रूप से स्टाम्प किया जाता है

/

[2023] 15 एस सी आर।

उपकरण को साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है, या पंजीकृत किया जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है या ऐसे व्यक्ति या सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

14. यह लंबे समय से विधि की एक मान्यता प्राप्त स्थिति रही है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कई फैसलों में स्वीकार किया गया है, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा।

15. जावेर चंद और अन्य में।V. पुखराज सुराना 7, बहुत पीछे

1961, इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ ने स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 और 36 के बीच परस्पर क्रिया की जांच करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि धारा 36 इस संदर्भ में स्पष्ट है कि जब किसी दस्तावेज़ को साक्ष्य में स्वीकार किया गया है, तो इस तरह के प्रवेश को मुकदमे या कार्यवाही के किसी भी चरण में इस आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जा सकता है कि दस्तावेज़ पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई थी। धारा 36 द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र अपवाद स्टाम्प अधिनियम की धारा 61 द्वारा विचार किए गए मामलों का वर्ग है। धारा 36 किसी अन्य अपवाद को स्वीकार नहीं करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यायालय ने दस्तावेज़ को सबूत में स्वीकार करने का गलत फैसला किया है या नहीं। धारा 35 एक दंडात्मक प्रावधान की प्रकृति में है जिसका दूरगामी प्रभाव है। मुकदमे के पक्षकारों को चौकस रहना होगा और सतर्क रहना होगा ताकि साक्ष्य में स्वीकार किए जाने से पहले किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता को चुनौती दी जा सके।

16. बिहार राज्य बनाम मेसर्स करम चंद थापर एंड ब्रदर्स लिमिटेड 8 में एक निर्णायक न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 35 के अंतर्गत मान्य किया जा सकने वाला दस्तावेज़ केवल मूल है, जब उस पर बिना मुहर लगी हो या उस पर सही तरीके से मुहर लगी हो। एक प्रति को मान्य नहीं किया जा सकता है और उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, हालांकि जहां कई प्रतियां तैयार की जाती हैं और हस्ताक्षर किए जाते हैं और संबंधित पक्षों को भेजे जाते हैं, प्रत्येक एक मूल साधन होगा।

17. जुपुडी केशव राव बनाम पुलवर्थी वेंकट सुब्बाराव और

अन्य 9, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 उन दस्तावेज़ों की स्वीकार्यता से निपटने के लिए अभिप्रेत नहीं है जिन पर स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मुहर लगाने की आवश्यकता है। इसके बाद, यह देखा जाता है:

“13. धारा 35 का पहला अंग स्पष्ट रूप से कर्तव्य के साथ प्रभार्य किसी भी उपकरण को साक्ष्य से बाहर कर देता है जब तक कि उस पर विधिवत मुहर न लग जाए। दूसरा।

7 ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1655 8 ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 110 9 (1971) 1 एससीसी 545।

1201

इन आरई: आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 [संजीव खन्ना, जे.] 1202 के अंतर्गत आर्बिट्रेशन समझौतों के बीच हस्तक्षेप

इसका अंग, जो उपकरण पर कार्रवाई करने से संबंधित है, स्पष्ट रूप से ऐसे उपकरण के किसी भी द्वितीयक साक्ष्य को बंद कर देगा, क्योंकि इस तरह के साक्ष्य को तब प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी जब शुल्क के साथ मूल रूप से स्वीकार्य रूप से आरोपित पर मुहर नहीं लगाई गई थी या जानबूझकर मुहर नहीं लगाई गई थी, यह उस दस्तावेज़ के समान

होगा जिस पर विधि या साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा कार्रवाई की जा रही है। प्रावधान (ए) केवल तभी लागू होता है जब मूल लिखत वास्तव में विधि के समक्ष होती है और दस्तावेज़ पर भरोसा करने की इच्छा रखने वाले पक्ष द्वारा जुर्माने के साथ डाक टिकट में अवज्ञा का भुगतान किया जाता है। स्पष्ट रूप से अप्रकाशित दस्तावेज़ की सामग्री के मौखिक साक्ष्य के रूप में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 द्वारा कवर की गई इसकी प्रति से द्वितीयक साक्ष्य उस परंतुक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा जो प्राधिकरण को दस्तावेज़ के अलावा साक्ष्य में कुछ भी प्राप्त करने का आदेश देता है। धारा 25 किसी लिखत की किसी भी प्रति से संबंधित नहीं है और एक पक्ष को केवल उस दस्तावेज़ पर भरोसा करने की अनुज्ञात जा सकती है जो धारा 35 के उद्देश्य के लिए एक साधन है। “धारा 2 (14) में “लिखत” को प्रत्येक दस्तावेज़ को शामिल करने के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व बनाया जाना, हस्तांतरित किया जाना, सीमित किया जाना, बढ़ाया जाना, समाप्त किया जाना या दर्ज किया जाना है। डाक्यूमेंट की एक प्रति को स्टाम्प एक्ट के उद्देश्य के लिए एक उपकरण के रूप में शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

14. यदि धारा 35 केवल मूल उपकरणों से संबंधित है और धारा 36 की प्रतियां नहीं हैं, तो धारा 36 की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि किसी उपकरण के द्वितीयक साक्ष्य को इसका लाभ मिले। धारा 36 में “एक साधन” शब्दों का वही अर्थ होना चाहिए जो धारा 35 में है। विधायिका केवल उन मामलों में धारा 35 के सख्त प्रावधानों से मुकर गई जहां मूल लिखत को मुकदमे या कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में बिना किसी आपत्ति के साक्ष्य में स्वीकार किया गया था। दूसरे शब्दों में, हालांकि आपत्ति दस्तावेज़ के साथ संलग्न डाक टिकट की असंवेदनशीलता पर आधारित है, एक पक्ष जिसे इसके स्वागत पर आपत्ति करने का अधिकार है, उसे दस्तावेज़ के पहले निविदा के समय ऐसा करना चाहिए। एक बार दस्तावेज़ी साक्ष्य के प्रवेश पर आपत्ति उठाने का समय पारित हो जाने के बाद, बाद के चरण में उसी आधार के आधार पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। लेकिन यह किसी भी तरह से धारा 36 की प्रयोज्यता को किसी ऐसे दस्तावेज़ की सामग्री के प्रमाण में प्रस्तुत या प्रस्तुत किए जाने की मांग किए गए द्वितीयक साक्ष्य पर लागू नहीं करता है, जिस पर बिना मुहर लगी हो या जिस पर वैज्ञानिक रूप से मुहर लगी हो। ”

/

[2023] 15 एस सी आर।

इस निर्णय में यह भी कहा गया है कि दस्तावेज़ की एक प्रति को मान्य नहीं किया जा सकता है। इसने इस उक्ति को खारिज कर दिया कि धारा 36 भी लागू होगी जहां अनुचित रूप से मुहर लगाए गए उपकरण के द्वितीयक साक्ष्य को गलत तरीके से स्वीकार किया गया है।

18. हमीद जोहारन और अन्य बनाम अब्दुल सलाम में

एल. आर. और अन्य 10 द्वारा, इस न्यायालय ने कहा कि स्टाम्प अधिनियम की प्रयोज्यता स्टाम्प अधिनियम की योजना तक ही सीमित है। डाक टिकट अधिनियम प्रकृति में एक वास्तविक कानून होने के कारण, सख्त निर्माण और उदार व्याख्या को लागू करने की आवश्यकता है। धारा 2 (15) में विभाजन की डिक्री शामिल है और धारा 35 सबूत में बिना मुहर वाले या बिना मोहर वाले टिकट को स्वीकार करने या उस पर कार्रवाई करने पर रोक लगाती है। हालाँकि विधि यह निर्धारित नहीं करता है कि लिंग अपील की अवधि निलंबित रहेगी, फिर भी स्टाम्प पेपर प्रस्तुत किया जाता है और उस पर विभाजन डिक्री तैयार की जाती है और न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित होती है। मुद्रांक अधिनियम का पूरा उद्देश्य कुछ देय राशि उपलब्ध कराना और राजस्व एकत्र करना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में काम करने वाले किसी अन्य कानून पर एक ओवरराइडिंग प्रभाव पड़ता है। एक डिक्री की प्रवर्तनीयता स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 का विषय नहीं हो सकती है, न ही सीमा को निलंबन के अंतर्गत कहा जा सकता है। धारा 35 का शीर्षक स्वयं प्रयोज्यता के सीमित क्षेत्र को दर्शाता है।

19. डॉ. चिरंजी लाल (डी) में एल. आर. वी.एलआर द्वारा हरि दास (डी)। 11, ए इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक अनस्टैम्पड प्रारंभिक डिक्री लागू करने योग्य नहीं है और इसलिए, सीमा की अवधि तब चलने लगती है जब डिक्री को स्टाम्प पेपर पर अंकित किया जाता है। मुद्रांक अधिनियम कुछ वर्गों के उपकरणों पर राज्य के लिए राजस्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक उपाय है। डाक टिकट अधिनियम वादी को उसके प्रतिद्वंद्वी के मामले से निपटने के लिए तकनीकी हथियार से लैस करने के लिए अधिनियमित नहीं किया गया है। चूंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जो विभाजन की प्रारंभिक डिक्री पर स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करने या किसी व्यक्ति को स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए कहने के लिए किसी भी समय को निर्धारित करता है, इसलिए यह प्रस्ताव कि सीमा की अवधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक कि स्टाम्प पेपर प्रस्तुत नहीं किया जाता है और उस पर डिक्री संलग्न नहीं की जाती है।

10 (2001) 7 एससीसी 573। 11 (2005) 10 एससीसी 746।

1203

इन आरई:आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 [संजीव खन्ना, जे.] 1204 के अंतर्गत आर्बिट्रेशन समझौतों के बीच हस्तक्षेप

20. हरिओम अग्रवाल बनाम प्रकाश चंद मालवीय 12 मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने करम चंद थापर (ऊपर), जुपुडी केशव राव का उल्लेख किया है।

(ऊपर), अवलोकन करने के लिए: “10. इस न्यायालय के निर्णयों और अधिनियम की धारा 33, 35 और 2 (14) के एक सादे पठन से यह स्पष्ट है कि एक उपकरण जिस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है, उसे जब्त किया जा सकता है और जब ऐसे उपकरण के लिए आवश्यक शुल्क और जुर्माना का भुगतान किया गया है तो इसे स्टाम्प अधिनियम की धारा

35 के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है। धारा 33 या 35 लिखत की किसी भी प्रति से संबंधित नहीं हैं और पक्ष को केवल उस दस्तावेज़ पर भरोसा करने की अनुज्ञात जा सकती है जो धारा 2 (14) के अर्थ के भीतर एक साधन है। स्टाम्प एक्ट के उद्देश्यों के लिए दस्तावेज़ की प्रति को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधि अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि दस्तावेज़ की प्रति को जब्त करके मान्य नहीं किया जा सकता है और इसे स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। "

21. श्यामल कुमार राय बनाम सुशील कुमार अग्रवाल 13 में, यह न्यायालय

यह पाया गया कि धारा 36 एक स्वतंत्र खंड है जो स्पष्ट रूप से विधि की न्यायालय को पर्याप्तता या अन्यथा किसी साधन पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क के संबंध में मामले को फिर से खोलने से रोकता है, यदि उसे साक्ष्य में स्वीकार किया गया है, तो एकमात्र अपवाद धारा 61 है जो संदर्भ और संशोधन के लिए प्रदान करती है। जावेर चंद (ऊपर) पर भरोसा रखा गया था।

22. अविनाश कुमार चौहान बनाम विजय कृष्ण मिश्रा 14

डाक टिकट अधिनियम की धारा 35 में उपयोग किए गए 'किसी भी उद्देश्य के लिए' शब्दों का अर्थ। इन शब्दों को प्राकृतिक अर्थ और प्रभाव दिया जाना चाहिए। इनमें संपार्श्विक उद्देश्य शामिल होगा, जैसा कि राम रतन बनाम परम नंद 15 में प्रिवी काउंसिल के निर्णय में माना गया था। पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 49 के संदर्भ में किसी दस्तावेज़ के पंजीकरण के गैर-प्रभावी अधिनियम के बीच अंतर किया गया था, जो संपार्श्विक उद्देश्य के लिए एक अपंजीकृत दस्तावेज़ के उपयोग पर रोक नहीं लगाता है। धारा 35 अलग-अलग गलत शब्दों में लिखी गई है, और जब लागू हो, तो संपार्श्विक उद्देश्य के लिए कृत्रिम रूप से मोहर वाले उपकरण के उपयोग पर रोक लगाती है।

12 (2007) 8 एससीसी 514। 13 (2006) 11 एससीसी 331। 14 (2009) 2 एससीसी 532। 15 ए. आई. आर. 1946 पी. सी. 51

/

[2023] 15 एस सी आर।

23. इस कानूनी स्थिति को लागू करना आवश्यक है, क्योंकि हम दिन के दौरान दूसरों के साथ अपनी बातचीत में कई बार अनुबंध या समझौते करते हैं। यहां तक कि चालान, रसीदें या मानक प्रारूप समझौतों के रूप में लिखित दस्तावेजों का अक्सर आदान-प्रदान किया जाता है, और बातचीत की शर्तें बनती हैं। एक बिना मुहर वाले या कम मुहर वाले अनुबंध या समझौते को जब्त नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब इसे ऐसा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति या डाक टिकट अधिनियम की धारा 33 के संदर्भ में एक सार्वजनिक

अधिकारी के समक्ष साक्ष्य में प्राप्त करने के लिए पेश किया जाता है। यह धारण करने के लिए कि विधि में असंवेदनशील मुद्रांकित उपकरण मौजूद नहीं है, अव्यवस्था और व्यवधान पैदा करेगा।

24. भविष्यवाणी और निश्चितता विधि के केंद्रीय सिद्धांत हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक और नियमित प्रकृति के मामलों में। व्यावसायिक या सामान्य दिन-प्रतिदिन के लेन-देन में अपने आचरण की अवहेलना करने के लिए पक्षों के लिए विधि पर भरोसा करने में सक्षम होने के लिए टकटकी के निर्णय के सिद्धांत का पालन करना आवश्यक है। अस्थायी विधि सार्वजनिक वैधता और विधि के शासन के जनादेश में विश्वास को कमजोर करते हैं। इस न्यायालय ने पहले कहा है कि अपने पहले के निर्णय की समीक्षा और संशोधन करने से पहले, न्यायालय को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि क्या सार्वजनिक भलाई के हित में या किसी अन्य अनिवार्य कारण से ऐसा करना आवश्यक है, और न्यायालय को देश में विधि की व्याख्या में निश्चितता और निरंतरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।¹⁶ कई मौकों पर, इस न्यायालय ने न्याय के प्रशासन की आधारशिला के रूप में न्यायिक निर्णयों में निश्चितता और निरंतरता पर जोर दिया है।¹⁷ न्यायिक निर्णयों में निरंतरता पक्षों को उनके दैनिक संबंधों का हिस्सा बनने वाले लेनदेन के परिणामों के बारे में आश्वस्त करने के लिए अनुकूल है।

25. एक उपकरण पर धारा 33 के अनुसार मुहर लगाई जानी चाहिए जब इसे निष्पादित किया जाता है या पहली बार निष्पादित किया जाता है। 'निष्पादित' और 'निष्पादन' अभिव्यक्तियों को स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 के खंड (12) में 'हस्ताक्षरित' या 'हस्ताक्षर' के अर्थ में परिभाषित किया गया है।¹⁹ इसमें अर्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का श्रेय देना शामिल है।

16 केशव मिल्स कं. लिमिटेड बनाम. आयकर आयुक्त, बॉम्बे उत्तर, अहमदाबाद, आकाशवाणी 1965 एससी 1636।

17 आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम ए. पी. जैसवाल और अन्य, (2001) 1 एस. सी. सी. 748.

18 टोटल एनवायरनमेंट बिल्डिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक उपायुक्त कर और अन्य, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 953; भारत संघ और एक अन्य बनाम रघुबीर सिंह (डी) एल. आर. आदि द्वारा, (1989) 2 एससीसी 754।

19 2. परिभाषाएँ।—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ अप्रिय न हो, -

(12) निष्पादित और निष्पादित।—“निष्पादित "और" निष्पादन ", संदर्भ 1205 के साथ उपयोग किया गया

इन आरई: आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 [संजीव खन्ना, जे.] 1206 के अंतर्गत आर्बिट्रेशन समझौतों के बीच हस्तक्षेप

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 11 20. अब मैं मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 की अवहेलना करते हुए एक मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में निष्पादन या 'हस्ताक्षर' की प्रासंगिकता का विश्लेषण करूंगा।

26. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 में कहा गया है:

“7. मध्यस्थता समझौता।—(1) इस भाग में, "मध्यस्थता समझौते" का अर्थ है पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता को उन सभी या कुछ विवादों को प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता जो उत्पन्न हुए हैं या जो एक अवज्ञाकारी कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वे संविदात्मक हों या नहीं।

(2) एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है।

(3) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा।

(4) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि यह (ए) पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ में निहित है;

(बी) पत्रों, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान-प्रदान जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से संचार शामिल है जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं; या

(ग) दावे और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान जिसमें समझौते के अस्तित्व का आरोप एक पक्ष द्वारा लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है।

(5) मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के लिए एक अनुबंध में संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि उस मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाया जाए। "

उपकरणों के लिए, जिसका अर्थ है "हस्ताक्षरित" और "हस्ताक्षर" और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 11 के अर्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का आरोपण शामिल है।

20 11. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का योगदान।—एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का श्रेय प्रवर्तक को दिया जाएगा -

(क) यदि यह स्वयं प्रवर्तक द्वारा भेजा गया था;

((ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में प्रवर्तक की ओर से कार्य करने का अधिकार था; या

(ग) स्वतः संचालित करने के लिए प्रवर्तक द्वारा या उसकी ओर से क्रमादेशित एक सूचना प्रणाली द्वारा।

/

[2023] 15 एस सी आर।

एक 'मध्यस्थता समझौता' पक्षों द्वारा उन सभी या कुछ विवादों को मध्यस्थता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता है जो उनके बीच उत्पन्न हुए हैं या उत्पन्न हो सकते हैं। विवाद कानूनी संबंध के संबंध में हो सकते हैं, चाहे वे संविदात्मक हों या नहीं। मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होना चाहिए।

27. धारा 7 की उप-धारा (4) निर्दिष्ट करती है जब मध्यस्थता समझौते को लिखित रूप में कहा जा सकता है। उप-धारा (4) के खंड (ए) में कहा गया है कि एक मध्यस्थता समझौता पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज हो सकता है। धारा 7 की उप-धारा (4) के खंड (बी) के अनुसार, एक मध्यस्थता समझौते को पत्रों, टेलेक्स, तार या संचार के अन्य रूपों के आदान-प्रदान से स्थापित या अनुमान लगाया जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संचार भी शामिल है। प्रावधान में 'निष्पादन' या पक्षों के हस्ताक्षर की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है। 21 इसी तरह, धारा 7 की उप-धारा (4) का खंड (सी) जो दावे और बचाव के बयानों के आदान-प्रदान को संदर्भित करता है, जिसमें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का आरोप एक पक्ष द्वारा लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है, एक ऐसे दस्तावेज को संदर्भित नहीं करता है जिस पर पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। खंड (ग) उस सिद्धांत को शामिल करता है जिसमें पक्षकार "सहमति" से मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के लिए सहमत होते हैं, या एक पक्ष द्वारा आरोप लगाए जाने पर और दूसरे द्वारा इनकार किए जाने पर इसके अस्तित्व से इनकार नहीं करके निहित रूप से सहमत होते हैं। एक मध्यस्थता समझौते को व्यापक शर्तों की अवहेलना की जाती है, और यह अंतर्निहित अनुबंध में एक खंड के रूप में या एक अंतर्निहित समझौते से अलग हो सकता है। विशेष रूप से, भले ही यह अंतर्निहित समझौते का एक खंड हो, इसे एक अलग समझौते के रूप में माना जाता है, एक पहलू जिसके लिए मैं विज्ञापन दूंगा।

28. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 22, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को सशक्त बनाती है

21 कारवेल शिपिंग सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम प्रीमियर सी फूड्स एक्विजम (पी) लिमिटेड (2019) 11 एस. सी. सी. 461; गोविंद रबर लिमिटेड बनाम. लुई ड्रेफस कमोडिटीज एशिया प्रा. लि. (2015) 13 एससीसी 477.

22 16. मध्यस्थता न्यायाधिकरण की अपनी अधिकारिता पर निर्णय लेने की क्षमता।— (1) मध्यस्थ

न्यायाधिकरण मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय सहित अपनी अधिकारिता पर निर्णय दे सकता है, और उस उद्देश्य के लिए, (ए) एक मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है, उसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र समझौते के रूप में माना जाएगा; और

(ख) मध्यस्थता न्यायाधिकरण का यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, न्यायिक रूप से मध्यस्थता खंड की अयोग्यता को लागू नहीं करेगा।

(2) एक याचिका कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, बचाव के बयान को प्रस्तुत करने के बाद नहीं उठाया जाएगा; हालांकि, एक पक्ष को 1207 में शामिल नहीं किया जाएगा।

इन आरई:आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 [संजीव खन्ना, जे.] 1208 के अंतर्गत आर्बिट्रेशन समझौतों के बीच हस्तक्षेप

अपने अधिकार क्षेत्र में शासन करना। इसमें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता को तय करने का अधिकार शामिल है। इसमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 का संदर्भ है, जिसकी मैंने जांच की है। धारा 16 के अनुसार, एक मध्यस्थता समझौता अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक समझौता है, भले ही यह अंतर्निहित अनुबंध में केवल एक खंड हो। इस धारा में विशेष रूप से कहा गया है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा अंतर्निहित अनुबंध को अमान्य ठहराने के निर्णय से न्यायालय द्वारा मध्यस्थता खंड की अयोग्यता नहीं होगी। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 की आवश्यकताओं के संदर्भ में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का पता लगाया जाना है। किसी दिए गए मामले में अंतर्निहित अनुबंध अमान्य हो सकता है, लेकिन मध्यस्थता खंड मौजूद हो सकता है और लागू करने योग्य हो सकता है। किसी अंतर्निहित समझौते की अवैधता, जब तक कि इसके गठन से संबंधित न हो, अंतर्निहित समझौते में मध्यस्थता खंड की अवैधता का परिणाम नहीं हो सकता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एक मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में पृथक्करण के सिद्धांत की नकारात्मक और सकारात्मक रूपरेखाओं को विस्तार से समझाया है, जिससे मैं सम्मानपूर्वक सहमत हूं।

29. इस संबंध में, मैं बी. एन. ए. बनाम बी. एन. बी. और अन्य 23 के मामले में सिंगापुर उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर ध्यान दे सकता हूं जिसमें कहा गया है कि मध्यस्थता समझौते में कोई दोष इसे शुरू से ही अमान्य नहीं करता है जब तक कि दोष इतना मौलिक या अपरिवर्तनीय न हो कि पक्षकारों के मध्यस्थता के इरादे या समझौते को नकार सके। यह सिद्धांत इन्सिग्मा टेक्नोलॉजी कंपनी के निर्णय में सिंगापुर के अपील न्यायालय की टिप्पणियों पर आधारित है।

लिमिटेड बनाम अल्सटॉम टेक्नोलॉजी लिमिटेड 24.

इस तरह की याचिका केवल इसलिए दायर करने से कि उसने मध्यस्थ की नियुक्ति की है या उसकी नियुक्ति में भाग लिया है।

(3) एक याचिका कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने अधिकार के दायरे को पार कर रहा है, जैसे ही मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान कथित रूप से अपने अधिकार के दायरे से बाहर का मामला उठाया जाता है, उठाया जाएगा।

(4) माध्यस्थ न्यायाधिकरण, उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट मामलों में से किसी एक में, बाद की याचिका को स्वीकार कर सकता है यदि वह विलंब को न्यायोचित मानता है।

(5) माध्यस्थ न्यायाधिकरण उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट याचिका पर निर्णय लेगा और जहां माध्यस्थ न्यायाधिकरण याचिका को अस्वीकार करने का निर्णय लेता है, वहां माध्यस्थ कार्यवाही जारी रखेगा और एक मध्यस्थ पुरस्कार देगा।

(6) इस तरह के मध्यस्थता पुरस्कार से व्यथित एक पक्ष धारा 34 के अनुसार इस तरह के मध्यस्थता पुरस्कार अपास्त करते हुए करने के लिए आवेदन कर सकता है।

/

[2023] 15 एस सी आर।

30. न्यायिक रूप से यह महत्वपूर्ण है कि किसी समझौते के नियमों और परिणामों में अंतर किया जाए जो शुरू से ही अमान्य हैं, और एक अमान्य समझौते, और एक समझौते पर अवैधता और विधि के उल्लंघन के प्रभाव को।

31. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872-25 के अनुसार, एक समझौता जो विधि द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, उसे अमान्य कहा जाता है, और विधि द्वारा लागू करने योग्य समझौता एक अनुबंध है।²⁶ एक अनुबंध जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाता है, वह अमान्य हो जाता है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाता है।-

32. अनुबंध अधिनियम 28 की धारा 10 की आवश्यकताएँ यह हैं कि अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्षों द्वारा, वैध विचार के लिए और वैध उद्देश्य के साथ अनुबंध किया जाना चाहिए। पार्टियों की सहमति निशुल्क होनी चाहिए। अनुबंध को स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। विरोधाभास से बचने और दोनों धाराओं को सामंजस्यपूर्ण रूप से लागू करने के लिए धारा 2 को धारा 10 के साथ पढ़ा जाना चाहिए न कि अलग-अलग।

33. धारा 11-29 और 12-30 अनुबंध के हकदार व्यक्तियों से संबंधित हैं। ऐसे उदाहरणों में जहां किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अक्षम घोषित किया जाता है या उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत किसी सक्षम व्यक्ति की अवज्ञा के दायरे में नहीं आता है, जैसे कि नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अनुबंध अमान्य होगा। एक समझौते को तब भी अमान्य कर दिया जाता है जब दोनों पक्ष तथ्य 31 की गलती अंतर्गत होते हैं। धारा 24 के अनुसार, समझौते अमान्य हैं यदि विचार और उद्देश्य आंशिक रूप से गैरकानूनी हैं।³² इस धारा का वर्तमान मुद्दे पर कोई अनुप्रयोग नहीं है, और न ही हम धारा 25 से संबंधित हैं, जो बिना विचार के समझौतों से संबंधित है।

25 संक्षेप में, "अनुबंध अधिनियम"।

26 2 (छ) विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होने वाले समझौते को अमान्य कहा जाता है; (ज) विधि द्वारा प्रवर्तनीय समझौता एक अनुबंध है।

27 2 (जे) एक अनुबंध जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाता है, वह अमान्य हो जाता है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाता है।

28 10. कौन से समझौते अनुबंध हैं?— सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्षों की निशुल्क सहमति से, एक वैध विचार के लिए और एक वैध उद्देश्य के साथ किए जाते हैं, और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित नहीं किए जाते हैं।

इसमें निहित कुछ भी भारत में लागू किसी भी विधि को लागू नहीं करेगा और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया जाएगा, जिसके द्वारा गवाहों की उपस्थिति में लिखित रूप में या दस्तावेजों के पंजीकरण से संबंधित किसी भी विधि की आवश्यकता होती है।

29 धारा 11, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872। 30 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 12। 31 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 20। 32 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 24।

1209

इन आरई:आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 [संजीव खन्ना, जे.] 1210 के अंतर्गत आर्बिट्रेशन समझौतों के बीच हस्तक्षेप

किस स्थिति में उन्हें शून्य माना जाना चाहिए। ऐसे समझौते जो विवाह के प्रतिबंध में या व्यापार के प्रतिबंध में हैं, अमान्य हैं।³⁴ दांव के माध्यम से समझौते भी अमान्य हैं।³⁵ जिन समझौतों का अर्थ निश्चित नहीं है, या जिन्हें सुनिश्चित किया जा सकता है, वे अमान्य हैं।³⁶ धारा 28 में कहा गया है कि कानूनी कार्यवाही के प्रतिबंध में समझौते अमान्य हैं, लेकिन अपवाद 1 में कहा गया है कि एक अनुबंध जिसके द्वारा पक्षकार उनके बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए सहमत होते हैं, अनुबंध को अवैध नहीं बनाएगा।³⁷

34. धारा 13 से 19 ए सहमति 38, निशुल्क सहमति 39, जबरदस्ती 40, अनुचित प्रवाह 41, धोखाधड़ी 42, गलत निरूपण 43, निशुल्क सहमति के बिना समझौतों की शून्य क्षमता 44 और अनुचित प्रवाह 45 द्वारा प्रेरित अनुबंध को अलग करने की शक्ति से संबंधित है। अनुबंध अधिनियम पूर्ववर्ती प्रावधानों द्वारा किए गए अनुबंधों को पीड़ित पक्ष के विकल्प पर अमान्य घोषित करता है।

35. धारा 21 अंतर्गत एक अनुबंध अमान्य नहीं है क्योंकि यह गलती से भारत में लागू विधि 46 के कारण होता है, और एक अनुबंध जहां एक पक्ष द्वारा तथ्य की गलती की जाती है, वह भी धारा 22 47 के अनुसार अमान्य नहीं है।

36. अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, किसी समझौते पर विचार या उद्देश्य तब तक वैध है जब तक कि यह विधि द्वारा निषिद्ध न हो या ऐसी प्रकृति का न हो जो विधि के प्रावधानों को विफल कर सके, या धोखाधड़ी हो। न तो ये प्रावधान बिना मोहर वाले या बिना वैज्ञानिक रूप से मुहर लगे उपकरणों के मामले में लागू होते हैं, न ही विचार या उद्देश्य गैरकानूनी है क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति या किसी अन्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है या इसका तात्पर्य है। धारा 23 का अंतिम खंड तब लागू होता है जब किसी समझौते के विचार या उद्देश्य को इस प्रकार माना जाता है -

33 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 25।

34 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 26 और 27। 35 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 30।

36 धारा 29, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872। 37 धारा 28, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872। 38 धारा 13, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872। 39 धारा 14, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872। 40 धारा 15, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872। 41 धारा 16, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872। 42 भारतीय अनुबंध अधिनियम,

1872 की धारा 17। 43 धारा 18, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872। 44 धारा 19, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872। 45 धारा 19 क, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872। 46 धारा 21, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872। 47 धारा 22, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872।

/

[2023] 15 एस सी आर।

अनैतिक या सार्वजनिक नीति के खिलाफ। एक उपकरण, चाहे उस पर बिना मोहर लगी हो या बिना ज्ञान के मुहर लगी हो, समझौते के अनैतिक होने के विचार या उद्देश्य के आधार पर गलत नहीं होगा, न ही यह सार्वजनिक नीति के विपरीत गलत होगा।

37. बी. ओ. आई. फाइनेंस लिमिटेड बनाम अभिरक्षक और अन्य 48 इस न्यायालय के बाद सार्वजनिक नीति के विषय पर मामला विधि की जांच करते हुए, यह पाया गया कि एक अवैध कार्य करने के लिए एक समझौते के अनुसार, एक लेनदेन, आंशिक रूप से, होता है जो अन्यथा मान्य होगा यदि ऐसा कोई पूर्व समझौता नहीं था, तो अनुबंध की अवैधता के बावजूद, पूर्ण लेनदेन को ही अमान्य नहीं माना जा सकता है।

38. इस निर्णय के बाद, केनरा बैंक और अन्य बनाम मानक मामले में

चार्टर्ड बैंक 49, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सार्वजनिक नीति के आधार पर अनुबंध को अमान्य घोषित करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि अनुबंध का उद्देश्य और विचार वह था जो अवैध था। जहां अनुबंध का उद्देश्य और विचार अवैध नहीं है जैसा कि प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद और मूल्य के भुगतान के मामले में है, तो अनुबंध सार्वजनिक नीति का विरोध करने के आधार पर अमान्य नहीं होगा। इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि विधि का उल्लंघन करते हुए अनुबंध का प्रदर्शन सार्वजनिक नीति के आधार पर अमान्य होगा। ये टिप्पणियां इस तर्क के संदर्भ में की गई थीं कि अनुबंध को पूरा करते समय विधि का उल्लंघन किया गया था और व्यवस्था सार्वजनिक नीति के खिलाफ थी।

39. स्विस टाइमिंग लिमिटेड बनाम श्री न्यायमूर्ति एस. एस. निज्जर का निर्णय ।

राष्ट्रमंडल खेल 2010 आयोजन समिति 50 ने विस्तार से काम किया है।

'शून्य' और 'शून्य' शब्दों के साथ और यह बताता है कि उनका उपयोग एक-दूसरे के साथ शिथिल और विनिमेय रूप से किया जाता है, हालांकि सख्ती से विधि में, वे ऐसे नहीं हैं। उन अनुबंधों के बीच अंतर करना भी महत्वपूर्ण है जो शून्य हैं, और जो ऑफ एर या स्वीकृति के तत्वों की कमी के कारण शुरू से ही शून्य हैं, जो एक अनुबंध को संचालन में आने से रोकते हैं। इस प्रकार, एक नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति द्वारा किया गया अनुबंध प्रभावी प्रभाव या स्वीकृति की कमी के कारण अमान्य हो जाएगा। लेकिन एक बार अनुबंध हो जाने के बाद, इसका मतलब यह है कि सभी पक्षों को, चाहे उनकी मन की आंतरिक स्थिति कुछ भी हो, क्या करना है।

1211

इन आरई:आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 [संजीव खन्ना, जे.] 1212 के अंतर्गत आर्बिट्रेशन समझौतों के बीच हस्तक्षेप

बाहरी उपस्थिति, विषय वस्तु की समान शर्तों में पर्याप्त निश्चितता के साथ सहमत, तब अनुबंध तब तक अच्छा है जब तक कि इसे किसी ऐसी शर्त की विफलता के लिए अलग नहीं किया जाता है जिस पर अनुबंध का अस्तित्व निर्भर करता है, या धोखाधड़ी के लिए, या किसी अन्य न्यायसंगत आधार पर। कोई भी पक्ष यह कहने के लिए अपनी गलती पर भरोसा नहीं कर सकता है कि यह शुरू से ही एक शून्य था, चाहे वह एक गलती थी जो उनके दिमाग अंतर्गत मौलिक थी, चाहे दूसरा पक्ष जानता था कि वह गलती के अधीन था।⁵¹

40. विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 52 में निर्णय , एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड का उल्लेख करने के बाद। एचएसबीसी पीआई

होलिंग्स (मॉरीशस) लिमिटेड 53, धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त अनुबंध और अनुबंध के बाद धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के बीच अंतर करता है। बाद वाला अनुबंध अधिनियम की धारा 17 के दायरे से बाहर है। यह देखता है कि धोखाधड़ी पूरे अनुबंध और सबसे बढ़कर मध्यस्थता के समझौते में व्याप्त हो सकती है, जिससे यह अमान्य हो जाता है। हालाँकि, ऐसा तब नहीं हो सकता है जब धोखाधड़ी के आरोप पक्षों के आंतरिक संबंधों को छूते हैं, जिसका सार्वजनिक क्षेत्र में कोई निहितार्थ नहीं होता है।

41. विद्या द्रोलिया (ऊपर) में निर्णय के दो पहलू भी हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले, मैं उस निर्णय में मेरे द्वारा की गई त्रुटि से सहमत हूँ और उसे स्वीकार करता हूँ जिसमें कहा गया है कि मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 3 के प्रवर्तन को देखते हुए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6 ए) का संचालन बंद हो गया है। जैसा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ठीक ही कहा है, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 3, जो धारा 11 के संशोधन से संबंधित है, को लागू नहीं किया गया है। दूसरा, जैसा कि निर्णय में उल्लेख किया गया है

माननीय मुख्य न्यायाधीश और कैरियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी बनाम ओम श्री ठाकुरजी एजुकेशनल सोसाइटी 54 में, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा

विद्या द्रोलिया (ऊपर) एक अनस्टैम्प्ड या अंडर-स्टैम्प्ड मध्यस्थता समझौते की वैधता नहीं थी। इस प्रश्न पर कोई विशेष राय व्यक्त नहीं की गई थी।

51 आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम देखें। जॉर्ज जोसेफ फर्नांडीस और एक अन्य (1989) 2 एस. सी. सी. 1, जो उद्धृत करते हैं

स्मिथ बनाम ह्यूजेस एल. आर. (1871) 6 क्यू. बी. 597 और सोल बनाम बुचर (1950) 1 के. बी. 671। आई. टी. सी. लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत था और इसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की व्याख्या के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए।

52 (2021) 2 एससीसी 1.

53 (2021) 4 एससीसी 713।

54 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 586।

/

[2023] 15 एस सी आर।

एक अनस्टैम्प मध्यस्थता समझौते की वैधता का संदर्भ, के रूप में

गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम में उल्लिखित। तटीय समुद्री निर्माण

& इंग.लिमिटेड 55, केवल एक मध्यस्थता समझौते के 'अस्तित्व' और 'वैधता' के बीच तुलना करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए था, न कि बिना मोहर वाले या कम मुहर वाले मध्यस्थता समझौतों के 'अस्तित्व' पर टिप्पणी या राय।

42. माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा विस्तार से बताए गए और इसमें दर्ज किए गए कारणों के लिए, मैं ऊपर बताए गए निष्कर्षों से सहमत हूँ। मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश के निर्णय के अन्य पहलुओं और अनुपात से भी सहमत हूँ।

--

उचित पीठ के समक्ष रखे जाने वाले मामले।

/

55 (2019) 9 एससीसी 209।